

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 1985

खण्ड-1 अंक 8

अधिकृत विवरण

विशय-सूची

मंगलवार, 19 मार्च, 1985

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(8)36

विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(8)46
वाक आउट	(8)53
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—  विलेज पालडी और राजपुर, पी0 एस0 फरुखनगर, जिला गुडगांव पर एक गैंग द्वारा अटैक किये जाने सम्बन्धी	(8)53
वक्तव्य—  मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(8)54
अध्यक्ष द्वारा घोशणा—  पंजाव युनिवर्सिटी सैनिट के लिए चुनाव स्थगित करने संबंधी	(8)56

## हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 19 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन

सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09:30 बजे हुई। अध्यक्ष

(सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

### Repairs of Roads

**\*852. Sh. Kitab Singh.** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether it is a fact that (i) Gohana Sisana Road (ii) Bhanswal Giwana Link Road and (iii) mahra Rewara Road, damaged due to floods are still lying unrepaired; if so, the time by which these roads are likely to be repaired; and

(b) whether any expenditure has been incurred on the roads referred to in part (a) above during the period from 1<sup>st</sup> June, 1983 to 1<sup>st</sup> December, 1984; if so, the details thereof?

### Public Works Minister (Sh. Amar Singh):

(a) Of the there roads, only two roads viz. Gohana Sisana Road and Mahara Reware Road were damaged during 1983 floods and both the roads stand repaired.

(b) An expenditure of Rs. 1,13,277/- and Rs. 10,000/- respectively was incurred on the roads referred to in part(a) above during the period from 1-6-1983 to 1-12-1984.

**श्री किताब सिंह:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी की नालेज में यह बात है कि भैंसवाला से गिवाना तक जो सड़क टूट गई थी, उसकी मुरम्मत हो चुकी है? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि सड़को पर जो गड्डे पड़ जाते हैं, वे कितने गहरे होने के बाद मेंटेनेंस के लिए माने जाते हैं।?

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, भैंसवाला से गिवाना तक की सड़क बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस सड़क पर 1.6.84 से लेकर 31.12.84 तक 28 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। इस समय यह सड़क बिल्कुल ठीक है।

**चौधरी धीर पाल सिंह:** स्पीकर साहब, इन्होंने सवाल के (बी) भाग के उत्तर में बताया है कि महरा—रिवाडासड़क पर 10 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस पैसे से कितने किलोमीटर सड़क पक्की की गई है और इस सड़क पर कौन सा वर्क किया गया है?

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, जैसे मैंने बताया है भैंसवाल—गिवाना सड़क फलड से क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, यह सड़क ठीक है। उसके पैच वर्क के लिए 28 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। आठवें फाईनैस कमी आन के अनुसार 24,000 रुपये पर

किलोमीटर सडक की मुरम्मत के लिए खर्च करना चाहिए जबकि हम 6,000 रुपये पर किलोमीटर सडको की मुरम्मत पर खर्च करके उन्हे हम ठीक रख रहे है। मैं अपने साथी विधायक को बताना चाहूंगा कि हमारे सूबे की सडकें दूसरे सूबो से बहुत अच्छी है।

**डा० भीम सिंह दहिया:** स्पीकर साहब, जो रोड गोहाना से सिसाना होते हुए दिल्ली जाती है, यह बहुत घटिया रोड है और दूसरे इस पर जींद तक की भी गाडियां चलती हैं जिस कारण इस रोड पर बहुत र । रहता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस रोड को गोहाना से दिल्ली तक स्टेट हाई-वे बनाने की कोई योजना है? क्योंकि अभी तक यह सडक एक लेन की ही सडक है और बहुत घटिया है।

**श्री अमर सिंह:** इस सडक पर 1.6.83 से 31.12.84 तक एक लाख सैंतीस हजार रुपये खर्च किए गए हैं। अब इस सडक को 10 फूट की चौडाई की बजाये 12 फूट चौडाई की बनाने की योजना है। अब तक इस पर 6 महीने के दौरान कुल मिलाकर 4 लाख 41 हजार रुपये के करीब खर्च हो चुके हैं। इस सडक पर 1 लाख 13 हजार 277 रुपये बाढ से जितनी सडक क्षतिग्रस्त हुई है, उस पर खर्च किया गया है। दूसरे इस सडक की मैन्टेनेंस पर 73 हजार रुपये खर्च कि गए है। इसके अलावा इस सडक की वाइंडिंग एण्ड स्ट्रैथनिंग पर 2 लाख 55 हजार रुपये खर्च किए गए है। इस प्रकार इस सडक पर कुल मिलाकर 4 लाख 41 हजार रुपये खर्च हो चुके है।

**श्री किताब सिंह:** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इन्हे बताना चाहूंगा कि यह सडक बिल्कुल ठीक नहीं हुई। क्या ये इस बात की इन्कवायरी करवाने के लिए तैयार है कि यह सडक ठीक है या नहीं?

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, यह सडक ठीक है। मैं आनरेबल मैम्बर से बताना चाहूंगा कि जो सडक ठीक की गई है उसकी लम्बाई 6.85 किलोमीटर है।

**श्री अध्यक्ष:** ये तो कह रहे हैं कि यह सडक बिल्कुल नहीं बनी। इनका कहना यह है कि क्या आप इस बात की इन्कवायरी करवाने के लिए तैयार है कि सडक बनी है या नहीं?

**श्री अमर सिंह:** सर, यह सडक बिल्कुल ठीक है। इसलिए इन्कवायरी करवाने का सवाल पैदा नहीं होता।

**चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि हरियाणा के अंदर डैमेज्ड रोडज़ कितने लम्बे हैं?

**श्री अध्यक्ष:** यह सवाल किसी पार्टिकुलर सडक के बारे में है। आम सडको के बारे में नहीं है। आप बैठ जाएं।

### **Rural Industries in Kilo Constituency**

**\*836. Sh. Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the villages-wise names of rural and other industries existing at present in Kilo Constituency; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up small scale or large scale industries in each village of Kiloj Constituency?

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया):

(क) वांछित सूचना सदन के पटल पर (अनुबन्ध 'ए') प्रस्तुत है।

(ख) नहीं

अनुबन्ध 'ए'

किलोई चुनाव क्षेत्र में ग्रामीण तथा अन्य उद्योगों की सूची

क.	इकाई का नाम	गांव	आईटमज्	रिमार्क
1	मै० हरियाणा ब्यूटी	बोहर	ब्रा	आर० आई० एस०
2	मै० केवल उद्योग संस्थान	आसन	गुड	''
3	मै० हरियाणा नाईलोन निवार	बोहर	नाईलोन निवार	''
4	मै० रामा वेपस	मकडोली	नोट बुक	''

	कर्नवटिंग इण्डस्ट्रीज़	कलां		
5	मै० अजीत एण्ड सन्स	घरोंठी	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
6	मै० राणा पेपर इंडस्ट्रीज़	अस्थल बोहर	नोट बुक	''
7	मै० सुबे राम इंडस्ट्रीज़	खिडवाली	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
8	मै० सत इंजिनियरिंग वर्कस	धामड़	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	एस० एस० आई०
9	मै० जगन साबुन उद्योग	सुखपुरा	सोप	आर० आई० एस०
10	मै० हरियाणा मेटल एण्ड स्टील उद्योग	गढी बोहर	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
11	मै० धामड आयल मिल	कन्साला	आयल	''
12	मै० न्यू भारत स्टील वर्कस	गढी बोहर	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
13	मै० जुगतीराम ई वर सिंह	कन्साला	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''



14	मै० इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रा	मकरौली	ब्रा	''
15	मै० प्रताप सिंह विजय पाल एग्रीकल्चर वर्कस	रुडकी	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
16	मै० भगवती एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	सुखपुरा	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	एस० एस० आई०
17	मै पंचाल ग्राम उद्योग	टिटोली	''	आर० आई० एस०
18	मै जसवन्त सिंह धर्म सिंह	बखेता	आयल	''
19	मै सुरिन्द्र स्टील इंडस्ट्रीज	धामड	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
20	मै० सुनीता इंजिनियरिंग वर्कस	धामड	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
21	मै० खेडा वूडन वर्कस	धामड	वूडन आईटम	''
22	मै जगदीश प्रसाद फलोर मिल	कलोई	आटा	''
23	मै० आर० एस०	कन्साला	एग्रीकल्चर	''

	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस		इम्पलीमेंटस	
24	मै० इन्द्र आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	सुखपुरा	आईस	एस० एस० आई०
25	मै ए० आर सर्जिकल इंडस्ट्रीज	बोहर	पट्टी	आर० आई० एस०
26	मै० आर्या इंडस्ट्रीज	भालोट	आयल	''
27	मै० एस नाथ इंडस्ट्रीज	मुंगांन	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
28	मै० वि वकर्मा इंडस्ट्रीज	बोहर	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
29	मै० भगत बाण उद्योग	खिडवाली	बाण	''
30	मै० जिले बाण फैक्ट्री	''	बाण	''
31	मै सोपी राम बाण	खिडवाली	बाण	आर० आई एस०
32	मै० चरण बाण	खिडवाली	बाण	''
33	मै० रुप भू	मकडोली	भू	''
34	मै० गजे भू कम्पनी	धामड	भू	''
35	मै० राजबीर बास्केट	धामड	बास्केट	''

36	मै० बलवान बास्केट	धामड	बास्केट	''
37	मै० दयानन्द टोकरी उद्योग	धामड	बास्केट	''
38	मै० रिछपाल बाण उद्योग	मकडोली	बाण	''
39	मै० उमेद कारपैन्टरी	कलोई	वुडल आईटम	''
40	मै० कृशणा इंडस्ट्रीज	जसिया	आयल	''
41	मै० रामा इंडस्ट्रीज	जसिया	गुड	''
42	मै० चांद राम भू इंडस्ट्रीज	खिडवाली	भू	''
43	मै० भगवान भू इंडस्ट्रीज	खिडवाली	भू	''
44	मै० भाले राम कारपैन्टरी वर्क्स	खिडवाली	वुडन आईटम	''
45	मै० रामधारी सुपुत्र नेकीराम	खिडवाली	''	''
46	मै० बलबीर भू फैक्ट्री	धामड	भू	''
48	मै० राम सिंह हैंडलूम	धामड	हैंडलूम	''

47	मै० परमा हैण्डलूम इंडस्ट्रीज	धामड	हैण्डलूम	''
49	मै० हवा सिंह जनरल इंडस्ट्रीज	धामड	फलोर मिल	''
50	मै० सुल्तान बीबर	कलोई	हैण्डलूम	''
51	मै० सुनीता इंजिनियरिंग वकर्स	आसन	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
52	मै० राज फर्नीचर्स	कन्साला	वुडन फर्नीचर्स	''
53	मै० पवन सोप फैक्ट्री	टिटोली	सोप	''
54	मै० सतपाल बाण वकर्स	कलोई	बाण	''
55	मै० रतन हैण्डलूम	धामड	हैण्डलूम	''
56	मै० हुकम हैण्डलूम	धामड	हैण्डलूम	''
57	मै० प्रवे । इंजिनियरिंग वकर्स	आसन	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
58	मै० छतर सिंह भू इंडस्ट्रीज	धामड	भू	''
59	मै० भले राम वास्केट	धामड	बास्केट	''

	इंडस्ट्रीज			
60	मै० हवा सिंह वास्केट	कलोई	बास्केट	''
61	मै० कन्हैया हैण्डलूम	धामड	हैण्डलूम	''
62	मै० ने नल एग्रो कास्टिंग इंडस्ट्रीज	गढी बोहर	कास्टिंग	''
63	मै० बलवन्त वास्केट वकर्स	धामड	बास्केट	''
64	मै० श्री िव फूड इंडस्ट्रीज	कलोई	राईस	''
65	मै० माया हैण्डलूम	कटवाडा	हैण्डलूम	''
66	मै० ई वर हैण्डलूम	कटवाडा	हैण्डलूम	''
67	मै० फेन्डस सर्जीकल	बोहर	पट्टी	''
68	मै० इन्द्र इंजिनियरिंग वकर्स	कलोई	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
69	मै० रुप हैण्डलूम	कटवाडा	हैण्डलूम	''
70	मै० वि वकर्मा वुड वकर्स	टिटोली	वुडन आईटम	''

71	मै0 राज स्टील इंडस्ट्रीज	बोहर	कारस्टिंग	''
72	मै0 धलवान थ्रेड वाल कारपोरे ान	बोहर	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
73	मै0 हरियाणा थ्रेड वाल कारपोरे ान	बोहर	थ्रेड वाल	''
74	मै0 चावला बिस्कुट फैक्ट्री	सुन्दरपुर	बिस्कुट	''
75	मै0 देवी उद्योग	लाडोथ	आयल	''
76	मै0 कृष्णा कारपेन्टर	सांघी	वुडन आईटम	''
77	मै0 राजपाल इनजीनियरिंग वर्कर्स	सांघी	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
78	मै0 ई वर भूज फैक्ट्री	सांघी	भूज	''
79	मै0 हरी राम भू उद्योग	बसंतपुर	भूज	''
80	मै0 माया राम जूती उद्योग	बसंतपुर	भूज	''
81	मै0 कमला का िदकारी वर्कर्स	हुमायूंपुर	का िदाकारी	''

82	मै० पूरन कारपेन्टरी	हुमायूंपुर	वुडन आईटम	''
83	मै० िव वुड वकर्स	कलोई	वुडन आईटम	''
84	मै० महिन्द्र कारपेन्टरी वकर्स	कलोई	वुडन आईटम	''
85	मै० अ ठोका इन्जीनियरिंग वकर्स	मुंगीन	एग्रीकल्चर इम्पलीमैन्टस	''
86	मै० रतन भू इंडस्ट्रीज	कलोई	भूज	''
87	मै० चन्द्र टायर पैन्चर	भालोट	पैन्चर	''
88	मै० परासर इंडस्ट्रीज	ब्राहमणवास	एग्रीकल्चर इम्पलीमैन्टस	''
89	मै० गुरु रविदास भू इंडस्ट्रीज	कलोई	भूज	''
90	मै० जनता हैण्डलूम इंडस्ट्रीज	कलोई	हैण्डलूम	''
91	मै० भीम फलोर एण्ड जनरल मिल	भालोट	आटा	''
92	मै० प्रका ा बाण फैक्ट्री	भालोट	बाण	''

93	मै० मिनाक्षी हैण्डीकाफट	बोहर	हैण्डीकाफट	''
94	मै० गयासम पोटर वर्क्स	भालोट	पोटरज	''
95	मै० रती राम पोटरज	भालोट	पोटरज	''
96	मै० रामफल अर्थन वेयर	भालोट	पोटरज	आर० आई० एस०
97	मै० सतबीर अर्थन वेयर	भालोट	पोटरज	''
98	मै० सत नारायण अर्थन वेयर	भालोट	पोटरज	''
99	मै० सुप्रीम सर्जिकल	बोहर	पट्टी	''
100	मै० भयाम इंडस्ट्रीज	कटवाडा	हैण्डलूम	''
101	मै० चन्द्र हैण्डलूम	कटवाडा	हैण्डलूम	''
102	मै० हनूमान बजरंग बली खादी उद्योग	सांघी	हैण्डलूम	''
103	मै० महमियां दाल मिल	सुन्दरपुर	दाल	''
104	मै० होरियार सिंह अर्थन वेयर	भालोट	पोटरज	''
105	मै० दिलबाग अर्थन वेयर	भालोट	पोटरज	''



106	मै० मुख्तयार अर्थन वेयर	भालोट	पोटरज	''
107	मै० परसा पोटरज	भालोट	पोटरज	''
108	मै० बिरसा पोटरज	चमारिया	पोटरज	''
109	मै० पूरन पोटरज	चमारिया	पोटरज	''
110	मै० ई वर अर्थन वेयर	चमारिया	पोटरज	''
111	मै० रिसाल देसी भूज	चमारिया	भू	''
112	मै० हुड्डा का पीदकारी	जसिया	का पीदकारी	''
113	मै० दया इंजिनियरिंग वर्क्स	मकडोली	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
114	मै० नफे सिंह इंजिनियरिंग वर्क्स	मकडोली	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
115	मै० नारायण बास्केट	मकडोली	बास्केट	''
116	मै० बिरखा बास्केट	मकडोली	बास्केट	''
117	मै० फूला वूडन वर्क्स	मकडोली	वूडन आईटम	''
118	मै० रोहिला गारमेंटस	कलोई	गारमेंटस	''
119	मै० निवास वूडवर्क्स	टिटोली	वूडन आईटम	आर० आई०

				एम0
120	मै0 रामफल फलोर मिल्ज	टिटोली	आटा	''
121	मै0 फोमपट रेडियोज	भालोट	रिपेयर	''
122	मै0 ओम साईकिल	कन्साला	रिपेयर	''
123	मै0 सुरे ा इंजीनियर वर्क्स	अस्थल बोहर	रिपेयर	''
124	मै0 राम का पीदकारी	कन्साला	का पीदकारी	''
125	मै0 रहेजा साईकिल वर्क्स	कन्साला	रिपेयर	''
126	मै0 गंगा एग्रीकल्चर वर्क्स	कन्साला	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंटस	''
127	मै0 रामा भू मेकर	कन्साला	जूते	''
128	मै0 बलदेवा पोटरज	कन्साला	पोटरज	''
129	मै0 भाोरा पोटरज	कन्साला	पोटरज	''
130	मै0 दरिया पोटरज	कन्साला	पोटरज	''
131	मै0 जगत पोटरत	कन्साला	पोटरज	''

132	मै० मेहर पोटरज	कन्साला	पोटरज	''
133	मै० सुरिन्द्रा पोटरज	कन्साला	पोटरज	''
134	मै० स्वास्तिक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	सुन्दरपूर	पोलोथीन बैगज	''
135	मै० सिक्का बैल्डिंग वक्स	सांघी	कृशि औजार	''
136	मै० सत ब्लैक रिमथी	कन्साला	कृशि औजार	''
137	मै० जय ब्लैक रिमथी	कन्साला	कृशि औजार	''
138	मै० कुन्दन कारपैन्टरी	कन्साला	लकडी आईटम	''
139	मै० रतिया कारपैन्टरी	कन्साला	लकडी आईटम	''
140	मै० कि गोर इंडस्ट्रीज	बोहरस्टील	फर्नीचर	''
141	मै० राम कि गन इंजीनियरिंग वक्स	किलाई	कृशि औजार	आर० आई० एस०
142	मै० श्री भगवान वैल्डिंग वक्स	ब्राहमण वास	कृशि औजार	''
143	मै० करतार सिंह आयरन वक्स	बसन्तपुर	कृशि औजार	''

144	मै० सत नारायण कारपैन्टर	बसन्तपुर	वूडन आईटम	''
145	मै० एक्स सर्विस मैन एन्टरप्राईजिज	अस्थल बोहर	स्टील फर्नीचर	''
146	मै० बलवान हैण्डलूम	कटवाडा	हैण्डलूम	''
147	मै० हवा सिंह इंडस्ट्रीज	टिटोली	कृशि औजार	''
148	मै० राम सिंह सा मिल	टिटोली	वूडन आईटम	''
149	मै० तारा चन्द्र भूज	खडवाली	भूज	''
150	मै० धर्म पाल बास्केट	थामड	बास्केट	''
151	मै० महिन्द्रा हैण्डलूम	बोहर	हैण्डलूम	''
152	मै० कपूर एमब्राइडरी	बोहर	एमब्राइडरी	''
153	मै० पवार इलैक्ट्रीकल	बोहर	रिपेयर	''
154	मै० बनवारा वैल्डिंग वर्क्स	सांघी	कृशि औजार	''
155	मै० हरियाणा ड्रिंक प्रा० लि०	अस्थल बोहर	साफ्ट ड्रिंक	एस० एस० आई०
156	मै० जगमन्दर	मकडोली	स्टील फ़ैवरकेटरज	आर० आई०

	फैबरीकेटर्स			एस0
157	मै0 राठी इलैक्ट्रिक वक्सर्स	सांघी	रिपेयर	"
158	मै0 वम्र इंडस्ट्रीज	सांघी	आटा	"
159	मै0 स्वास्तिक आयल मिल	बोहर	तेल	"
160	मै0वि वकर्मा वैलिडिंग वक्सर्स	किलाई	कृशि औजार	आर0 आई0 एम0
161	मै0 जनता एग्रो सर्विस केन्द्र	किलोई	कृशि औजार	"
162	मै0 अ तौका टायर वक्सर्स	भालोट	रिपेयर / पैन्चर	"
163	मै0 औम मूडा मेकिंग इंडस्ट्रीज	टिटोली	मूडा	"
164	मै0 रोहतक दाल एण्ड फलोर मिल	सुन्दरपूर	दाल	"
165	मै0 भान्ति फलोर मिल	बसन्तपूर	आटा	"
166	मै0 राज टेलर्ज	बोहर	रेडीमेड गारमैन्ट्स	"

167	मै० राम किान हैण्डलूम	किलोई	हैण्डलूम	''
168	मै० करन हैण्डलूम	किलोई	हैण्डलूम	''
169	मै० बागडी हैण्डलूम	किलोई	हैण्डलूम	''
170	मै० जय नारायण ब्लैकस्मिथी	सांघी	कृशि औजार	''
171	मै० राजे ा इंडस्टरी कारपोरे ान	अस्थल बोहर	स्टील फर्नीचर	ग्रा० उ० यो०
172	मै० ओम इंडसटरीज़	मकरौली	बार्बड वायर	''
173	मै० जसपाल स्टील उद्योग	अस्थल बोहर	स्टील फर्नीचर	''
174	मै० महमियां राईस एण्ड जनरल मिल	सुन्दरपूर	चावल	''
175	मै० हरियाणा कोप० डेरी डेवलैपमेंट फ़ैडरे ान प्लांट गोहाना रोड	गोहाना रोड रोहतक	दूध और घी	मध्यम स्केल इंडस्टरीज़
176	मै० हैफेड कैटल फीड	सुखपुरा	प ़ुचारा	''
177	मै० हरियाणा पोलीस्टील	गोहाना	एलाय स्टील	लघु उद्योग

	इंडस्ट्रीज	रोड		
178	मै० लक्खी बान फैक्टरी	सांघी	बान	ग्रा० उ० यो०
179	मै० आर० के० फलोर मिल	गोहाना रोड सुखपुरा	आटा	''
180	मै० डायमैण्ड वूलन मिल	सुखपुरा	वुलन आईटम	लघु उद्योग
181	मै० चावला सोप फैक्टरी	सुखपुरा	साबुन	लघु उद्योग
182	मै० एस० डी० एन्टरप्राईजिज	चमारिया	लीफ स्पेरिंग	ग्रा० उ०यो०
183	मै० जयकरण सुपुत्र नाकेराम	चिडी	जुती	''
184	मै० प्रेम चन्द्र सपुत्र कुन्दन लाल	चिडी	जुती	''
185	मै० भयोकरण सुपुत्र बखान	चिडी	जुती	''
186	मै० कमपन सुपुत्र बखान	चिडी	हुक्का	''
187	मै० जगत एग्रो	चिडी	कृशि औजार	''

	इंडस्ट्रीज			
188	मै० जगदी ा एग्री० इम्पलीमेंट वर्क्स	गरवठी	कृशि औजार	''
189	मै० सतनारायण वूडन वर्क्स	बसन्तपूरा	वुडन आईटम	''
190	मै० भारत हैण्डलूम	घडौठी	हैण्डलूम	''
191	मै० बालाजी कैमिकल सोप	जसिया	साबुन	''
192	मै० नन्दरुप भू वर्क्स	हुंमायुपूर	जूते	''
193	मै० सुनील इंजीनिरिंग वर्क्स	आसन	कृशि औजार	''
194	मै० सतनामी एम्ब्राइडरी	चिडी	एम्ब्रायडरी	''
195	मै० रन सिंह कारपेंटरी वर्क्स	कन्साला	वुडन आईटम	''
196	मै० किताब केन क रिर	चिडी	गुड	''
197	मै० श्री महे वरी गुड खांडसारी	चिडी	गुड	''



198	मै० बनी लैदर गुड्स	चिडी	जूते	''
199	मै० जय नारायण रैडीमेड गारमेंट्स	घरोठी	रैडिमेड गारमेंट्स	''
200	मै० जगदी । विलैज पोटर	टिटोली	पोटर	''
201	मै० विनय जनरल इंडस्टरीज	टिटोली	एग्री० इम्पलीमेंट्स	''
202	मै० इन्द्र एग्री काफ्ट	टिटोली	एग्री० इम्पलीमेंट्स	''
203	मै० रती राम वुडन वर्क्स	टिटोली	वुडन आईटम	''
204	मै० राधु फर्मज टूल्ज	टिटोली	हैंड टूल्ज	''
205	मै० बजे सिंह भूज	टिटोली	जूते	''
206	मै० मेहर एग्री टूल्ज	टिटोली	कृशि औजार	''
207	मै० भारत इंजीनियरिंग वर्क्स	टिटोली	कृशि औजार	''
208	मै० सतबीर हैण्डलूम	घरोठी	हैण्डलूम	''
209	मै० प्रका । इंजीनियरिंग वर्क्स	लाडोत	एग्री० इम्पलीमेंट्स	''

210	मै० महिन्द्र टेलर्ज	चिडी	रेडीमेड गारमैटस	''
211	मै० जाले एग्री टूल्ज	टिटोली	कृशि औजार	''
212	मै० दीप इंडस्ट्रीज	लाडोत	एग्री० इम्पलीमेंटस	''
213	मै० राम निवास वुड वर्क्स	सुंगान	वुडन आईटम	''
214	मै० हीरा वूलन गारमैटस	सुखपूरा	गारमैटस	एस एस आई
215	मै० हकीकत राय बी० ओ०	भालोट	ब्रिकस	''
216	मै० राज सिंह रतन सिंह	रुडकी	ब्रिकस	''
217	मै० यूनाईटिड गुड एण्ड खांडसारी उद्योग	टिटोली	गुड	आर आई एस
218	मै० अमीन रैडिमेड गारमैटस	चिडी	गारमैटस	''
219	मै० महावीर फ्लोर मिल	घरौठी	आटा	''
220	मै० राम मेहर केन कै र	टिटोली	गुड	''
221	मै० रामचन्द्र केन	टिटोली	गुड	''

	कै र			
222	मै० हवा सिंह कुन्दु केन कै र	टिटोली	गुड	''
223	मै० राज कुन्दु उद्योग	टिटोली	गुड	''
224	मै० राम धन बी० के० ओ०	टिटोली	ब्रिक्स	एस एस आई
225	मै० ईमान का पीदकारी	टिटोली	का पीदकारी	आर आई एस
226	मै० दया नंद केन कै र	टिटोली	गुड	''
227	मै० ओम प्रका ा केन कै र	चिडी	गुड	''
228	मै० महेन्द्रा केन कै र	चिडी	गुड	''
229	मै० वि वकर्मा फनीचर हाउस	घरौठी	स्टील फर्नीचर	''
230	मै० संत राम फ्लोर मिल	चिडी	आटा	''
231	मै० सैनी का पीदकारी	टिटोली	का पीदकारी	''
232	मै० मुरारी फ्लोर मिल	चिडी	आटा	''

233	मै० जंगरा कारपैंटरी	चिडी	वुडन आईटम	आर० आई० एस०
234	मै० जंगा वुडन फर्नीचर	चिडी	वुडन आईटम	''
235	मै० विजय का पीदकारी	चिडी	का पीदकारी	''
236	मै० औम इंडस्ट्रीज़	घरौठी	आटा	''
237	मै० औम ब्लैक स्मिथी	जीन्दरान	एग्री० इम्पलीमेंटस	''
238	मै० धर्मपाल केन कै र	नान्दल	गुड	''
239	मै० घासी राम केन कै र	चिडी	गुड	''
240	मै० महिन्द्रा केन कै र	नान्दल	गुड	''
241	मै० उजाला केन कै र	नान्दल	गुड	''
242	मै० थम्बू पोटरज	चिडी	पोटरज	''
243	मै० किदारा अर्थन पोटरज	चिडी	पोटरज	''
244	मै० रामधारी पोटरज	घरौठी	पोटरज	''
245	मै० निहालु कारपैंटरी	नान्दल	वुडन आईटम	''

246	मै० परस राम कारपेंटरी	घरोटी	वुडन आईटम	''
247	मै० राजेन्द्रा टूलज	नान्दल	एग्री० इम्पलीमेंटस	''
248	मै० भगत एग्री टूलज	नान्दल	एग्री० इम्पलीमेंटस	''
249	मै० धर्मा ब्लैक स्मिथी	चिडी	एग्री० इम्पलीमेंटस	''
250	मै० रजिन्द्रा मूढा इंडसटरीज	टिटोली	मूढा	''
251	मै० लक्ष्मी भूज	टिटोली	भू	''
252	मै० रामकली का पीदकारी	चिडी	का पीदकारी	''
253	मै० राज मूढा इंडस्टरीज	घरौठी	मूढा	''
254	मै० राजबाला का पीदकारी	टिटोली	का पीदकारी	''
255	मै० न्यू हरियाणा का पीदकारी	टिटोली	का पीदकारी	''
256	मै० एम० बी० प्लास्टिक	बोहर	प्लास्टिक बोतल	''
257	मै० प्रभु आटा चक्की	सांघी	आटा	''
258	मै० धारा बाण	सांघी	बाण	आर० आई०

				एस0
259	मै0 सरुप बाण इंडस्ट्री	सांघी	बाण	''
260	मै0 रिसाल भूज	सांघी	भूज	''
261	मै0 देहाती का पीदकारी	टिटोली	का पीदकारी	''
262	मै0 रुरल नीटिंग सैन्टर	टटोली	निटींग	''
263	मै0 हरियाणा का पीदकारी सैन्टर	सुन्दरपुर	का पीदकारी	''
264	मै0 भारत का पीदकारी	सुन्दरपुर	का पीदकारी	''
265	मै0 रंगा टैलर्ज	टटोली	गारमेंटस	''
266	मै0 भयाम रिपेयर वर्क्स भापे	सुन्दरपुर	रिपेयर	''
267	मै0 देवी राम भूज	घरौटी	भूज	''
268	मै0 जुगती लैदर गुडस	चिडी	भूज	''
269	मै0 गोकल भूज	चिडी	भूज	''
270	मै0 रामदिया भूज	चिडी	भूज	''
271	मै0 प्रेम सा मिल	चिडी	वूडन आईटम	''

272	मै० हरि सिंह बलैक स्मिथी	चिडी	एग्री० इम्पलीमेंटस	"
273	मै० बलदेवा भूज	चिडी	भूज	"
274	मै० देवी वूडन वक्स	चिडी	वूडन आईटम	"
275	मै० बलवान हैण्डटूल्ज	चिडी	हैण्ड टूल्ज	"
276	मै० रतन भूज	चिडी	भूज	"
277	मै० धर्म सिंह भूज	चिडी	भूज	"
278	मै० एस० कुमार० टेलर्ज	भालोट	गारमेंटस	"
279	मै० राम सिंह भूज	चिडी	भूज	"
280	मै० गोवर्धन भूज	चिडी	भूज	"
281	मै० वजीर भूज	चिडी	भूज	"
282	मै० मंगत भूज	चिडी	भूज	"
283	मै० जेले लैदर गुडज	चिडी	भूज	"
284	मै० रामा का पीदकारी	कन्साला	का पीदकारी	"
285	मै० भुजा साईकल रिपेयर वक्स	कन्साला	रिपेयर	"

286	मै० रामा भूज	कन्साला	भूज	''
287	मै० धर्मा पोटरज	चिडी	पोटर	''
288	मै० धर्म पाल का गीदकारी	चिडी	का गीदकारी	''
289	मै० चन्द्र ब्लैक स्मिथी	चिडी	एग्री० इम्पलीमेंटस	''
290	मै० रघु भूज	चिडी	भूज	''
291	मै० रथवीर कारपेंटर	चिडी	वूडन आईटम	''
292	मै० दीप भूज	चिडी	भूज	''
293	मै० हवा सिंह भूज	घरोठी	भूज	''
294	मै० फतेह भूज	घरोठी	भूज	''
295	मै० प्यारे का गीदकारी	चिडी	का गीदकारी	''

**श्री हरि चन्द हुडडा:** स्पीकर साहब, इन्होने हाउस की टेबल पर करीब 300 इंडस्ट्रीज की लिस्ट रखी है। मैंने गावों में जा कर देखा है वहां कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है। (विघ्न)

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, जो लिस्ट 295 इंडस्ट्रीज की दी गई है, ये सब की सब चालू है। इनका



सवाल भी यही था कि किलोई कांस्टीच्युऐंसी में कितनी इंडस्ट्रीज़ है। उस के उत्तर में मैंने 295 की लिस्ट सदन की टेबल पर रखी है।

**श्री विरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, इन्होंने हाउस की टेबल पर 295 इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट रखी है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनमें से कितनी इंडस्ट्रीज़ चालू है और कितनी बंद पड़ी है और वे कब से बंद पड़ी है?

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ चालू है। इसके अलावा, मैं इन्हे यह भी बताना चाहूंगी कि इंडस्ट्रीज़ विभाग सर्वे कर रहा है कि कुल इंडस्ट्रीज़ में से कितनी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं और कितनी बंद पड़ी है। वैसे तकरीबन 7 प्रति 10 के आसपास इंडस्ट्रीज़ आज के दिन बंद है। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। यदि इन इंडस्ट्रीज़ में से 7 प्रति 10 बंद हो तो कोई विशेष बात नहीं।

**श्री विरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, इनमें से एक भी इंडस्ट्री चालू नहीं है और बहन जी कह रही है कि सारी की सारी चालू है। हम हर बार कहते हैं कि सवाल का जवाब गलत आ रहा है। यह फ़ैक्ट है कि आज के दिन कोई सिंगल इंडस्ट्री भी नहीं चल रही। जब हम कहते हैं कि जवाब ठीक नहीं है तो हमसे कहा जाता है कि सबूत दो। स्पीकर साहब, बे 10 के हाउस की एक

कमेटी बैठा दी जाए। वह कमेटी इस बात की जांच कर लेगी कि आया ये इंडस्ट्रीज चालू है या नहीं। स्पीकर साहब, हमारा सवाल पर ऐलीगे उन है कि आज के दिन इन 295 इंडस्ट्रीज में से एक भी चालू नहीं है।

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्यों की बड़ी कद्र करता हूँ। इनका यह कहना कि इन 295 इंडस्ट्रीज में से एक भी चालू नहीं है, कितनी गलत और बे-बुनियाद बात है। यह तो हो सकता है कि इन इंडस्ट्रीज में से 15-20 इंडस्ट्री नहीं चलती हों। जैसा की बताया गया है कि आज के दिन औसतन 7 प्रति शत इंडस्ट्री बंद हैं। यह बात भी सही हो सकती है कि जो 15-20 इंडस्ट्रीज बंद हो, वह भी इस 7 प्रति शत में आती हो। स्पीकर साहब, बकायदा चालू इंडस्ट्रीज की लिस्ट दी गई है। यदि ये चाहे तो हम इनके नाम इनको पढ़कर सुना देते हैं। (विघ्न) आप गांवों में तो कभी जाते नहीं। (विघ्न) आप गांवों में जा कर देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये इंडस्ट्रीज चलती भी है या नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि पिछले पांच सालों में 19 हजार के करीब देहातो में इंडस्ट्रीज लगी है और 51 हजार लोगों को देहातो में रोजगार मिला है। सदन में ये जो कुछ कह रहे हैं, यह बिल्कुल बेसलैस है। जो बात हर रिकार्ड के बेसिज पर कहते हैं, उसको कहते हैं कि यह ठीक नहीं है और जो ये बात कहते हैं, उसको ठीक कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? आप मुझे यह बतायें कि

साहब, फलां गावं में बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है। हम इसकी इन्कवायरी कर लेंगे और आपको बता देंगे कि क्यों नहीं है (व्यवधान)

**श्री हरि चन्द हुडडा:** स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि देहातो में इंडस्ट्री लगी हुई है और हम कहते हैं कि नहीं लगी है। यह कहना कि मैं गावों में नहीं जाता, गलत बात है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तीसरा इलैक्शन गावों से लडा है और अब चौथा भी लडूंगा। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैंने खुद गांव में नायलून की इंडस्ट्री लगवाई है और यह नायलून की इंडस्ट्री फेल पडी है। मैंने खुद चैकिंग की है, किसी गांव में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है और जो लगी थी, वह उठ गई है या बन्द पडी है।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जी ने खुद माना है कि 7 प्रसैंट बन्द पडी है। इसका मतलब है कि 295 में से 21 इंडस्ट्री बन्द हो सकती है। अगर इससे ज्यादा बन्द है तो आप बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, 295 में से पौने तीन सौ इंडस्ट्रीज़ चल रही है। अध्यक्ष महोदय, इनकी तसल्ली के लिए एक बात कहूंगा कि अगले भानिवार और इतवार को सैशन नहीं है, छुट्टी है। भानिवार के दिन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ आफिसर इनके साथ जिला रोहतक चला जाएगा। जिन जिन गावों में ये

जाना चाहते हैं, उनके साथ जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वाकई गावों में इंडस्ट्रीज़ हैं या नहीं। फिर सोमवार को आकर हमें बता दें कि क्या पोजीशन है।

**श्री हरि चन्द हुड्डा:** ठीक है जी।

**श्री फतेह चन्द विज:** स्पीकर साहब, रुरल इंडस्ट्रीज़ स्कीम के तहत सारी स्टेट को मदद देते हैं लेकिन सरकार ने जितनी मदद दी है, उससे जो इंडस्ट्रीज़ खुली थी, वे सब देहातों में बंद पड़ी हैं। ये कहते हैं कि चल रही है, इसलिए क्या हाउस की एक कमेटी बना कर सारी स्टेट का सर्वे करवायेंगे कि कितनी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं और कितनी बंद पड़ी हैं।

**श्री अध्यक्ष:** इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया है।

**श्री फतेह चन्द विज:** स्पीकर साहब, जो जवाब इन्होंने तैयार करके भेजा है इस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीज़ के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये मार्किट में बड़ी इंडस्ट्रीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका जो माल बनता है वह आगे बिकता नहीं है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ बन्द पड़ी हैं। यह कहना कि 295 इंडस्ट्रीज़ में से 275 इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, गलत बात है। टोटल इंडस्ट्रीज़ बन्द पड़ी हैं।

**श्री अध्यक्ष:** मैं आपको आफर देता हूँ कि आप भी हुड्डा साहब के साथ चले जाएं और देख आएँ।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया कि 7 प्रसैंट इंडस्ट्रीज़ बंद पडी है। क्या अपने कभी यह सर्वे किया है कि इनके बन्द होने के मुख्य कारण क्या हैं?

**श्री विरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, मेरा सुझाव है कि हुड्डा साहब रोहतक इंडस्ट्रीज़ देखने के लिए जाएंगे इसलिए, इस सवाल को डैफर कर दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** इसको डैफर करने का कोई सवाल नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो बाद में सोच लेंगे।

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, आर्य साहब ने सवाल पूछा था कि क्या कोई सर्वे करवाया है या नहीं। मैं इन्हे कहना चाहूंगी कि 7 प्रसैंट इंडस्ट्रीज़ बन्द पडी है। 7 प्रसैंट की जो फिगर दी है, यह सर्वे करने के बाद ही दी है। जहां तक इन 7 प्रसैंट के बंद होने का सवाल है, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो पार्टनरशिप में लडाई हो सकती है, और पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति काम न करना चाहता हो। दूसरे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिती ऐसी हो सकती है जो काम न चला पाता हो, ऐसे ही कई कारण हो सकते हैं। हां यह बात जरूर है कि हम किसी का लोन माफ नहीं करते।

**श्री ए० सी० चौधरी:** स्पीकर साहब, जितनी भी रुरल इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, मेनली उन में से बन्द पडी है। इसकी दो वजह है। सबसे बडी वजह यह है कि इनको बिजली नहीं मिलती

और उस इंडस्ट्रीज के जो मुलाजिम है, वे बिजली न होने के कारण बिना काम के बैठे रहते हैं छोटी इंडस्ट्रीज वाले जिन के पास पैसा कम होता है वे इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि प्रोडक्शन हो न और तन्खाह देते रहें। क्योंकि मंत्री महोदया रुरल इंडस्ट्रीज को एन्करेजमेंट देने के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा मेहरबानी करवाएंगी?

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, यह सम्भव हो सकता है कि किसी ने बिजली न मिलने के कारण अपना यूनिट बन्द कर दिया हो, लेकिन हमने रुरल इंडस्ट्रीज को बिजली का कनेक्शन देने में टॉप प्रायोरिटी दे रखी है और उसकी ड्यूटी में भी छूट दे रखी है।

**श्री ए० सी० चौधरी:** स्पीकर साहब, मेरी अपनी इंडस्ट्री है, मुझे लगाए हुए चार साल हो गये हैं। एक रुरल एरिया में लगी हुई है। लगी हुई मीनरी के मुताबिक उस में प्रोडक्शन 50 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन 50 हजार की भी प्रोडक्शन नहीं हुई। इसका कारण है कि जो रुरल फीडर है, उसको सिर्फ 5 घंटे आल्टरनेटिव दिन में बिजली सप्लाई होती है। कोई भी इंडस्ट्रीलिस्ट, जिसने दो चार लाख रुपया इंडस्ट्री पर लगा रखा हो, उसे कमाई न हो और उस पर उल्टा खर्चा पड रहा हो तो वह इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता, परिणामस्वरूप उसको इंडस्ट्री बन्द करनी पडती है।

**श्री अध्यक्ष:** इसका जवाब तो सुरलेवाला जी देंगे।

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला):** अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है कि श्री ए० सी० चौधरी साहब की इंडस्ट्री का कनैक्टान नान-पेमेंट आफ बिल की वजह से कटा हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि कारखाने में पैदावार नहीं होती। जब कनैक्टान कटा हुआ हो तो पैदावार कहां से होगी?

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, चौधरी साहब एम० एल० ए० हैं। भायद इनकी इंडस्ट्री में प्रोडक्टान इसलिए भी नहीं हो पाई होगी क्योंकि ये अपनी फैक्ट्री को पूरा समय न दे पायें हो।

**श्री ए० सी० चौधरी:** स्पीकर साहब, जिस यूनिट के बारे में मैंने इन से बात की थी वह यूनिट दूसरा है, उसकी बिजली काट दी गई थी। (विघ्न) स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीज के मेरे दो और यूनिट्स हैं, एक रुरल एरिया में है और दूसरा अर्बन एरिया में है। इसका मतलब यह नहीं है कि मंत्री जी इवेसिव-वे में जवाब दें और हाउस को मिसगाईड करें। मैंने तो एक फैक्ट्री का एक बिल छोड़ कर भोश बिजली के बिल की पेमेंट कर दी है लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या सभी डिफाल्टर्ज के साथ इसी तरह सख्ती से पे आते हैं? स्पीकर साहब, हमारे नोटिस में तो यह बात है कि बिजली महकमे के कर्मचारी पैसे लेकर बिजली

सप्लाई करते हैं। स्पीकर साहब, मेरे जैसे ला-अबाइंडिंग आदमी का तो बिजली का कनेक्शन कट जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े डिफाल्टर हैं उनका कनेक्शन नहीं काटते। स्पीकर साहब, मैंने इनसे कान्फिडेंस गैली एक पर्सनल बात की थी। इन्हें इस हाउस में नहीं करना चाहिए था। स्पीकर साहब, जिस इंडस्ट्री का ये जिक्र कर रहे हैं, उस में लेबर प्रोब्लम थी। वहां 7 महीने से स्टाफ इंडस्ट्री के अन्दर नहीं जा सका। मैं भी उनसे मिल न सका। इसलिए बिजली के बिल की पमेंट नहीं हो सकी थी। मैं यह बात उनकी नालेज में लाया था। अगर मैं कोई पर्सनल कान्फिडेंस गैली बात इनसे करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये उसका मजाक इस तरह उड़ाएं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके इन्होंने मेरा अपमान किया है।

**चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, मैंने कोई मजाक नहीं किया है और न ही अपमान किया है। चूंकि इन्होंने खुद प्रोडक्शन के बारे में जिक्र किया था, इसलिए मैंने इसका जवाब देना जरूरी समझा। इन्होंने कहा था कि बिजली न होने की वजह से मेरी फ़ैक्टरी में नुकसान है। अगर ये पर्सनल बात न करते तो मैं इस बात का जिक्र न करता। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कर्मचारी पैसे लेकर बिजली सप्लाई करते हैं, इस बात की इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की है। ये इस बात की शिकायत कर सकते थे। अगर ये शिकायत करते और मैं एक्शन न लेता तो फिर ये इस तरह की बात कर सकते थे।



**श्रीमी चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, इन्होंने डाबरी वाले का कनेक्शन क्यों नहीं काटा?

**श्री अध्यक्ष:** यह बिजली के कनेक्शन का सवाल नहीं है, आप बैठ जाइए।

**डा० औम प्रकाश भार्मा:** स्पीकर साहब, जगाधरी टाऊन भारतवर्ष में स्टील के बर्तन बनाने में बड़ी भारी भाँहरत रखता है। वहाँ पर बर्तन बनाने वाले 80 परसेंट यूनिट बंद पड़े हैं। क्या यह बात उनके नोटिस में है, अगर है तो क्या इनको बिजली देने की कृपा करेंगे?

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** स्पीकर साहब, यह क्वैचन केवल किलोई कांस्ट्रिक्ट्यूएरी का था। आप का सैपरेट क्वैचन है। फिर भी मैं आज ही स्थिती की जांच करवा दूँगी कि किस वजह से ये फैक्ट्री बन्द पड़ी है।

**श्री भले राम:** स्पीकर साहब, कुछ युनिट्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि मार्किट में कंपिटिशन तगडा होने के कारण उनका सामान नहीं बिकता। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी नीति है जिसके तहत इन युनिट्स द्वारा बनाए हुए माल को सरकार ले ले?

**श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया:** जी हाँ। 28 आर्टमस ऐसी है सरकार ने निधारित कर रखी है जिन्हे निगम या विभागों को अनिवार्यतः इन औद्योगिक इकाइयों से खरीदना पडता है।

**श्री मंगल सेन:** स्पीकर साहब, मुझ से पहले दो आदरणीय सदस्यों ने प्र न पूछे और बहन जी ने कहा कि 295 यूनिटस लगे हुए है तथा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे हुडडा साहब के साथ डिसिट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ आफिसर को भेज देंगे और आपने विज साहब का नाम भी साथ जोड़ दिया, यह कह कर कि वे पानीपत के इलाके में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा इनसे कुछ क्लैरिफिके ान लेना चाहूंगा। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि 295 इंडस्ट्रीज़ किलाई इलाके में लगी हुई है लेकिन खुद ही इन्होंने यह भी कह दिया कि 7 प्रसेंट इंडस्ट्रीज़ सारे हरियाणा में बन्द है। यह बात ये जरा स्पष्ट करें। फिर इन्होंने 28 आईटमज की बात कही है। इन्होंने कहा कि विभागो और निगमो को इन आईटमज को लेना लाजमी किया गया है। मैं आपके द्वारा इनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या इनकी इंस्ट्रक ान की पालना हो रही है या नहीं? अगर नहीं तो क्या ये डिफाल्टर्ज के विरुद्ध ऐक ान लेंगे? क्या इनकी नालेज में यह बात भी है कि रुरल इंडस्ट्रीज़ वालो ने क रिप्रैजैन्टे ान दिया है कि साहब, क्या करें, हम जो माल तैयार करते हैं, वह बिकता नहीं तथा उसे बेचने का उचि प्रबन्ध किया जाए? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी इन बातों का विस्तार से जवाब दें।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गहराई में नहीं जाते। ये गहराई में गए बगैर ही ऐसी बात कह देते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 सालो में 19 हजार के करीब

औद्योगिक इकाईयां देहातो में लगी है और 18 करोड रुपया बकायदा लोन के रुप में उन लोगों को दिलाया गया है। 11 करोड के करीब का माल रुरल इंडस्ट्रीज़ का स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ कार्पोरे ान के माध्यम से सरकार ने बिकवाया है। इनको, अध्यक्ष महोदय, यह भी पता होना चाहिए कि देहात के अन्दर छोटे उद्योग वाले जो माल बनाते है, वह यदि बिकता नही है तो उस लेकर रख लिया जाता है और उसकी कीमत का 80 परसेंट एडवांस उन्हे दे देते है। बाकी का 20 परसेंट पैसा माल बिकने पर दिया जाता है। हुडडा साहब के इलाके में 3 करोड 60 लाख रुपये का लोन दिलाया गया है। तकरीबन 4 करोड रुपये का माल वहां बना है जो बिक गया है।

#### **Non-availability of Nationalized Text Books**

**\*954. Ch. Kundan Lal:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Nationalized Text Books were not available to the students last year at the time of admission; if so, the reasons thereof; and

(b) the steps, if any, taken by the Government to supply such text books to the students as referred to in part (a) above at the time of admission during 1985?

**Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):**

(a) No. All school text books except two for primary classes were available at the time of admission last year.

(b) Yes, several administrative steps have been taken to ensure timely supply of nationalized text books in sufficient number at the time of admission during 1985-86.

**चौधरी कुन्दन लाल:** स्पीकर साहब, पिछले साल बहुत लेट किताबें छप कर आई थी और वे सब ब्लैक मार्किट में बिकी जिन को हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज़ के बच्चे खरीद नहीं सके। इस वजह से रिजल्ट भी पिछले साल काफी खराब रहा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में जिन अधिकारियों ने गलती की है उनके खिलाफ इन्क्वायरी करके क्या उन्हें सजा दी जाएगी और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए कोई प्रबन्ध किया जाए?

**श्री जगदी 1 नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, तीसरी और चौथी कक्षा की अध्यन्न प्रवेशिका ये दो किताबें समय पर नहीं छप सकी थी। जहां तक रिजल्ट की बात है, क्लास 3 तक तो नो डिटेन्शन पालिसी लागू है। इसलिए तीसरी क्लास तक तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी क्लास के रिजल्ट पर जरूर इसका असर पड़ेगा। लेकिन स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि जिसके यहां से ये किताबें छपवाई गई थी उसने इनको लेट छापा था। इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने खुद माना कि तीसरी ओर चौथी की पुस्तके समय से नहीं आई और इसकी वजह से चौथी क्लास के रिजल्टपर असर पडा। क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताएंगे कि जो बच्चे सरकार की गलती से फेल हुए है, क्या उन्हें पास करने में कोई रियायत दी जाएगी?

**Mr. Speaker:** This is no question.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, सरकार की गलती से वे फेल हुए है। जब किताबें ही नहीं होगी तो वे क्या पढ़ेंगे?

**Mr. Speaker:** Please sit down.

डा० भीमसिंह दहिया: स्पीकर साहब, इनसे सवाल यह पूछा गया था कि भविश्य में इस बात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि बच्चों को किताबें वक्त पर मिल जाए। जवाब यह आया है कि कई कदम उठाए है। आप खुद ही सोंचे, क्या यह जवाब ठीक है? इन्होंने कौन से कदम उठाए है क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हाउस को यह बताना चाहता हूं कि इस बार किसी किताब की मार्किट में कमी नहीं रहेगी। सभी किताबें वक्त पर मार्किट में आ जाएंगी। इसके लिए हमने जो कदम उठाए है वे इस प्रकार है—

(1) Printing orders were given in advance this year.

(2) Number of copies of each book in printing order were enhanced as compared to those of last year inter-alia to avoid hoarding and black-marketing.

(3) A high powered committee headed by Chief Minister has been constituted to review and streamline the working regarding the supply of paper and power.

(4) A monitoring committee headed by State Education Minister has been formed to review the working regarding preparation of manuscript and printing system.

**चौधरी कुलबी सिंह मलिक:** क्या मंत्री जी बताएंगे कि पिछले साल जिन किताबों की डैफिंसी रही थी वह कितनी देर रही? क्या वह सारे साल रही या केवल एक दो महीने ही रही? दूसरी बात अध्यक्ष महोदय यह है कि दुकानदार बड़ी ब्लैक मार्किटिंग करते हैं। वे किताब को जिल्द लगा लेते हैं और सजिल्द किताब दो रुपये महंगी देते हैं। क्या वे ऐसा कर सकते हैं?

**Mr. Speaker:** It is a good question.

**श्री जगदी नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, पिछले साल सारी किताबें बदली गई थीं। कुल 13 टाइटल थे। जैसा मैंने पहले अर्ज किया केवल दो किताबें, एक तीसरी की और एक चौथी की लैट आई। तीसरी की किताब 8-1-85 को आई और चौथी की किताब 29-1-85 को आई। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि दुकानदार सजिल्द किताब धक्के से देते हैं, यह रिपोर्ट हमें

आई थी। इस बार हम यह इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि जो व्यक्ति सजिल्द किताब लेना चाहे उसे वैसे किताब मिल जाए और जो बिना जिल्द लेना चाहे उस बिना जिल्द के किताब मिल जाए।

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कहा कि पिछले साल चूंकि इन्होंने सिलेबस बदल दिया था, किताबें बदल दी थी, इसलिए किताबें छपने में देरी हो गई मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि सिलेबस कब कब बदलते हैं, क्यों बदलते हैं और उसके बदलने का मापदंड क्या है?

**श्री अध्यक्ष महोदय:** डाक्टर साहब, आप इस बात से सहमत होंगे कि यह सिलेबस बदलने का क्वैशन नहीं है।

**10:00 बजे**

**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, इन्होंने जो कारण दिये हैं उसी से मेरी सप्लीमेंटरी अराइज हुई है कि पब्लिकेशन इन इस वजह से पूरी नहीं हो पाई। सिलेबस बदला गया था या कोई और कारण है। इसलिए मुझे उसके रूट कॉज़ में तो जाना ही पड़ेगा। हरियाणा की 1 करोड़ तीस लाख जनता है और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को यह सरकार कैसे लूट रही है, इसलिए मेरा सवाल यह है कि सिलेबस चेंज करने का क्या काइटेरिया है? दूसरे जो आपने कदम उठाये हैं कि अब ज्यादा पुस्तकें और एडवांस में प्रिंटिंग के आर्डर दे दिये, एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी जिसके खुद ही प्रधान बन बैठे और एक माइनोरिटी कमेटी बना दी।

इसलिए मैं वजीर साहब से बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ कि सिलेबस को बदलने का क्या कार्टिरिया है, पिछले साल कितनी बुक्स प्रिंट करवाने के आर्डर दिये थे और कितनी हुई? दूसरे आपने यह भी कहा कि बुक्स की कमी हुई थी। इस बात कि किस पर रिस्पोंसिबिलिटी डाली और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

**श्री जगदी । नेहरा:** जहां तक सिलेबस की बात है किस कार्टिरिया के हिसाब से बदला है, उसके बारे में तो ये दूसरा सवाल करें, जवाब दे देंगे। दूसरा सवाल यह किया कि क्या कार्यवाई की गई है दो जनवरी 1984 को प्रिंटिंग आर्डर दिया गया था। इस साल भी दिया है लेकिन इस साल तो किताबें आनी भुरु हो गई हैं। पिछले साल जो आर्डर दिया गया था उसकी पूरी किताबे समय पर नहीं आ सकी क्योंकि उस प्रिंटिंग प्रैस के दो पार्टनर थे। उन दोनों का आपस में झगडा हो गया था। इसलिए समय पर किताबें नहीं आ सकी। किताबें छपवाने का आर्डर कंट्रोलर प्रिंटिंग एण्ड स्टे ।नरी डिपार्टमेंट देता है और वही कार्टिरिया फिक्स करता है। कंट्रोलर के आर्डर के मुताबिक अगर कोई फर्म एक हफ्ते तक किताबें नहीं दे तो पांच परसेंट पेनल्टी, एक महीने तक न दे तो 10 प्रसेंट, डेढ महीने तक न दे तो 15 प्रसेंट पेनल्टी लगती है। प्रिंटिंग के जो रूलज़ है उनके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अभी तक उनसे किताबे लेनी है और पैसे की सेंटलमेंट करनी है।



**श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, दो साल हो गए हैं। अभी तक भाव का फ़ैसला नहीं हुआ।

**श्री निहाल सिंह:** स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बताया है कि तीसरी क्लास तक के बच्चों को फेल करने का हुक्म नहीं है और तीसरी क्लास के बच्चों को किताबें भी देर से मिली जिस कारण से उनकी पढाई नहीं हुई। अगर कोई टीचर न पढाए तो उनके काम को कैसे देखा जा सकता है? मैं मंत्री महोदय ` जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने यह पालिसी क्यों बनाई और इसका क्या कारण है?

**श्री अध्यक्ष:** यह सैपरेट क्वै चन है।

**सेठ राम दास धमीजा:** स्पीकर साहब, जहां तक किताबों की जिल्द की बात है इस बारे में अम्बाला जिले की ग्रिवेंसिज कमेटी में भी बात आई थी। जिल्द की आठ आने या 12 आने कीमत मुकरर कर देनी चाहिए। जो बिना जिल्द की लेना चाहे वह ले ले और जो मय-जिल्द के लेना चाहे वह ले ले दोनों किस्म की किताबों की कीमत मुकरर होनी चाहिए। क्या ऐसा करने का विचार है?

**श्री अध्यक्ष:** यह सप्लीमेंटरी नहीं है?

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, इन्होंने बताया कि दो जनवरी 1984 को प्रिंटिंग के आर्डर दिये गये। 8-1-1985 और 29-1-1985 को बुक्स आ रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि

जिन फर्मज को आर्डर दिये हैं, उनके नाम क्या है? दूसरे जो बुक्स आई है, उनका साइज पेपर जो इस्तेमाल हुआ उसका वेट क्या स्पैसिफिके इन के अनुसार था या नहीं? क्या बुक्स के साइज और कागज के वेट के बारे में आपके पास कोई रिक्वायत आई है, यदि आई है तो आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

**श्री जगदीश नेहरा:** पेपर की क्वालिटी के बारे में रिक्वायत नहीं आई। यदि आप रिक्वायत करेंगे तो कार्यवाही कर ली जायेगी। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि छपने के लिए किस कि को किताबें दी गई, उस बारे में निवेदन है कि पहली से पांचवी क्लास तक 13 टाईटल थे। नौ टाईटल तो गवर्नमेंट प्रैस में छपे, दो टाईटल स्वान प्रिंटिंग प्रैस जालन्धर में छपे और दो टाईटल अरुण राजीव प्रिंटिंग प्रैस चण्डीगढ में छपे हैं। जो किताबे हमारे पास लेट आई है वे अरुण राजीव प्रैस चण्डीगढ से आई है।

**श्रीमती चन्द्रावती:** क्या यह तथ्य है कि सन् 1980 से अब तक स्कूलों के बच्चों की किताबों की कमी होती रही है?

**श्री जगदीश नेहरा:** अध्यक्ष महोदय, सन् 1980 से तो मैं कह नहीं सकता कि कमी होती रही है लेकिन मैं हाउस को अ योरेन्स दे सकता हूँ कि सन् 1985-86 में किताबों की कोई कमी नहीं रहेगी। पिछले साल दो किताबों की कमी रही, इस साल वह भी नहीं रहेगी।

**Opening of Primary Health Centre at Village Banwasa**

**\*845. Shri Bhalle Ram:** Will the Minister of State for Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that for the purpose of opening a Primary Health Centre in village Banwasa in Kathura Block, (Sonepat District), the Panchayat of the said village has deposited the desired amount and has also provided the land required therefore; and

(b) if so, the time by which the said Primary Health Centre is likely to be opened?

**स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती करतार देवी):**

(क) हां। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि अभी तक स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित नहीं की गई है।

(ख) सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान।

**श्री भले राम:** स्पीकर साहब, पंचायत से सरकार ने जो चाहा था वह जमा करवा दिया और जमीन भी दे दी। इस बात को हुए कई साल हो गये लेकिन वह जमीन अभी तक हैल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुई। क्यों नहीं उसका इन्तकाल हैल्थ डिपार्टमेंट के नाम हुआ? मंत्री महोदय ने दूसरा जवाब दिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू करेंगे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल में काम चालू हो जाएगा?

**श्रीमती करतार देवी:** जहां तक काम भुरु करने का ताल्लुक है, वह तो तभी हो सकता है जब लैन्ड ट्रांसफर हो जायेगी। लैन्ड ट्रांसफर होते ही काम भुरु हो जायेगा। जहां तक जमीन ट्रांसफर का सवाल है, वह हैल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि दिनांक 21-2-1985 को डिप्टी कमी नर ने डायरेक्टर आफ पंचायत को लिखा है कि यह जमीन ट्रांसफर कर दी जाये। अभी तक हैल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुई है।

**श्री अध्यक्ष:** खानपुर जाटान गांव की जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है। चार एकड जमीन मांगी थी वह ट्रांसफर हो चुकी है। अब आपने यह कन्डी न लगा दी कि छः एकड जमीन ट्रांसफर कर दी जाये। अब गांव में छः एकड जमीन मांगे यह बहुत ज्यादा है।

**श्रीमती करतार देवी:** सर, पहले ऐसा था कि एक ब्लाक में एक ही पी० एच० सी० बनाते थे। अब थोड़े से नार्मज चेंज हो गये हैं। अब यह तय हुआ है कि 30 हजार की आबादी एक एक पी० एच० सी० बनेगा जिसमें खानपुर कोलियां का नाम भी आ जाता है। वहां पर भी हम जल्दी ही पी० एच० सी० बनाने जा रहे हैं और काम भुरु करने जा रहे हैं।

**श्री निहाल सिंह:** स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर महोदया ने यह बताया है कि नार्मज चेंज हो गये हैं। पहले एक ब्लाक में

एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर होता था लेकिन अब इन्होंने जैसे बताया है, नार्मर्ज चेन्ज होने की वजह से दूसरे ब्लॉक्स को प्रायरिटी मिलेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन से ब्लॉक्स ऐसे होंगे जिनको प्रायरिटी मिलेगी और वहाँ पर दूसरे पी० एच० सी० खुलेंगे? इसका काइटेरिया क्या होगा?

**श्री करतार देवी:** अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया है कि पहले एक ब्लॉक में केवल एक ही पी० एच० सी० बनाते थे लेकिन अब 30 हजार की पापुले 1न पर एक मोडिफाईड पी० एच० सी० बनायेंगे जिनके भवन की लागत 20-22 लाख रुपये आयेगी। यह बात अलग है कि उसमें पी० एच० सी० के मुकाबले में स्टाफ थोड़ा सा कम होगा लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हमने 395 पी० एच० सी० खोलने हैं। हमारे कुछ सबसिडीयरी हैल्थ सैन्टर्ज आलरेडी बने हुए हैं, उनको हम पी० एच० सी० में परिवर्तित कर देंगे। हमें 233 नये पी० एच० सी० बनाने पड़ेंगे। हमारे पास भारत सरकार की यह डायरेक्ट 1न है कि सन् 2000 तक 2000 तक की जनसंख्या को कवर करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं पहुंचानी हैं। इस लक्ष्य को हम सारे हरियाणा में 1999 तक पूरा कर लेंगे।

**श्री निहाल सिंह:** मैंने तो काइटेरिया पूछा था।

**श्रीमती करतार देवी:** काइटेरिया यही है कि 30 हजार की आबादी पर एक पी० एच० सी० एक ब्लॉक में हो जाएगा। पहले

जहां एक लाख की पापुले ान को एक पी० एच० सी० कवर करता था वहां अब 30,000 की पापुले ान को कवर करेगा। मान लो एक ब्लाक की पापुले ान 2-3 लाख है, तो वहां पर इसी हिसाब से नम्बर आफ पी० एच० सी० बढ़ जायेगा। अब कोइटेरिया सिर्फ पापुले ान का रह गया है। उसके लिए नार्मर्ज इस तरह से बनाये गये है कि हम पहले जहां 6 एकड जमीन मांगते थे, इसके लिए हम केवल साढे तीन-चार एकड जमीन मांगते है और पंचायत को 40 हजार रुपया जमा करवाने के लिए कहते है।

**श्रीमती भारदा रानी:** स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदया ने यह कहा है कि ब्लाक की सारी पापुले ान को कवर करने के लिए 30 हजार की पापुले ान का काइटेरिया रखा गया है। देहात की पापुले ान तो एक ब्लाक के अन्दर आ जाती है लेकिन जहां पर आबादी बहुत बढ़ गई है और बहुत बडे बडे भाहर है, उनके लिए भी क्या कोई काइटेरिया बनाया गया है? क्या वहां पर भी कोई हस्पताल और डिस्पेंसरी अधिक बनाने का कार्यक्रम है?

**श्रीमती करतार देवी:** सर यह सवाल तो पी० एच० सी० का है।

**चौधरी कुन्दन लाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बहिन हैल्थ मिनिस्टर साहिबा को यह बताना चाहूंगा कि पिछले 8-10 महीने से मेरे हल्के मुआना गावं में हैल्थ सैन्टर मंजूर हो चुका है और 45000 रुपया भी जमा करा दिया गया है। जैसे प्राअवेटल

तौर पर कहा था कि डाक्टरों और दूसरे स्टाफ के रहने का प्रबन्ध होना चाहिए। वह प्रबन्ध भी कर दिया गया है। लेकिन आज तक उस हेल्थ सैन्टर में स्टाफ नहीं गया है। मेरे हलके का यह सबसे बड़ा गांव है। इसकी कम से कम 15-20 हजार की आबादी है, आस पास कोई हेल्थ सैन्टर नहीं है। वहां पर स्टाफ भेजने का क्या कारण है? क्या जल्दी से जल्दी स्टाफ भेजने की कृपा करेंगे?

**श्रीमती करतार देवी:** स्पीकर साहब, मैंने पहले बताया है कि 30,000 की पापुलेशन के हिसाब से पी० एच० सी० बनेंगे। उस हिसाब से हमारे पी० एच० सी० जितने बनने चाहिए इनको बनाने के लिए भवनों का निर्माण कार्य इन जगहों पर चल रहा है। एक कुंजपुरा करनाल डिस्ट्रिक्ट में जल्दी ही स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा में भी काम चल रहा है। उन जगहों पर भी काम चल रहा है जहां पंचायतों से रकम प्राप्त कर ली गयी है और अनुमान तैयार करवा लिये गये हैं।

**श्री मंगल सैन:** कलानौर का भी बता दो।

**श्रीमती करतार देवी:** कलानौर का हस्पताल तो कब का चालू हो गया है। डा० साहब भायद आप कई दिनों से वैसे भी कलानौर गये नहीं हो। वैसे भी कलानौर की चिन्ता करने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सफीदो हलके के माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये मुआना गांव के बारे में मैं

उनको यह बताना चाहती हूं कि पंचायत से भूमि मिलते ही हम सबसिडीयरी हैल्थ सेंटर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं।  
(व्यवधान एवं भाोर)

**डा० औम प्रकाश भार्मा:** क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि मेरे हलके बिलासपुर ब्लॉक में, हरनौली गांव में, जहां पर सबसिडीयरी हैल्थ सेंटर मंजूर हो चुका है, उसपर काम शुरू कर दिया गया है या नहीं? अगर नहीं, तो कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है?

**श्रीमती करतार देवी:** सर, इस समय हमारे पास सबसिडीयरी हैल्थ सेंटर की इन्फर्मेेशन नहीं है। इस समय तो प्राइमरी हैल्थ सेंटर के बारे में इन्फर्मेेशन है। जहां तक सबसिडीयरी हैल्थ सेंटर का सम्बन्ध है, मैं डाक्टर साहब को एक बात बता सकती हूं कि जब भी हम किसी ब्लॉक में प्राइमरी हैल्थ सेंटर बनाते हैं तो सबसिडीयरी हैल्थ सेंटर की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि 30 हजार की पापुलेशन के लिए हम मॉडर्न पीओ एचओ सीओ बनाने जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम 233 नये पीओ एचओ सीओ बनायेंगे। यह बात सैद्धांतिक रूप में स्वीकार की जा चुकी है। जहां पर हम स्वीकृति दे चुके हैं, वहां पर हम ये मॉडर्न पीओ एचओ सीओ जरूर बनायेंगे। जहां तक किसी जगह पर बिल्डिंग बनाने की बात का सम्बन्ध है, इसके लिए फण्डिंग की बात सबसे पहले आती है। हमारे पास पिछले साल 597 लाख रुपया था जिसमें से निर्माण कार्य के लिए बहुत थोडा



पैसा रखा गया था। अब 1985-86 के लिए हमें 8.72 करोड़ रुपया दिया गया है जिसमें से 280.78 लाख रुपया निर्माण कार्य के लिए होगा।

**डा० औम प्रकाश भार्मा:** मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो सबसिडीयरी हेल्थ सेंटर मंजूर हो चुका है, क्या उसकी बिल्डिंग आप इसी साल बनायेंगे?

**श्रीमती करतार देवी:** जरूर बनायेंगे। मैं यह बताना चाहती हूँ कि जहां हम सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे चुके हैं, वहां जरूर बनायेंगे और नये साल में काम शुरू कर देंगे।

**चौधरी धीर पाल सिंह:** बहन जी को भी पता होगा और मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी को भी पता है। ये दो दफा बादली में गये थे। वहां की पी० एच० सी० की बिल्डिंग की खस्ता हालत देखकर यह कह कर आये थे कि जल्दी ही हम आपको बना देंगे। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस पी० एच० सी० के भवन को बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

**श्रीमती करतार देवी:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने बताया है कि वहां पर पी० एच० सी० का भवन है तो परन्तु खस्ता हालत है। इसलिए वहां पर भवन निर्माण का कार्य जल्दी शुरू किया जाये। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि ज्यों ज्यों हमें पैसा मिलेगा और जहां जहां पर पी० एच० सी० या

सबसिडीयरी हैल्थ सेंटर या दूसरे किसी भवन की हालत खस्ता है, उसका निर्माण कार्य पहले किया जाना चाहिए हम अब य ही इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

### **Nathpa Jhakri Hydel Project**

**\*875. Shri Hira Nand Arya & Dr. Bhim Singh**

**Dahiya:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) amount of expenditure so far incurred by the Haryana State for the construction of Nathpa Jhakri Hydel Project situated in Himachal Pardesh; and

(b) whether there is any proposal to hand over the project to Government of India; if so, details thereof?

**Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):**

(a) The State has incurred an expenditure of Rs. 2.12 crores on Nathpa Jhakri Hydle Electric Project so far.

(b) It has been recently decided that this project is now to be constructed in central sector by National Hydro-Electric Power Corporation with the association of Himachal Pradesh in view of limitation of financial resources. However, allocation of 30 to 35% of power to Haryana for meeting the deficit is under consideration of the Central Government.

**श्री हीरा नन्द आर्य:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि निर्माण केन्द्रीय सैक्टर में राष्ट्रीय जलीय विद्युत

परियोजना निगम द्वारा किया जायेगा। इन्होंने यह बात तो मान ली है कि यह काम अब सैन्टर की एजेंसी के द्वारा किया जायेगा लेकिन हमारा बिजली में हिस्सा क्या होगा, इस बारे में यह कहा है कि यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहले जो एग्रीमेंट हिमाचल सरकार के साथ हुआ था, उसमें हमारा कितना हिस्सा था? जब हिस्से वाली बात पहले से ही तय भुदा थी तो फिर से कंसीडर करने की बात कैसे आ गई? जिस तरह से इस प्रोजैक्ट को हैण्ड ओवर किया गया है, उसी तरह से हमारा तय भुदा हिस्सा भी ट्रांसफर होना चाहिए था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पहले हमारा हिस्सा क्या था और अब क्या डिमांड किया गया है?

**चौधरी भाम शेर सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक हमारे हिस्से की बात है, इस बारे में मुख्य मंत्री जीने पहले ही हाउस में कैटेगोरीकली बता दिया है। मैं उसी बात को दोबारा कह देता हूँ। इनका कहना यह है कि जब यह फैसला हुआ कि यह काम एन० एच० पी० सी० करेगा, तो यह फैसला भी हो जाना चाहिए था। हरियाणा के पास दोनो प्रोजैक्ट को एक साथ एक्सीक्यूट करने के रिसोर्सिज नहीं है। सितम्बर, 1984 में गवर्नमेंट आफ इंडिया से यमुना नगर थर्मल प्लांट की एप्रुवल फाइनली आ चुकी है। इसलिए यह तय किया गया है कि हम यमुनानगर थर्मल प्लान का काम करेंगे। उसमें भी 400 करोड रुपये का खर्चा होगा, यह सातवीं प्लान का प्रोजैक्ट है। इसके साथ ही दूसरे प्रोजैक्ट में

भी 400-500 करोड रुपया खर्च होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक हजार करोड रुपया हम सातवीं प्लान में इस प्रोजैक्ट पर भायद खर्च नहीं कर पायेंगे, इसलिए यह फैसला हुआ कि यमुनानगर थर्मल प्लांट का काम हम अपने आप एक्सीक्यूट कर ले और नाथपा झाखडी हाईडल प्रोजैक्ट का काम एन० एच० पी० सी० को सैन्ट्रली फन्डिड प्रोजैक्ट के तौर पर करने दें। जहां तक भोयर के डिटरमिनेशन का सवाल है, वह एन० एच० पी० सी० और हिमाचल सरकार आपस में फैसला करेंगे। अभी यह मसला बाकी है। फिलहाल यह सवाल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में जाएगा। अभी वह स्टेज नहीं पहुंची है। हमें इस बात का आवासन दिया गया है कि हमारा इंट्रस्ट सेफगार्ड रहेगा। स्पीकर साहब, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है कि अब कितनी राशि है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि लेटैस्ट ऐस्टीमेटिड कोस्ट आफ द जनरेशन की राशि 656.17 करोड रुपये है और ट्रांसमिशन की राशि 140.64 करोड रुपए है। दोनों को मिलाकर 796.81 करोड यानी लगभग 800.00 करोड रुपया बनती है।

**श्री मनफूल सिंह:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 2.12 करोड रुपया नाथपा झाखडी प्रोजैक्ट के लिए हरियाणा सरकार ने दिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपए में से लेबर पर कितना खर्च हुआ, दूसरे कामों पर कितना खर्चा हुआ और अपने पास कितना रखा?

**चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, बारह लाख रुपया असठैबलि ामेंट पर खर्च हुआ और दो करोड हिमाचल बिजली बोर्ड को इंफास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया अगर फाइनल स्टेज पर यह फैसला हुआ कि रुपया इंवैस्ट करने में हरियाणा का कोई ताल्लुक नहीं होगा तो यह रुपया उस वक्त एडजस्ट हो जाएगा।

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, अभी तो नाथपा झाखडी का प्रोजैक्ट भुरु भी नहीं हुआ। क्या मंत्री महोदय बताएँगे कि यह 2.12 करोड रुपया कहां चला गया? क्या इसका कोई हिसाब किताब है?

**चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, दो करोड रुपया हिमाचल बिजली बोर्ड को दिया था और इस रुपए से उसने वहां पर सडकें बनाई और कालोनीज बनाई है। इंफास्ट्रक्चर बनाने के लिए हिमाचल बिजली बोर्ड ने अपने पास से भी खर्चा किया और इस रुपए से भी खर्च किया।

**श्री विरेन्द्र सिंह:** गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए मुख्य मंत्री जी ने ए योरेन्स दी थी कि नाथपा झाखडी प्रोजैक्ट में जो हमारा हिस्सा तय हुआ था, वह हमको मिलेगा। लेकिन आज ये उस स्टैंड से डेविएट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मिनिस्टर आफ इरिगे ान एण्ड पावर ने कहा है कि हमने नाथपा झाखडी प्रोजैक्ट पर इसलिए खर्च करना बन्द कर दिया कि

हमारे रिसॉर्सिज़ इतने नहीं थे कि हम उस पर भी पैसा खर्च करते और अपने ऑन गोइंग प्रोजैक्ट पर भी खर्चा करते। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह अच्छा नहीं होता कि जब हमारा हिमाचल सरकार से एग्रीमेंट हो चुका था और उसमें हमारी बिजली भी एन् योर हो चुकी थी, तो पहले हम उस प्रोजैक्ट को पूरा करते ताकि जो बिजली हमें वहां से मिलनी थी वह जल्दी मिलती और ज्यादा भी मिलती, और अपने प्रोजैक्ट को बाद में हाथ में लेते?

**चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, बात यह है कि हिमाचल और हरियाणा में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुंताबिक उस प्रोजैक्ट को पूरा होने में सात-आठ साल लगेंगे और उसका बैनिफिट सात-आठ साल के बाद ऐकू होता। हरियाणा में जो ऑन गोइंग प्रोजैक्ट है उसमें से एक यूनिट इस साल के अन्त में कम्पलीट हो जाएगा। और इससे हमें 210 मैगावाट बिजली मिलेगी। एक प्रोजैक्ट अगले साल के जून तक कम्पलीट हो जाएगा। यमुनानगर का जो प्रोजैक्ट है वह सातवीं प्लान से पहले बनकर तैयार हो जाएगा और उससे 425 मैगावाट बिजली मिलेगी। इसलिए ऑन गोइंग प्रोजैक्ट को पहले कम्पलीट करना जरूरी था। स्पीकर साहब, नाथपा झाखडी और अपने ऑन गोइंग प्रोजैक्ट पर साइमल्टेनियसली रुपया इंवैस्ट करना हरियाणा सरकार के लिए फिजिबल नहीं था। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि हमारी स्टेट से बाहर के जो प्रोजैक्ट, जैसे बदरपूर का है और

संगरोली का है जिनसे हमें बिजली मिलती है, वहां से हमें पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता है। वहां से बिजली लाने में हमें दिक्कत रहती है। हमारी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट में यही था कि हम पहले अपने ऑन गोजिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लें। स्पीकर साहब, जहां तक स्टेट को उस प्रोजेक्ट से बिजली मिलने का सवाल है, हमें इस बात की पूरी तसल्ली है, हमें जबानी आ वासल मिला है और वह आ वासन लिखित में भी आ जाएगा कि हमें 30-35 प्रसेंट भोयर उस प्रोजेक्ट में से मिलेगा। स्पीकर साहब, यह भोयर हमें बगैर इंवेस्टमेंट के मिल जाएगा। इससे ज्यादा लाभदायक प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए और क्या हो सकती है?

**चौधरी नेकी राम:** स्पीकर साहब, बिजली आज के जमाने में तरक्की का एक बहुत बड़ा साधन है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नाथपा झाखडी प्रोजेक्ट को सात आठ साल के बताये पांच साल में कम्प्लीट कराने की कृपा करेंगे?

**चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, यह प्रोजेक्ट लम्बा है, इसमें काफी समय लगेगा।

**डा० भीम सिंह दहिया:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा है कि उस प्रोजेक्ट में हरियाणा का भोयर तीस से पैंती परसेंट तक होगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट में भोयर होल्डर नहीं रहेगे तो हमारा स्टेटस परचेजर का होगा या कुछ और होगा? दूसरा मेरा सवाल यह है

कि लाइनें बिछाई जाएंगी, इन की कोस्ट हम बीयर करेंगे या हिमाचल सरकार करेगी?

**चौधरी भामेरा सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, जब हम खर्च में भोयर नहीं करेंगे तो बिजली में हमारा भोयर नहीं होगा। हमें कितनी बिजली मिलेगी, इसको एन योर करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि जो सैन्टर का भोयर है उसमें से हमें बिजली मिल जाए। दूसरा यह है कि सैन्टर हमें ज्यादा बिजली एलोकेट कर सकता है। तीसरा यह हो सकता है कि हिमाचल को उतनी बिजली की जरूरत न हो और हम उससे बिजली परचेज कर लें। ये तीन चार बातें हो सकती हैं। सैन्टर के एनर्जी सैक्रेटरी ने यह कहा था कि हरियाणा को पूरी बिजली दी जाएगी। स्पीकर साहब, फैसला करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा और यह एन योर करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि हरियाणा को अधिक से अधिक बिजली मिल सके। स्पीकर साहब, हमारा स्टेटस परचेजर का होगा।

**Mr. Speaker:** Question House is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों  
के लिखित उत्तर

#### **Lavatories for Women**

**\*880. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to



construct lavatories for women in any of the villages in the State, if so, details thereof?

विकास मंत्री(श्री राजिन्द्र सिंह): जी नहीं।

**Electricity received from various sources**

**\*908. Sh. Mangal Sein:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total quantum of electricity required to be received and actually received by the H.S.E.B from various sources during the period from 1<sup>st</sup> January, 1984 to-date;

(b) whether it is a fact that the State Chief Minister and Irrigation and Power Minister made surprise visits to Panipat and Faridabad Thermal Plants during January and February, 1985; and

(c) if reply to part (b) is in affirmative whether any officers/officials were suspended as a result of the said visits; if so, the names and designations of all such officers/officials?

**Irrigation and power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala);**

(a) The total quantum of electricity required to be received and actually received by H.S.E.B. from 1-1-84 to 28-2-85 from various sources is as under:-

Total quantum of electricity required to be received	Actually Availability

(figures in lac units)	
56598	49038

(b) Yes.

(c) No.

**T.A/D.A and Telephone Bills of Chief Minister, Ministers  
etc.**

**\*922. Ch. Om Parkash & Sh.Ram Bilas Sharma:**

Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of expenditure incurred on T.A/D.A and telephone bills of Chief Minister, Ministers, Ministers of State and Chief Parliamentary Secretary from 1<sup>st</sup> April, 1984 to-date, separately?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अपेक्षित सूचना का एक विवरण (अनुबन्ध 'क') सदन के पटल पर रखा जाता है।

**अनुबन्ध 'क'**

मुख्य मंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिव के यात्रा/दैनिक भत्ता तथा टैलिफोन बिलों का दिनांक 1-4-84 से 28-2-85 तक की अवधि के दौरान खर्च की गई राशि की सूची

क्रम	नाम तथा पद	यात्रा भत्ता/ दैनिक	टैलिफोन के खर्चे के बिल (कार्यालय तथा	रिमाक्स

		भत्ता	आवास)	
1	श्री भजन लाल, मुख्य मन्त्री	15903.00	294831.30	श्री राजे ा भार्मा राज्य मन्त्री श्रम एवं रोजगार को अमेरिका में इलाज के लिए 2 लाख रु की राि ा यात्रा भत्ता एडवांस दी गई है ।
2	श्री भाम ेर सिंह, सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री	8737.00	90279.50	
3	कर्नल राम सिंह, परिवहन मन्त्री	18606.00	72658.50	
4	श्री राजेन्द्र सिंह, विकास मन्त्री	7584.00	92911.00	
5	श्रीमती प्रसन्नी देवी, लोक निर्माण मन्त्री (जन-स्वास्थ्य)	12868.00	83472.00	
6	श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया, उद्योग मन्त्री	7362.25	30576.00	
7	श्री कटार सिंह, आबकारी एवं कराधान मन्त्री	7558.00	47356.60	
8	श्री कल्याण सिंह, खाद्य	8640.00	33917.60	

	एवं आपूर्ति मंत्री			
9	श्री अमर सिंह धानक, लोक निर्माण मंत्री (भवन तथा सडके)	4797.25	21313.00	
10	श्री सागर राम गुप्ता, वित्त मंत्री	1500.00	4855.00	
11	श्री गोवर्धन दास चौहान, वन एवं जेल मंत्री	1200.00	1410.00	
12	श्री लाल सिंह, राज्य मंत्री प उपालन	8148.00	80362.50	
13	*श्री राजे टा कुमार, राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार	4887.00	62042.90	
14	श्री चन्दा सिंह, राज्य मंत्री परिवहन	11282.00	98165.00	
15	श्री जगदी टा नेहरा, शिक्षा	8362.00	108368.00	
16	श्री लक्ष्मण दास अरोडा,	15114.00	69748.80	

	राजस्व			
17	श्री प्यारा सिंह, स्थानीय भासन	4988.00	10571.20	
18	श्रीमती करतार देवी, स्वास्थ्य	3300.00	11886.40	
19	श्री रोान लाल, मुख्य संसदीय सचिव	3675.00	10718.60	

**भुतपूर्व मंत्री**

1	श्री हरपाल सिंह, कृषि	1644.00	22473.30	30-12-84 से त्यागपत्र
2	श्री बिरेन्द्र सिंह, सहकारिता एवं डेरी विकास मंत्री	6414.00	70567.30	यथोपरि
3	श्री रहीम खान, सिंचाई एवं विद्युत	5760.00	30464.60	यथोपरि
4	श्री बृज मोहन सिंगला, आबकारी एवं कराधान	459.00	27861.30	31-5-84 से त्यागपत्र

### Distance covered by the vehicles used by Ministers

\*914. **Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state the Minister wise number of kilometers covered by the vehicles used by the members of Haryana Cabinet during the period from 20<sup>th</sup> Nov, 1984 to 24<sup>th</sup> Dec, 1984?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वांछित सूचना संलग्न सूची में दी जाती गई है।

### सूची

क्रम	मंत्री परिशद के सदस्य का नाम	सरकारी यात्रा	निजी यात्रा	कुल
1	श्री भजन लाल, मुख्य मंत्री	6108	7402	13510
2	श्री एस एस सूरजेवाला, मंत्री	5016	600	5616
3	कर्नल राम सिंह, मंत्री	6471	—	6471
4	श्री राजेन्द्र सिंह, मंत्री	4266	—	4266
5	श्रीमती प्रसन्नी देवी, मंत्री	6120	—	6120
6	श्री सागर राम, मंत्री	8433	—	8433
7	श्री गोवर्धन दास चौहान,	1980	—	1980

	मंत्री			
8	श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया, मंत्री	5495	—	5495
9	श्री कटार सिंह, मंत्री	4802	984	5786
10	श्री कल्याण सिंह, मंत्री	3081	249	3330
11	श्री अमर सिंह, मंत्री	10053	—	10053
12	श्री लाल सिंह, राज्य मंत्री	7803	—	7803
13	श्री प्यारा सिंह, राज्य मंत्री	3537	—	3537
14	श्री राजे ा कुमार, राज्य मंत्री	3141	—	3141
15	श्री चन्दा सिंह, राज्य मंत्री	6709	311	7020
16	श्री लक्ष्मण दास, राज्य मंत्री	5715	—	5715
17	श्री जगदी ा नेहरा, राज्य मंत्री	3409	200	3609
18	श्रीमती करतार देवी, राज्य मंत्री	6561	—	6561
19	श्री रहीम खान, राज्य मंत्री	2530	40	2570

20	श्री हरपाल सिंह, मंत्री	3943	1178	5121
21	श्री बिरेन्द्र सिंह, मंत्री	783	412	1195
22	श्री रोशन लाल, सी० पी० एस०	4170	70	4240
23	श्री मोहन लाल पीपल, संसदीय सचिव	3015	—	3015

### **Converting the Surgical Centre Sonapat into Polytechnic**

**\*935. Shri Devi Dass:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert Surgical Centre, Sonapat, into Polytechnic College;

(b) the names of such officers/employees of the said Surgical Centre, if any, as are working there for the last more than 5 years;

(c) whether any students of the said Surgical Centre went on strike during the last three years; if so, the details of their demands together with the action, if any, taken thereon; and



(d) whether any complaint alleging embezzlement in the said Surgical Centre has come to the notice of the Government; if so, the action, if any, taken thereof?

**Minister of State for Transport (Ch. Chanda Singh):**

(a) Yes.

(b) A statement is laid on the Table of the House as at Annexure-I.

(c) Yes. A statement showing the demands of the students and the action taken thereon is laid on the Table of the House at Annexure-II.

(d) Yes. An anonymous complaint alleging embezzlement in the purchase of some items purchased during the year 1979 & 1980 at this Institute was received by the Government during 1983. No embezzlement was found in these transactions on investigation.

#### **ANNEXURE-I**

List of Officers/Employees of Government Institute of Surgical Technology, Sonapat who are working there for more than 5 years as on 11-3-1985.

<b>Sr.No.</b>	<b>Name &amp; Designation</b>	<b>Date since when working</b>
---------------	-------------------------------	--------------------------------

1	<b>Principal</b> D. M. Talwar	10-5-61
2	<b>Senior Lecturer</b> P. R. Dhawan	1-11-77
3	<b>Lecturers</b> S. C. Abro Kuldip Singh N. K. Bajaj	11-8-67 21-11-68 14-4-69
4.	<b>Superintendent Workshop</b> Gurdial Singh	16-4-60
5	<b>Junior Instructors</b> B. D. Prothi P. K. Jain V. P. Sharma Madan Gopal	10-9-55 4-3-62 10-3-62 7-10-63
6	<b>Drawain Instructor</b> N. D. Monga	25-3-72
7	<b>Mechanic</b> Sham Dass	30-10-69

8	<b>Ministerial and other Supporting Staff</b> M. L. Khurana, Head Clerk Ram Mehar, Accountant Ram Phal, Cashier Babu Lal, Storekeeper Tuli Ram, Daftri Raghu Nath, Lab. Attendant Guru Dutt, Lab Attendant Jagdish Chander, Lab Attendant Banwari Lal, Workshop Cooli Sukh Lal, Worksop Cooli Ram Dayal, Peon Sri Krishan, Peon Dalip Singh, Peon Pale Ram, Chowkidar Sunder, Chowkidar Hari Singh, Sweeper Itbari, Sweeper	29-11-67 2-8-66 5-10-71 1-5-73 19-6-48 5-1-79 13-11-79 30-11-79 25-7-63 19-2-69 18-12-65 1-1-67 21-1-67 24-9-54 14-8-75 13-11-65 2-6-76
---	--	---

	Total No of with more than 5 years stay as on 11-3-1985	29
--	---	----

**ANNEXURE-II**

<b>Demand of students of Govt. Institute of Surgical Instruments Technology Sonapat, made in Nov. 1983 and March, 1984</b>	<b>Action Taken</b>	<b>Remarks</b>
1. The Students demanded departmental audit of the students Fund Account.	The student fund Account was got audited by the local auditors of the examiner, local fund accounts, Haryana in Sep, 1983 and also by the Accounts Officer of Technical Education, Haryana, Chandigarh, during January/March, 1984 The Principal was directed to supply the documents and sanctions asked for to the Auditors. Necessary sanctions and documents will be produced to the audit at the time of next inspection.	
2. The diploma being given at Sonapat Institute should be made more broad based and cover more areas to increase the scope of	The matter was examined by an expert Committee of the Northern Regional Committee in the All India Council for Technical Education at Govt.	

<p>employment. its nomenclature should also be changed.</p>	<p>Institute of Surgical Instruments Technology, Sonapat, on 24-1-85. The Committee recommended the introduction of three revised courses at this Institute for Production Engineering &amp; Industria Management, Tool and Die Engineering and Chemical Engineering. Final action will be taken on receipt of Govt. of India's approval.</p>	
<p>3. The Principal should teach the classes himself.</p>	<p>This is being done.</p>	
<p>4. Repairs to the hostel should be expedited.</p>	<p>The P.W.D B&amp;R has since completed the repairs during Nov. 1984.</p>	
<p>5. The hostel fund should be got checked and accounted for</p>	<p>The hostel funds were got checked and found to be upto date.</p>	
<p>6. An instructor in Sports should be posted</p>	<p>The post has been filled since 6-2-84.</p>	
<p>7. Sportsmen of the Institute should be given advantages as allowed in other Polytechnics.</p>	<p>Except reservation of 2% seats at the time of admission to the Institution, no other special benefit is given to any sportsmen/women of the Polytechnic in the State.</p>	

	Facilities of equipment posting of a PTI and organizing of tournaments etc. are arranged for the sportsmen in the Polytechnics and in the S.I.T. Sonapat.	
8. The doctor may be appointed.	a part-time doctor stands appointed since 2-12-1983	
9. The employees of the Institute and hostel should work on their respective jobs.	This has been ensured.	

**Taking Over Control of Agra Canal in Haryana Territor**

**\*930. Ch. Khillan Singh:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the control of the part of the Agra Canal as falls in the Territory of Haryana. if so, the time by which the said proposal is likely to materialize?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): जी हां। यह मामला उत्तर प्रदेश 1 और भारत सरकार के साथ तत्परता के साथ परस्यू कर रहे है। परन्तु यह अन्तर्राज्यी तथा नीति सम्बन्धी विषय होने के कारण इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि यह चैनलें हरियाणा को कब तक स्थानान्तरण हो जायेंगी।

## **Class II, III and IV posts in the cooperation Department**

**\*947. Master Ram Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of class II, III and IV posts in the cooperation Department at present separately; and

(b) the number of posts, out of those referred to in part (a) above, if any, filled up in accordance with the prescribed reservation quota separately?

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** क तथा ख – विवरण सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

### **विवरण सूची**

(क) सहकारिता विभाग में वर्तमान श्रेणी 2, 3 तथा 4 के पदों की कुल संख्या इस प्रकार है—

श्रेणी 2 – 47

श्रेणी 3 – 1934

श्रेणी 4 – 362

(ख) उक्त भाग (क) में वर्णित पदों में से निर्धारित आरक्षण कोटा के अनुसार भरे गए पदों की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्रम	पद संख्या	अनुसूचित जाति	पिछडे वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	भारीरिक तौर पर अपंग
1.	श्रेणी 2	8	2	1	—
2.	श्रेणी 3	293	148	70	7
3.	श्रेणी 4	87	55	42	8

### विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री विरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। मुझे अभी अभी श्री बलबीर सिंह, एक्स चेयरमैन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फतेहाबाद, जो स्टेट एकजेटिव बी० जे० पी० के मैम्बर भी है, की ओर से एक टेलीफोन मिला है। उन्होंने टोहाना बाई-इलैक्शन में श्री भाम लाल सरदाना की मदद की थी। उनका एक ट्रक ट्रक-यूनियन फतेहाबाद में है। मुख्य मंत्री महोदय के भाई ने उस ट्रक को ट्रक-यूनियन में से निकलवा दिया है। उसे व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आगे उन्होंने टेलीग्राम में यह भी लिखा है कि मेरी लाईफ को भी खतरा है और ट्रक बिजनेस से मुझे डिबार कर दिया गया है। इनके भाई का बकायदा नाम दिया गया है। स्पीकर साहब, यह बड़ा ही सीरियस मामला है। आपको इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। (गौर एवं व्यवधान)।



**चौधरी औम प्रकाश:** स्पीकर साहब, कल दिनांक 18-3-85 को रात के साढ़े नौ बजे एक ट्रक नम्बर एच0 वाई0 एफ0 2272 हिसार से चंडीगढ़ के लिए आ रहा था। रास्ते में कैथल और पिहोवा के बीच में पिहोवा के बैरियर पर जब वह ट्रक पहुँचा तो बैरियर वालों ने उस ट्रक को जबरदस्ती रुकवाया और उस ट्रक वाले को कहा कि टैक्स देने के लिए तुम ने लाईट देने के बावजूद भी ट्रक क्यों नहीं रोका। उसने आगे कहा कि आपको पता है कि यह \* \* \* का ट्रक है और भाराब की बोटले उस ट्रक में रखी हुई थी। ( गोर) स्पीकर साहब, यह बडा ही सीरियस मैटर है। मैने इस बारे में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस भी भेजा है। स्पीकर साहब, इस बारे में सरकार को अवश्य वक्तव्य देना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** औम प्रकाश जी आप बैठिए। यह नाम नहीं आयेगा।

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, मुझे एक लैटर मिला है, उसमें लिखा है कि कुछ लोगों को हरियाणा राज्य परिवहन डिपो, यमुनानगर में रोजगार कार्यालय द्वारा 26-7-84 को लगाया गया था। यह पत्र 29 आदमियों द्वारा भेजा गया है। इस के अनुसार 56 प्रार्थियों को नियुक्त किया गया था। चीफ मैडिकल आफिसर, अम्बाला द्वारा उनका मैडिकल भी करवाया गया था, एक महीने की ट्रेनिंग भी दी गयी थी लेकिन उनमें से 29 प्रार्थियों को, तीन महीने बाद, बिना कारण बताए, बिना वेतन दिये, बिना कोई

नोटिस दिये निकाल दिया गया है। इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से रिकवैस्ट है कि उन लोगों का क्या कसूर है जिनको हटा दिया गया है? उनको न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों को दोबारा नौकरी में लिया जाना चाहिए। इन प्रार्थियों से पहले 5-5, 10-10 हजार रुपये लेकर भर्ती किया गया था। और अब बिना कारण बताये, नौकरी से निकाल दिया गया है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। सर, मैं इस लैटर को आन दी टेबल आफ दी हाउस पर रखने के लिए तैयार हू।

**श्री अध्यक्ष:** आप इस लैटर को मेरे चैम्बर में भेज देना।

**श्रीमती चन्द्रावती:** ठीक है जी।

**श्री मंगल सैन:** अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं जीरो आवर में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ था और आपने यह कहा था कि आपने जो नोटिस दिया था, मैं उसे देख लूंगा। आ ग है आपने अब तक मेरा नोटिस जो फरीदाबाद में काम कर रहे मजदूरों की जिंदगी को खतरे के बारे में है, को देख लिया होगा।

**श्री अध्यक्ष:** डाक्टर साहब, जो वर्ज से सम्बन्धित आपका काल अटैन् इन नोटिस था, उस पर मैंने 48 आवर्ज में सरकार से कामेंट्स मांग लिये हैं।

**श्री मंगल सैन:** अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी रोहतक में एक चुनाव सभा में कह कर आये थे कि चुनाव के बाद मैं रोहतक में पानी ही पानी कर दूंगा। रोहतक की दो लाख के

करीब आबादी है और वहां पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। इन्होंने यह भी कहा था कि घर घर में पानी पहुंचा दूंगा, वह तो पहुंच ही रहा है लेकिन छः दिन से वहां पर पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत लोगों को हो रही है।

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, इसी प्वायंट पर श्री औम प्रकाश बेरी की तरफ से भी एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस आया हुआ है। उस पर मैंने 48 आवर्ज में सरकार से कामेंट्स मांग लिये हैं।

**श्री मंगल सेन:** तीसरी बात तार वाली है जिसके बारे में अभी मेरे भाई विरेन्द्र सिंह जी ने भी जिक्र किया है। भजन लाल जी अभी इंकार कर देंगे जैसी की इनकी आदत है। सरकार को इस बात की जांच करवानी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, ये छोटी छोटी बातें हैं। आप यह बताएंगे कि हर बात की इस असैम्बली की ही जिम्मेवारी है?

**श्री मंगल सेन:** स्पीकर साहब, सरकार की हर बात के लिए जिम्मेवारी बनती है। लोगों की जिन्दगी का सवाल है। चुनाव में मुखालफत कर दी तो यूनियन से निकलवा दिया। कभी कह देते हैं कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। कभी पिस्तौल छाती पर रख देंगे। स्पीकर साहब, मुकद्दमे दर्ज हुए हैं, बड़ा सीरियस मैटर है। इन बातों की जांच होनी चाहिए।

**Mr. Speaker:** He is replying to your point.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इन को तो फोबिया हो गया है। ( गोर एवं व्यवधान) चौधरी वीरेन्द्र जी ने अभी श्री बलबीर सिंह का एक टेलीग्राम पढ़ कर सुनाया। उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वे भारतीय जनता पार्टी फतेहाबाद के वर्कर है। मैं भी उसी तहसील का हूँ। कांग्रेसी तो वे कभी हुए नहीं। पहले जनसंघ में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में है। ( गोर) वहां पर हमें कांग्रेस ने इलैक्ट्रान लडा है और बाई-इलैक्ट्रान भी फतेहाबाद में हुआ था जिन में कांग्रेस जीतती रही है। कोई व्यक्ति यूँ ही नहीं कह दे कि फलां जगह मेरे साथ ज्यादाती हुई है तो कोई बात नहीं बनती। उसका किसी के साथ झगडा हो गया होगा, किसी से कले ा हो गया होगा जिसकी वजह से उसका नम्बर काट दिया होगा। बगैर नम्बर के कोई माल लाद कर जा रहा होगा। इस किस्त का कोई कारण हो सकता है। लेकिन बगैर मतलब के यह कह देना कि भजन लाल के भाई ने नम्बर काट दिया गलत है। कोई आदमी रोहतक में गुनाह कर दे तो कह देते हैं कि भजन लाल के भाई ने कर दिया होगा। इनको तो हर बात का फोबिया हो गया है, इसका कोई अन्त नहीं है। कोई बात अगर कहनी है तो सबूत के साथ कहें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इनकी तरह नहीं, गलती करे भी और माने भी नहीं, अगर कोई गलती हमसे हुई है तो हम ठीक करेंगे। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस तरह की बे-बुनियाद बेसलैस बातें सदन में कहना, जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है जिन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, उनको यहां सदन में कहना

भाभा नही देता। ( गोर एवं व्यवधान) कोई ठोस बात हो तो कहे, हम खुशी से सुनेंगे।

**चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल:** स्पीकर साहब, भिवानी में पीने के पानी की समस्या है। बिजली की कमी के कारण भी फसलें तबाह हो गयी हैं। इस बारे में मैंने एक कॉल अटैन्शन मोड का नोटिस दिया था उसका क्या बना है जी?

**श्री अध्यक्ष:** मैंने उस पर कमेंट्स मंगवा लिए हैं।

**चौधरी मनफूल सिंह:** स्पीकर साहब, मुझे एक ऐप्लीकेशन मिली है और इस बारे में अखबारों में भी खबर छपी है कि दहेज के लालचियों ने एक विवाहिता को जला कर मार डाला है। यह मेरे हलके असंध के एक गरीब परिवार की घटना है। ऐप्लीकेशन में लिखा है कि 27-8-84 को मैंने अपनी लडकी की भाादी बडी धूमधाम से की थी। भाादी के बाद मेरा दामाद दहेज का लालची हो गया ( गोर) मैं भारत में बता देता हूँ। 25-2-85 को उस लडकी को लडके वाले अपने घर ले गये और 1-3-85 को उस लडकी को आग लगाकर जला दिया। हिसार में उन्होंने पुलिस में रपट दर्ज करवाई लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। स्पीकर साहब, यह बडा ही जरुरी सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए। आम लोगों की बहु-बेटियों को दहेज के लालच में जला कर मारा जा रहा है। जिस परिवार ने इस तरह का कुकृत्य किया है, उसके खिलाफ सरकार को उचित

कार्यवाही करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसे लोगो को इस तरह के काम करने की जुरत न हो। मै इस पत्र को आन दी टेबल आफ दी हाउस रखता हूं।

**चौधरी भजन लाल:** चौधरी मनफूल सिंह जी, आप यह लैटर मेरे पास भिजवा दें।

**चौधरी मनफूल सिंह:** अच्छा जी।

**श्री भागी राम:** अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने सिरसा जिले के रानियां कस्बे में जलसा किया था। वहां उन्होंने लोगो की डिमांड को देखते हुए सब-तहसील बनाने की अनाउंसमेंट की थी लेकिन अब तक उस बारे वहां काम चालू नहीं हुआ। उसके बाद लोगों की यह भावना बन गई है कि मुख्य मंत्री जी केवल घोशणा ही करते रहते हैं और काम कोई करते नहीं। ( गोर) इस बारे में मैने लिख कर भी दिया है।

**श्री अध्यक्ष:** मै इसे कंसिडर करुंगा।

**श्री मंगल सेन:** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मै आपकी रुलिंग चाहता हूं कि सदन में गवर्नर एड्रैस पर या सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स पर हम अपनी बात कहते है जो हमें रुल्ज़ के मुताबिक कहने का अधिकार है अगर उस दौरान हम मुख्य मंत्री जी का ध्यान इनकी ज्यादतियों पर लाएं तो ये बडे नाराज होकर कहते है कि मै आपकी तरह बे आधारित बात नहीं करता। ये जो चाहे कब दें क्योकि ये मुख्य मंत्री है \* \* \* \* \* और

बडी अम्ब्रेसिंग पोजी तन हो जाती है। हमें तो बकायदा आपकी इजाजत लेकर बात करनी पडती है। मैं कहना चाहता हूं कि जीरो आवर इसी परपज़ के लिए है कि गवर्नमेंट की कोई ज्यादाती हो या किसी इंडिविजुयल का फंडामेंटल राइट एनक्रोच होता हो तो हम इस वक्त मामला सदन में उठा सके। (विघ्न) अगर ऐसी बात कहने के लिए यह फोरम नहीं है तो कौन सा फोरम है। किसी मैम्बर को अगर ऐसी बात कहने का भी राइट नहीं है तो क्या किया जाए ( गोर)।

**राजस्व मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा):** @ @ @ @ @ @  
@ @ @ @ @

**श्री हरि चन्द हुडडा:** स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल ने क्या कसूर किया है। पिछले 37 सालों में जो भी बडा आदमी हुआ उसने क्या नहीं बनाया। \*\* \*\* \* \* \* \* \* अगर हिन्दुस्तान का कोई बडा आदमी इससे बचा न हो तो उसका क्या कसूर है? ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** यह नाम रिकार्ड न किया जाए।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, इनका तो सिवाए इन बातों के और कोई काम ही नहीं होता। ये कोई नीति की या स्टेट के हित की बात नहीं करते। जैसा कोई इन्सान खुद होता है वह वैसा ही दूसरों के बारे में सोचता है। यह प्रकृती का नियम

हैं। मैं घटिया बातों पर नहीं आना चाहता, अगर आना चाहूँ तो सबके बारे में बता सकता हूँ कि ये कैसे है? ( गोर)

**श्रीमी चन्द्रावती:** जनाब इनके परिवार के लोगो ने कानून अपने हाथ में ले रखा है। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। \* \* \*

**श्री अध्यक्ष:** यह रिकार्ड न किया जाए।

**चौधरी औम प्रकाश:** स्पीकर साहब, मैंने दो तीन काल अटैन्शन मांगे थे। उनमें से एक झज्जर जिला, रोहतक में पीने के पानी के बारे में था जिसके बारे में आपने कह दिया कि गवर्नमेंट के कमेंटस मांगे हुए हैं। एक दूसरा झज्जर भाहर में सीवरेज के बारे में रॉंगफूल और इललीगल बिल्डिंग के बारे में था....  
.....।

**श्री अध्यक्ष:** यह मैंने डिस-अलाउ कर दिया है।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने इस बात का बुरा माना कि हमने टेलीग्राम क्यों पढा। स्पीकर साहब, जिस बात को हम ठीक समझते हैं उसी को ही आपके नोटिस में लाते हैं। हमारे पास बहुत से टेलिग्राम आते हैं लेकिन जो ठीक हो, उसी को आपके नोटिस में लाते हैं। यहां पर और भी मंत्री हैं और उनके भाई और रिश्तेदार हैं, उनके बारे में हमें कोई कभी टेलीग्राम रिसीव नहीं हुआ। अगर हम कोई बेजा बात कहे तो हमने अपनी तरफ से कही हो तो बताएं। बाकी मंत्री यहां पर एक



नही बल्कि 25 की कतार बैठी है, इनके किसी भाई, लडके या रि तेदार के खिलाफ हमारे पास कोई बात नहीं आती। इन्ही के भाई के खिलाफ आती है इसका क्या कारण है? ये कहते हैं कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन इन को मौका दे दें ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। स्पीकर साहब, आप आज ही इनको यह मौका दे दें ताकि इनके सामने जिसकी बोलने की हिम्मत हो वह बोल सके।

**चौधरी भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, इनका तो एक ही प्रोग्राम है, टैलीग्राम्ज़ दिलवाने का। जब ये बात करते हैं तो यही कहते हैं कि इनके परिवार ने ज्यादाती कर दी। कम से कम इन्सान को थोडा पिछै झांक कर भी देखाना चाहिए। मुझे अपने परिवार पर पूरा फख है। कोई भी कह दे कि मेरे परिवार का पोलिटिक्स में दखल है तो मैं सजा भूगतने के लिए तैयार हूँ। \* \* \* आप जैसा मेरा परिवार नहीं है। आपके बेटे दखल देते थे। यहां तक कि पोतों तक का भी दखल था। एक एक एम0 एल0 ए0 पोतों तक को नमस्ते करता था। जो फ़ैसला वह \* \* \* \* \* करते थे वही फ़ैसला माना जाता था। ( गोर)

**श्री अध्यक्ष:** किसी का नाम रिकार्ड पर नहीं आएगा।

**चौधरी कुलबीर सिंह मलिक:** स्पीकर साहब, पिछले दिनों उचाना के साथ लगते हुए एक गावं में, जहां भूगर मिल लग रहा है, वहां मुख्य मंत्री जी सूबे सिंह जी के लिए वोट मांग

रहे थे। वहां के लोगो से इन्होंने वायदा किया था कि भूगर मिल लगाने के लिए जिनकी जमीन ली जाएगी, उनके एक एक लडके को भूगर मिल में नौकरी देंगे। इन्होंने वहां के 15-20 लडके डेली वेजिज़ पर लगाए थे लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। क्या उनको दोबारा लगाया जाएगा?

**चौधरी भजन लाल:** सभी भूगर मिलों में टैम्परेरी तौर पर लडके लगाए थे, उन सभी को हटा दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, आप कहते हैं कि सी० एम० साहब हर बार खडे हो जाते हैं। अगर कोई हर बात में ऐलिंगे इन लगाएगा और किसी 'वायदे' का लफ़ज़ लाएगा तो वे खडे होंगे ही और उसका जवाब देंगे।

**श्री मंगल सेन:** मैंने तो आपकी रुलिंग चाही थी कि एक मैम्बर के लिए अपनी बात कहने का और कौन सा फोरम है जहां हम स्पीकर साहब की अटैन् इन इनवाइट न कर सके। हमें ये कहते हैं कि हम गलत बोलते हैं, क्या सच के अवतार तो यही हैं। ( गोर)

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बार-बार उन पर ऐलिंगे इन लगाते हैं। स्पीकर साहब, जब एक्टीविटीज ही ऐसी हो और हम फ़ैक्टस देकर बात कहना चाहे तो क्यों न कहें? इनको तो विदआउट युअर परमि इन सब कुछ कहने की इजाजत है, जो चाहें ऐलिंगे इन लगाएं। लेकिन

जब हम खडे होते है तो इनको क्यों तकलीफ होती है? स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि फ़ैक्ट्स के साथ नाम देकर, तारीखें दे कर, नोटिफिके इन नम्बर दे कर हम सबमिट करते हो और उसको भी ये बेबुनियाद चार्जिज कहे तो ठीक नही ।हम जो चार्जिज लगाते है, यदि वे बेबुनियाद है तो उस बारे में इन्कवायरी करवाने में क्या दिक्कत है? इनको ऐसा कहने से कोई फर्क नही पडता कि मैं इस्तीफा दे दूंगा यदि कोई गलत बात हो। आप ज्यूडिाियल इन्कवायरी करवा लें, सारा मामला तय हो जाएगा। आप जुडिाियल कमि इन बैठा दें चाहे लोकायुक्त बैठा दें, सारे मैम्बर्ज के खिलाफ जितनी भी बातें है, वह सारी क्लीयर हो जाएंगी। स्पीकर साहब, इनके खिलाफ जितनी ऐलीगे इन होगीं, ज्यादातियां इररेगुलैरिटीज होंगी यदि हम उनको विधान सभा के अन्दर प्वायंट नही करेंगे तो दूसरा कौन सा प्लेटफार्म हैं जहां पर हम इनकी इररेगुलेरिटीज को प्वायंट आउट करें।

मैने आपकी सेवा में एक काल अटैन् इन मो इन का नोटिस दिया था जिसमें 4 प्रैस वालो के नाम लिखे थे। जब हम ऐसी बात कहते हैं, चाहे प्रैस स्टेटमेंट के जरिए कहते हैं या हाउस में कहते है और जब वे बातें प्रैस में छपती हैं तो यह सरकार प्रैस वालो का भी गला घांटती है। स्पीकर साहब, इनके पास जनरल सैक्रेटरी, ने इनल यूनियन आफ जरनेलिस्ट (इंडिया) श्री एन0 के0 तिरखा का लैटर आया है जिसमें उन्होने लिखा है

कि सरकार हमारे प्रैस के चार आदमियों को तंग कर रही है या पुलिस से तंग करवाती है।

**Shri Mangal Sein:** If this is true then it is a very serious matter, Sir.

**श्री अध्यक्ष:** चौधरी भाम ार सिंह की बात सुन लें, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा।

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला):** स्पीकर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा और दूसरे कई मैम्बरान ने भी कहा कि हम किसी मंत्री या मैम्बर के खिलाफ नहीं कहते, मुख्य मंत्री के खिलाफ क्यों कहते हैं। स्पीकर साहब, ये खुद ही बात करते हैं और उसका जवाब खुद ही रखना चाहते हैं। स्पीकर साहब, आपोजी ान के साथियों का यह डैलिब्रेटली परिप्लांड वाइल्ड एलीगे ांज इन्सीनिवे ांज, कंजेक्चर्ज और सरमाइजिज लगाने का काम था और एक ऐसी माहौल पैदा करने का प्रयत्न इन्होंने किया। इन्होंने सोचा कि इतना किचड फैंको उसमें से सारा नहीं उतरेगा तो कुछ न कुछ लगा रह जाएगा इसलिए इन्होंने मुख्य मंत्री जी पर इन बातों का अटैक किया। मेरे अपोजी ान के भाईयों का यह ख्याल है कि इस तरह की बातें कह कर मुख्य मंत्री और मंत्रियों को डिवाइड करना चाहते हैं। यह उनकी गलतफहमी है। इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। यदि वे चीफ मिनिस्टर को अटैक कर रहे हैं तो उसमें पूरी गवर्नमेंट शामिल है। सारी रुलिंग पार्टी मुख्य मंत्री जी के साथ है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ( गोर)

\* \* \* \* \*

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैर कोई बात रिकार्ड न कि जाए।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। \* \* \* \* ( गोर)

श्री अध्यक्ष: यह भी रिकार्ड न कि जाए।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, पार्लियमेंटरी अफैयर्ज मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमे वाइल्ड ऐलिंगे इन लगाते की आदत है। It is absolutely wrong. We always speak on facts and truth, nothing but truth. In a democratic set up, it is a duty of a Member.

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, आपकी बात आ गई है। अब आप बैठिए। सम्पत सिंह जी इस सम्बन्ध में आपका अटैन् इन मो इन नं: 16 था। I have disallowed this on the following grounds:-

(1) That the matter is not of urgent nature.

(2) That there is no resentment among the journalists in Haryana or the public.

(3) That there is no danger to the freedom of the Press as alleged.

### वाक आउट

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, अगर आप इस काल अटैन्शन को एडमिट नहीं करते और आप यह समझते हैं कि प्रैस को कोई खतरा नहीं है तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(विलेज पालडी और राजुपूर, पी0 एस फारुखनगर जिला गुडगांव पर एक गैंग द्वारा अटैक किये जाने सम्बन्धी)

**श्री अध्यक्ष:** आनरेबल मैम्बरज, मुझे श्री राम विलास भार्मा, एम0 एल0 ए0 की ओर से विलेज पालडी और राजुपूर, पी0 एस फारुखनगर जिला गुडगांव पर एक गैंग द्वारा अटैक किये जाने के बारे में काल अटैन्शन नोटिस मिला है, मैं इसे एडमिट करता हूँ। श्री राम विलास भार्मा अपना नोटिस पढ़ दें। अगर मिनिस्टर साहब इसका जवाब आज देना चाहे तो दें।

**श्री राम बिलास भार्मा:** इस महान सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और लोकहित के मुद्दे पर दिलाना चाहते हैं कि

20-0-85 को गांव पालडी (फारुखनगर) के पास गुडगांव जिले में रात्रि में एक गिरोह ने पूरे गांव पर हमला किया। इसमें कई औरतें और बच्चे घायल हो गए। इस के बाद 23-2-85 को पालडी के नजदीक राजुपूर गांव में थाना फारुखनगर में इसी गिरोह ने फिर रात्रि को हमला किया वहां पर कई कारतूस चले। लगभग पांच घंटे घेराबंदी के बाद गांव वालों की मुकाबले से यह गिरोह वापस हुआ। 27-2-85 को इसी तरह छिलर गांव को घेर लिया। 6-3-85 को सायं 05:30 बजे गांव राजुपुर को फिर इसी गिरोह ने घेर लिया। वहां पर गांलियां चली। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारे इलाके में दह आत फैली हुई है। लोग आतंकित हैं। सरकार इस पर कार्यवाही करे तथा इस सदन को उससे अवगत करवाए।

स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह काल अटैन्डान्स देने के बाद, उसी एरिया में एक गांव है जोड सांप, उस गांव में भी दो आदमियों को मार दिया गया है। इस कारण से उस एरिया में लोगों के अन्दर आतंक और दह आत फैली हुई है। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि उस एरिया के लोगों को आतंक से दूर करने के लिए सरकार सदन के अन्दर अपनी नीति स्पष्ट करे।

**वक्तव्य**

**मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी**

**मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):** अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विधायक ने मान्य सदन का ध्यान जिला गुडगांव में डकैती के कुछ घटनाओं की ओर दिलाया है, उस घटना के तथ्य, जो 20/21-2-85 को ग्राम पलडी थाना फारुखनगर जिला गुडगांव में हुई, इस प्रकार है कि डाकुओं का एक गैंग जिसमें 9 अपराधी शामिल थे, रात करीब 12:30 बजे ग्राम पलडी में धर्म सिंह पुत्र चन्द्र सिंह अहीर के घर के समीप आये। श्री चन्द्र सिंह जो अपनी बैठक में सोया हुआ था, जाग गया और उसने भागे किया। डाकुओं ने उस पर गोली चलाई और जबरदस्ती उसके घर में घुस गये। उन्होंने उसकी (चन्द्र सिंह) की पत्नी को धमकाया और उसे अलमारी की चाबियां देने के लिए कहा। जयपाल पुत्र चन्द्र सिंह डाकुओं के साथ गुथमगुथा हो गया परन्तु जख्मी हो गया।

डाकू सोने के आभूषण तथा 3500 रु की नकदी ले गए। श्री चन्द्र सिंह जो गोली लगने से जख्मी हो गया था, मर गया। डाकू मारु सिंह पुत्र हर सहाये, मंगल पुत्र राम सरूप, परभाती पुत्र नत्थू, अहीर और राम सिंह पुत्र मुन् पी, सतपाल पुत्र मनफूल, मनोहर पुत्र राम नारायण, सुखपाल पुत्र सुल्तान सिंह, राजेन्द्र पुत्र श्री राम, रोहता सिंह पुत्र देवी सहाय और राम कुमार पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत के घरों में भी घुसे। कुल मिलाकर 6 आदमी और 2 औरतें जख्मी हुए जिन में से 4 आदमी बन्दूक की गोलियों से जख्मी हुए जबकि 2 आदमी और 2 औरतों को मामूली



चोटें आईं। उन्हें हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। यह कहना गलत है कि 20 घर लूटे गये।

यह कहना भी गलत है कि दिनांक 23-2-85 को गैंग ने ग्राम पालडी के नजदीक ग्राम राजूपुर पर भी आक्रमण किया। यह सच है कि उस रात को गोली चली। भय के कारण ग्रामवासियों ने गोलियों चलाई जबकि मध्यरात्रि में उन्होंने एक वाहन को अपने ग्राम की ओर आते देखा। अनुसन्धान से पता चला है कि यह ग त डियूटी पर पुलिस जीप थी जिसे गलती से डाकुओ का वाहन समझ कर गोलियां चलाई गई थी। उस रात किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

दिनांक 27-2-85 को ग्राम छिलर नारनौल में कोई भी डकैती व लूट की घटना नहीं हुई।

दिनांक 6-3-85 की ग्राम राजूपुर घटना के बारे, जांच से पाया गया है कि कुछ ठिकारी जीप में उस ग्राम में आये, कुछ पक्षियों को मारा और उन्हें लेकर चले गये। किसी भी डकैती व लूट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली जैसा कि आरोप लगाया गया है। प्रभावी क्षेत्रों में पुलिस ग त तेज कर दी गई है। जैसा आरोप लगाया गया है वैसा वहां कोई भय व आतंक नहीं है। भोश अपराधियों को पकडने के लिए तेजी से अनुसन्धान किया जा रहा है। उपरोक्त उठाये हुए कदमों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की कोई भी आव यक बात नहीं रह गई है।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि पुलिस के साथ मुठभेड हुई है, राव गणे पी लाल थाना प्रबंधक भी इसमें जख्मी हुआ और कई लोग मारे गए हैं। फिर ये कहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं सरकार के हित की ही बात कर रहा हूँ। वहाँ पूरे इलाके में गोलियाँ चली हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि छिलर ग्राम में कोई गोली नहीं चली और यह ग्राम नारनौल जिले में आता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ग्राम छिलर भी थाना फारुखनगर के अधीन ही आता है। इसको आप देख लें। वहाँ के लोगों में काफी दहशत फैली हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दहशत को खत्म करने के लिए कोई कम्पिटेंट आफिसर लगाएंगे ताकि लोगों में अमन-चैन कायम हो सके?

**श्री अध्यक्ष:** इस बारे में इन्होंने बता दिया है कि प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गति तैज कर दी गई है। इसके अलावा, छिलर ग्राम की घटना के बारे में बताया है कि वहाँ पर डकैती या लूट की कोई घटना नहीं हुई।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि छिलर ग्राम नारनौल जिले में नहीं आता। यह गांव जिला गुडगांव में ही पडता है। वहाँ पर थाना अध्यक्ष श्री गणे पी लाल जख्मी हुए हैं। ग्राम छिलर के अन्दर भी डाकुओं के साथ मुठ-भेड हुई है। मैं चाहता हूँ कि सरकार वहाँ लोगों में फैली दहशत को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाए।

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बता दिया है कि उस इलाके में पुलिस की गति तेज कर दी है। इनको मुबारक बाद देनी चाहिए कि उस पुरे गैंग को हमारी पुलिस ने पकड़ लिया है। यह गैंग यु० पी० मथुरा-आगरा साइड की है। इस गिरोह के 12 सदस्य थे। जिसमें से 8 डाकू पकड़ लिए गए हैं। 4 डाकू अभी पकड़ने भोश हैं। जो डाकू पकड़े गए हैं इनमें से 6यू० पी० के और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। जो 2 डाकू हरियाणा के रहने वाले हैं, यही उस गैंग को सी० आई० डी० देते थे कि कहां कहां पर डाका डालना है। जो 4 डाकू पकड़ने भोश रहते हैं, उनको भी हमारी फोर्स जल्दी ही पकड़ लेगी। मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन डाकुओं को पकड़ लिया। हमारी पुलिस की कोशिश रहती है कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना न घटे।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** आपने जो पहला सवाल पूछा है, मुझे तो वह भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो सवाल आपने पूछा है, उसका जवाब तो पहले ही मुख्य मंत्री जी ने दे दिया था।

**श्री राम बिलास भार्मा:** स्पीकर साहब, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इस डाके के अन्दर मेवात एरिया के किसी सरपंच का नाम भी शामिल है?

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, इस गिरोह में इस गिरोह में सरदार मलखान सिंह है। इसके भाई लखन सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैंने बताया है कि 12 आदमी इस डाके में शामिल थे।

**श्री अध्यक्ष:** ये पूछ रहे हैं कि क्या मेवात एरिया के किसी गांव का सरंपच भी गिरोह में शामिल है या नहीं?

**चौधरी भजन लाल:** स्पीकर साहब, हरियाणा के दो व्यक्ति इस गिरोह में शामिल है। एक जनोला गांव का सुरे कुमार और दूसरा चुगाना गांव का महावीर है।

### अध्यक्ष द्वारा घोशणा

पंजाब युनिवर्सिटी सैनिट के लिए चुनाव स्थगित करने सम्बन्धी

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला):** स्पीकर साहब, पंजाब युनिवर्सिटी की सैनेट में हरियाणा सभा के सदस्यों द्वारा 2 आर्डिनरी फैलोज़ का कल चुनाव होना है और जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके मुताबिक 11:00 बजे से 3:00 बजे के बीच में मतदान होगा। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि कल बजट पे होना है और उसके पचास मिनट्स में खत्म हो जाएगा। कल दोपहर के बाद तकरीबन एक घण्टा बजट पे होने में लगेगा जिसका मतलब यह है कि 11:00 बजे के बीच से खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैम्बर साहेबान यहां से

जाना चाहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम की बजाये इन आर्डनरी फैलोज़ का चुनाव परसों करा लिया जाये ताकि मैम्बर साहेबान अपना मतदान ठीक प्रकार से कर सके। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** सुरजेवाला साहब ने सुझाव दिया है कि पंजाब युनिवर्सिटी को सैनेट के लिए असैम्बली के मैम्बरो द्वारा आर्डनरी फैलोज़ के लिए जो चुनाव होता है, वह कल की बजाये परसों करा लिया जाए क्योंकि कल बजट पे 1 होने के बाद मैम्बर साहेबान जाना चाहेंगे।

**आवाजें:** ठीक है जी, यह चुनाव परसों करा लिया जाये।

**श्री अध्यक्ष:** अच्छी बात है, यह चुनाव परसों करा लिया जाये।

### दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल, 1985

**श्री अध्यक्ष:** अब फाइनेंस मिनिस्टर, हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 1) बिल, 1985 को एन्ट्रोडयूस करने और कन्सीडर करने का मो ान मूव करेंगे।

**Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta):** Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1985

Sir, I beg also to move-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken in to consideration at once.

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken in to consideration at once.

**डा० भीम सिंह दहिया (रोहट):** स्पीकर साहब, इस सदन के सामने जो एप्रोप्रिएशन बिल आया है, मैं इसके विरोध में बोलना चाहता हूँ। इस बिल के जरिए जो एकसैस पैसा खर्च हो गया है, वह मांगा गया है। सबसे पहले मैं इस बिल की डिमांड नं 2 जो पी० डब्लू० डी० की है, पर बोलना चाहूंगा। स्पीकर साहब, वहां का सब-डिविजन जो पंचकुला और चण्डीगढ़ का है वह अपने कैबिनेट के लोगों की देखभाल करता है। इस सब-डिविजन के अन्दर काफी गडबड है और इस गडबड की वजह से यह काफी बदनाम और नटोरिय हो चुका है। स्पीकर साहब, इस सब-डिविजन के बारे में अखबारों में भी किस्से आते रहते हैं। कल ही एक अखबार में खबर थी कि वहां के एक कर्मचारी ने 6 हजार रु के चैक को 60 हजार रु का बनवा कर पैसे निकलवा लिए हैं। यहां पर एक एस० डी० ओ० साहब है जो सरकारी काम के साथ साथ कान्ट्रैक्ट का और बिजनेस का काम करते हैं। यह एस० डी० ओ० बैलेंस 1 लाख रु के करीब दिखाते हैं लेकिन जब वैस्ट की चैकिंग करते हैं तो एक पैसा भी नहीं मिलता। इस प्रकार यहां पर गलत पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के डिवीजन या सब-डिवीजन है जिन में इस किस्म के कर्मचारी हैं उनके उपर चेक होनी चाहिए। ये हेराफेरी करके पैसा इधर-उधर करते रहते हैं। जो हर साल एकसैस एक्सपेंडीचर होता

है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान नहीं है। सरकार ने आज तक इस तरह की कोई चैकिंग नहीं की। स्पीकर साहब, हम पी० ए० सी० की मीटिंग में भी इस तरह के पैसे देखते हैं जिनमें हर डिपार्टमेंट में और वि. शेर कर पी० डब्लू० डी० में काफी पैसा एकसैस खर्च किया जाता है। स्पीकर साहब, यह जो एकसैस स्पेंडिंग की जाती है, यह गलत बजेटिंग का नमूना है। जो लोग पैसा खर्च करने वाले हैं, उनको पता है कि पैसा तो हाउस से पास करवा ही लेना है क्योंकि इनकी मजोरिटी है, मैजोरिटी के बेसिस पर पास हो ही जाना है। अब मैं डिमांड नं० 3, जो होम के बारे में है, थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स पर बोलते हुए भी मैंने कहा था कि कई करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स बढ़ानी है। हमें यह समझ नहीं आता कि हरियाणा बनने के बाद कई गुणा पुलिस फोर्स क्यों बढ़ गई। एक लिहाज से ठीक ही बढ़ी है क्योंकि पुलिस का काम बहुत बढ़ गया है। पहले पुलिस को लॉ एण्ड आर्डर ही देखना होता था लेकिन अब कई किस्म के काम करने पड़ते हैं। चाहे पंचायत समितियों के इलैक्शन हो, चाहे बाई-इलैक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट के जनरल इलैक्शन हो, चाहे विधान सभा के इलैक्शन हो इन में पुलिस का पुरा इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिनों, स्पीकर साहब, आपने सुना होगा, पंचायत के कुछ मैम्बरज को पुलिस उठा कर ले गई थी। उनकी मार पीट की गई क्योंकि ये चाहते थे कि किसी खास कैंडिडेट को वोटें दी जायें और उसको ब्लाक समिति का चेयरमैन बनाया जाए। स्पीकर

साहब, इससे मैं यही समझा हूँ कि जब तक कांग्रेस की मैजोरिटी न हो जाए, तब तक ब्लाक में इलैक्ट्रिक इन नहीं होंगे। इस में चाहे थानेदार का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे डी० एस० पी० को इस्तेमाल करना पड़े, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यही है कि इनकी मैजोरिटी होनी चाहिए। यह सारा काम पुलिस से करवाया जाता है। अपोजि इन के लोगों को काबू करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपोजि इन के लोग इनके गडबड घोटाले को प्रकाश में न ला सकें। पुलिस के द्वारा टैरर किएट किया जात है। सरकार के किसी नेता ने आना हो और भाषण देना हो तो उस जलसे में आदमी इकट्ठे करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लोग पुलिस द्वारा जबरदस्ती न आएँ जो गांव के लम्बरदार या सरपंच को पकड़ कर ऐसा माहौल किएट किया जाता है जिससे लोग डरें। इसके अलावा, पुलिस से और भी कई खतरनाक काम लिए जाते हैं। पानीपत में पिछले दिनों बड़ी गडबड हुई। एक खास कम्युनिटी के लोगों को मारा गया। इस में पुलिस का हाथ था। पुलिस के लोग प्लेन क्लोथज में गडबड करवाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल पुलिस का यह काम क्यों हो गया। सरकार को प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह देखेंगे कि हरियाणा में जो काम होंगे, वे कायदे कानून के हिसाब से नहीं होंगे। इस हिसाब से होंगे जिस में देखा जाएगा कि फलां काम किस आदमी का है। अगर कांग्रेस पार्टी का नेता होगा या उसका रिश्तेदार होगा तो सब कुछ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कुछ



नहीं होगा। स्पीकर साहब, मैं परसों टोहाना गया था। वहाँ एक बंसल सिनेमा है। बंसल सिनेमा वाले का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसने लोकदल का झंडा लगा रखा था। इलैव इन के दौरान 5 तारीख की रात को उस सिनेमा को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। (व्यवधान) मैं वहाँ देख कर आया हूँ। वहाँ एक पब्लिक जलसा था। हमारी पब्लिक लाईफ है हमें जाना पड़ता है। मैंने उस सिनेमा को खुद देखा है। 5 तारीख की रात को कुछ लोगो ने, जो कांग्रेस पार्टी के थे, उस सिनेमा पर हमला कर दिया। इन्होंने नया नया इलैव इन जीता था, भाराब पी रखी थी और न े में थे। इन लोगो ने सिनेमा को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिनेमा के विंडो पैनज़ और लाईट समै ा कर दी। सिनेमा वाले डर कर स्ट्रंग रूम में घुस गए लेकिन इन लोगों ने उन पर बरछो के साथ हमला किया। जहाँ ऐसा वातावरण हो, वहाँ इन्साफ की क्या उम्मीद हो सकती है। जहाँ वोट देने का हक न हो, जहाँ यह भी हक नहीं कि अपनी पार्टी का झंडा लगा लें, वहाँ डेमोकसी कैसे जिंदा रह सकती है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के झण्डे का ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी के लोग इस झण्डे को घरों पर नहीं लगाते, दुकानों और फ़ैक्ट्रियों पर लगाते हैं ताकि लोग वहाँ आने से डरें। सरकार ने सारा वातावरण खराब कर रखा है। हरियाणा में किसी भी कायदे कानून का पालन कोई आफिसर नहीं करता।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं0 5 पर बोलना चाहता हूँ जो स्टेट एक्सार्ज के बारे में है। इस डिमांड के नीचे एक

आईटम है जि के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि स्टेट में एक और डिस्टिलरी हरियाणा में लगेगी। आज हरियाणा में सरकार भाराब को जितना बढ़ावा दे रही है, इतना भायद हरियाणा बनने के बाद कभी भी बढ़ावा नहीं मिला। यह तो कोई जरूरी नहीं कि डिस्टिलरी की ही फैक्ट्री लगनी है और कई अच्छी चीजें हैं जिनकी फैक्ट्रीज लगाई जा सकती है। बी० एच० ई० एल० यूनिट यूनियन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कंसर्न है, इसका प्लांट क्यों नहीं हरियाणा में लगाया जाता? और भी कई बड़े बड़े उद्योग हैं वे लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनको डिस्टिलरी ही मिलती है। एक सिस्टम इन्होंने ठेके और इन करने का बना रखा है। इस सिस्टम के द्वारा ये ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। हर साल ठेका नीलाम होता है और हर साल इसमें 40 प्रसेंट की बढ़ोतरी होती है। बाद में ठेकेदार चाहे कुछ भी मिलावट करे, लेकिन अगर पिछले साल ठेका 5 लाख में गया तो इस साल 7 लाख में देते हैं। अगर 5 लाख का ठेका 7 लाख में देंगे तो जाहिर है कि ठेकेदार को हेराफेरी करनी पड़ेगी, तभी वह कमायेगा। इससे लोगों की सेहत खराब होगी। इस तरह अडल्ट्रे इन से हूच ट्रेजडी होती है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि साल भर में कितनी बोतले बिकती हैं और उनसे कितना मुनाफा हो सकता है। आपके पास अमला है, आप चाहे तो सारी फिगर्ज इकट्ठी कर सकते हैं। हिसाब किताब लगाने से जो जायज मुनाफा है वह ठेकेदार को छोड़ दिया जाए लेकिन इस तरह से पांच-पांच सात-सात लाख में और इन करना ठीक नहीं है। ठेके की और इन एक तरह से

गैम्बलिंग है। लोगों के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि एक बार सरकार को औकान में ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दो, फिर बाद में जो कुछ मर्जी आये, करते रहेंगे। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लोगों को इस जहमत से छुड़ा दिया जाए, यह बड़ी गलत बात है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** अब आपका समय हो गया है।

**डा० भीम सिंह दहिया:** ठीक है जी, मैं बैठ जाता हूँ। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

**श्री फतेह चन्द विज (पानीपत):** स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिएशन (नं 1) बिल, 1985 हाउस के सामने है और उस पर डिस्कशन हो रही है। मैं सरकार का ध्यान खास तौर पर फाईनैस मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि यह ऐप्रोप्रिएशन किस कदर मिसऐप्रोप्रिएशन हो रहा है या होगा। मैं कुछ प्वायंट्स आपके सामने रखूंगा पानीपत के जी० टी० रोड से जब यू० पी० की रोड भुरु होती है उस रोड को उंचा करने के लिए दो अढाई महीने पहले मिटटी पडनी भुरु हुई थी। उसमें कहीं पर तीन फुट, कहीं पर दो फुट और कहीं पर एक फुट मिटटी पडनी है। लेकिन पिछले एक महीने से काम बन्द पडा है। उस रोड से यू० पी० और हरियाणा का ट्रैफिक, ट्रक और बसें आदि सैंकडों की तादात में रोजाना आता जाता है। जब कभी कोई ट्रक या बस वहां से गुजरती है तो आंधी की तरह मिटटी उड कर दुकानों के अन्दर

दाखिल होती है। जब महकमे से पूछा गया कि यह काम बन्द क्यों हो गया है तो बताया गया कि ठेकेदार से कोई झगडा है। स्पीकर साहब, चौधरी कटार सिंह जी भी अपने हलके में जाने के लिए वहीं से गुजरते हैं। मैंने जब इसके बारे में इनसे पूछा तो कहने लगे कि वाकई दिक्कत वाली बात हैं। स्पीकर साहब, अगर एक बारि 1 हो गई तो सारा ट्रफिक रुक जाएगा। आगे छानबीन करने पर पता यह लगा कि जब टैन्डर मांगे गए थे तो उसमें यह कंडीशन लगा दी गई थी कि मिटटी 14 किलोमीटर दूर से आएगी। पता नहीं किस गर्ज से यह लिख दिया गया। मिटटी जितने फुट डलवाई जानी थी वह बात इसमें लिखी जाती। ठेकेदार ने टैन्डर तो दे दिया लेकिन उस कहीं दो तीन किलोमीटर की दूरी पर मिटटी मिल गई और वह उसे डाल रहा था। इस पर डिपार्टमेंट ने उससे कहा कि आप 14 किलोमीटर दूर से मिटटी क्यों नहीं ला रहे हो? इस झगडे में वह काम अब वह एसे ही पडा है। स्पीकर साहब, आप दिल्ली जाते है। आप देखै कि वहां जी0 टी0 रोड पर जितनी भी दुकाने है, उनके आगे पर्दे लगे हुए है क्योंकि सारी मिटटी अन्दर जाती है। पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर के नोटिस में भी मैं यह बात लाया हूं।

**लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह):** वह सडक बन रही है।

**श्री फतेह चन्द विज:** स्पीकर साहब, वहां बाई-पास बनाने का काम भी कई सालो से पेंडिंग पडा है। वैसे तो उसे

सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है लेकिन प्रदे 1 सरकार द्वारा सारा पैसा खर्च होता है और प्रदे 1 सरकार ही उसे बनवाती है। जनता सरकार के टाईम में वह बाई-पास मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। हाउस में यह कहा भी गया था कि वह जरूर बनेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो पांच छः मील तक वह इलाका आबाद हो गया है। जमीन भी बडी उपजाऊ है। पहले उसे बनाने के लिए तीन करोड रुपये का ऐस्टिमेट था लेकिन अब वह 10 करोड रुपये से भी नहीं बन सकता। इसके बारे में मैंने पिछले सै 1ान में भी एक सुझाव दिया था और उस अब मैं फिर देता हूँ। भाहरों के अन्दर आज देखने में आ रहा है कि जमीन न मिलने के कारण 20-20 मंजिली ईमारतें बननी भुरु हो गई है ताकि अधिक से अधिक परिवार थोडी सी जगह पर रह सके। आप भी वहां पर जमीन एक्वायर न करे बल्कि यह जो पहला जी0 टी0 रोड है, इसी पर फलाई ओवर बना दें। दूसरे मुल्को के अन्दर आपकी कई टीमें जाती हैं और आफिसर्ज जाते हैं। उन्होने कई जगह देखा होगा कि वहां 4-4, 5-5 किलोमीटर लम्बे फलाई ओवर बने हुए हैं। मैंने सी0 एम0 साहब को भी इसका हवाला दिया था। सी0 एम0 साहब अमेरिका में जहां आपरे 1ान करवाने गए थे, उसी हस्पताल के पास 7 किलोमीटर लम्बा फलाई ओवर बना हुआ है। अगर उसी तरह के फलाई ओवर बनाने का काम ये अपने प्रदे 1 में भी भुरु कर दें तो एक तो इन्हे जमीन एक्वायर नहीं करनी पडेगी दूसरे 8 करोड रुपये का काम तीन चार करोड रुपये में हो जाएगा। यह तजुर्बा अपनी स्टेट में पानीपत से

भारु किया जाना चाहिए। वहां म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर फलाई ओवर बना दिया जाए। इन्होंने पिछले सै। न में यह ए योरें। दी थी कि ये सैन्ट्रल गवर्नमेंट को इ बारे में लिखेंगे। पता नहीं इन्होंने कहां कहां लिखा है और उस पर क्या विचार हो रहा है?

स्पीकर साहब, हुडडा की जमीन के मुताबिक कल यहां बात आई थी। इन्होंने जिस वक्त जीमन ली तो गरीब आदमियों को 9-10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से पैसे दिए। कई लोग पैसे लेकर घर बैठ गए। वे अपील नहीं कर सके क्योंकि गरीब थे। जिन लोगो ने अपील की उन्हें तिगुने और चौगुने पैसे मिले हैं। कई केस अभी कोर्ट में पैडिंग हैं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भी इस सिलसिले में कम्प्लेंट गई थी। उन्होंने एक तो कानून में तरमीम की है और दूसरे स्टेटस को लिखा है कि अगर किसी जगह एक प्लॉट की कीमत तीस चालीस रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दी गई हो तो डायरेक्टर को चाहिए कि वह अपने लैवल पर ही बाकी पैसा दे दे ताकि लोग मुकदमेबाजी से बचें। तो स्पीकर साहब, मेरी आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना है कि उन गरीबों को भी पैसा दिया जाना चाहिए जो मजबूरी के कारण कोर्ट में नहीं जा सके थे।

स्पीकर साहब, इंडस्ट्री के मुताल्लिक आज भी यहां काफी बात हुई है। कहने को तो ये यहां तक कह देते हैं कि देहात के अन्दर काफी रुरल इंडस्ट्रीज़ लगी है लेकिन वहां देखने से पता लगता है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज़ को ताले लगे हुए हैं।

उसका कारण यह है कि जो गरीब लोग देहात के अन्दर इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, उनका माल फरोख्त के लिए अच्छी तरह से प्रबंध नहीं किया जाता। माल न बिकने की वजह से वे न तो नया रा-मैटीरियल खरीद सकते हैं और न ही बैंको की कि त दे सकते हैं जिसने उन्होंने रुपया लिया होता है। इसलिए वे ताला लगा कर भागे हुए हैं। आगे आगे वे होते हैं और पीछे पीछे बैंक वाले होते हैं। स्पीकर साहब, जब तक सरकार उनका माल बेचने का अच्छा प्रबंध नहीं करेगी, तब तक यह फिगर देने से कि किलोई हलके में 295 इंडस्ट्रीज़ लगी है, कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में यह बात भी लाना चाहता हूं कि जिस किसी इंडस्ट्री वाले ने 25 हजार रुपया लोन लेने के लिए ऐप्लाइ किया हुआ है, उसे चार पांच हजार रुपया बैंक में या दलाल को दिए बिना लोन नहीं मिला। जो कोई भी लोन लेकर गया है, वह 25 हजार रु की बजाय 20-21 हजार रुपया लेकर गया है। बाकी केस अभी पैडिंग पड़े हैं। मैंने पिछले साल सैन्टर के फाईनेंस मिनीस्टर श्री प्रणव मुखर्जी जी को एक लैटर लिखा था। उनका जवाब मेरे पास आया हुआ है। उन्होंने लिखा था कि हमारे पास भी इस तरह की ि कायतें आई हैं और हम बैंकस की मिटिंग बुला रहे हैं। स्पीकर साहब, यहां जो फिगर दी जाती है कि 8 हजार लोगों को लोन दे दिया या 10 हजार लोगों को लोन दे दिया, ये गलत दी जाती हैं। इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दें। जिनके केस आपने रिकमेंड करके भेजे हैं, उनको कम से कम रुपया जरूर दिलाएं। जो बैंक

लोन नहीं देते उनके खिलाफ ऐव इन लेने के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा जाना चाहिए।

ट्रांसपोर्ट के मुताल्लिक भी यहां काफी जिक्र हुआ। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि पहले वक्त में जब राजे महाराजे होते थे, सौ या दो सौ साल पहले, तो वे रात को भेश बदल कर देखा करते थे कि प्रशासन कैसे चल रहा है। सी० एम० साहब और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब चूंकि इस समय यहां नहीं बैठे हैं, इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि वे भेश बदल कर एक ट्रक के अन्दर अम्बाला से बैठ जाएं। माल भी उस ट्रक में उतना ही लोड है जितना होना चाहिए। माल की ऊंचाई भी उतनी है जितनी होनी चाहिए। आप अगली सीट पर अपना आदमी बैठा दिजिए और देखें कि ट्रक वाला कितने रुपये दे कर अपने निश्चित स्थान पर पहुंचता है। इस बारे में मैंने पिछले बार भी कहा था कि सौ मील के सफर में गरीब आदमी को कितने रुपये दे कर पहुंचना पड़ता है।

यहां पर यह कहा गया कि पांच फलाइंग स्काड और बना दिये गये हैं जो चैकिंग करेंगे। यह तो वही बात हो गई जैसे कोई नौकर दूध पिलाता हो, वह पहले आधा दूध पी जाता है और फिर पानी मिला देता है। उसमें से आधा फिर पी गया और पानी मिला दिया। इस तरह से चौथे हिस्से का दूध रह गया सो आपने जो ये फलाइंग स्काड बनाये हैं, उनसे तो ज्यादा करण इन बढ़ती जा रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहंगा कि दिन की



रो रानी में और रात के अंधेरे में ट्रक वालो को लूटा जा रहा है। सौ मील के सफर में जब इतने पैसे देने पडते है तो जहां वे हजार मील का सफर तय करते है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते है वहां आप अन्दाजा लगायें कि उन्हे इस तरह कितनी नाजायज पेमेंट करनी पडती होगी। इस तरह से रि वत का पैसा इकटठा किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके जरिए सरकार को सुझाव दूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

**सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी):** स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिए रान बिल (नं0 1) 1985 जो सदन में पे र है मैं उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। यह पैसा अब खर्च हो चुका है, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। मैं अपोजी रान के भाईयों से दरखास्त करुंगा कि यह बिल पास कर देना चाहिए, फिजूल में हाउस का टाईम क्यो खराब कर रहे हैं?

स्पीकर साहब, मैं मांग नम्बर दो के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हरियाणा में लॉ एण्ड आर्डर की हालत और सारे प्रदे रों से काफी अच्छी है। अगर हरियाणा से ज्यादा अच्छी लॉ एण्ड आर्डर की पोजी रान किसी प्रदे र में हो तो अपोजी रान के साथी बता दें। साथ में प्रदे र के डाके मारे गये कितनी ही गडबड हुई लेकिन हमारे यहां फिर भी भांती रही। यह कह देना कि यहां पर हालात ठीक नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ तो काम नहीं चलता बराबर का सूबा चाहे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यू0 पी0

हो, इन सब से अच्छे हालात हरियाणा में है। कभी कभी ये हवाला देते हैं कि यहां पर बूथ कैपचरिंग की जाती है। यह बात अलग है। अम्बाला में 24 दिसम्बर को लोक सभा के इलैक्ट्रान हुए अम्बाला में सात सौ के करीब बूथ थे। एक बूथ की भी कैपचरिंग नहीं हुई। अपोजी इन के भाई 1 लाख 77 हजार वोटों से हार गए। ये असल बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। इन्हें हार को हार और जीत को जीत समझना चाहिए। यह कहना कि बूथ कैपचरिंग कर ली हमने उनके वोट अपने डिब्बों में डाल लिए गलत बात है। अगर हम ऐसी करते तो आन्ध्र प्रदेश में या उसके बराबर के सूबे में अपोजी इन की जीत कैसे होती? वहां पर जनता पार्टी का राज हो गया। यह तो मानी हुई बात है कि आप को लोगों की राय को नमस्कार कहना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि हार को हार और जीत को जीत मानना चाहिए। लोक सभा के इलैक्ट्रान में इनकी हार हुई और अभी तीन विधान सभा के बाई इलैक्ट्रान में भी हार हुई। जब यहां हरियाणा में इनकी बात नहीं चली तो ये हिमाचल में गये। पहले बी० जे० पी० की 28 सीटें थी इस बार ये 28 से 7 ही ले पाए और जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, उसे हरा कर चुपके से आ गए। इन्होंने वहां पर यह कहा कि एक रुपये किलो आटा देंगे और दो रुपये किलो चावल देंगे। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, लोक सभा में कुल तीन सीटें डी० एम० के० पी० को और दो सीटें बी० जे० पी० को मिली हैं। ये 508 में से मिली है, यह एक प्रसैंट भी नहीं बैठती। जनता ने इन्साफ दिया है।

एक्साइज एण्ड टैक्स डिवीजन के बारे में एक तजवीज देना चाहता हूँ। जितने टैक्स कम होंगे उतनी ही आमदनी ज्यादा बढ़ेगी। भारत सरकार ने इनकम टैक्स में जो रियायत दी है, उसका नतीजा अगले साल पता लगेगा। भारत सरकार की आमदनी बढ़ेगी। हर एक आदमी हमसूस करेगा कि चोरी कम हुई है और इनकम टैक्स ज्यादा मिला है। इसलिए अगर सेल्फ टैक्स कम करेंगे तो हरियाणा सरकार को आमदनी ज्यादा होगी।

डिमांड नम्बर आठ रोड्स और बिल्डिंग्स के बारे में है। हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कमिटी की सड़कों की हालत बहुत खराब है। म्यूनिसिपल कमिटी के पास इतना पैसा नहीं है कि वे उन्हें ठीक करा सकें। उनसे सड़कों की मैनटेनेंस भी नहीं होती। अम्बाला भाहर और कैंट की सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। अगर 15 मिनट बारिश हो जाए तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से तजवीज दूंगा कि पी0 डबल्यू0 डी0 वाले सड़कें बनवा दें ताकि वह दस पन्द्रह साल तक ठीक तरह से रह सकें और उनकी मैनटेनेंस म्यूनिसिपल कमिटी करवाती रहे। अम्बाला टाउन में टोटल 15-20 किलोमीटर की सड़कें होंगी। इन पर कोई लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं आता। इनकी हालत ऐसी है कि अगर कोई आदमी साइकिल पर चलना चाहे तो साइकिल पर भी नहीं चल सकता। इस आने वाले बजट में सड़कों के लिए ज्यादा पैसा रखें ताकि लोगों को कुछ सुविधा मिल सके।

दूसरी बात में हस्पतालो के विशय में भी अर्ज करना चाहता हूं। अस्पतालो के लिए नैट रुपया थोडा रखा गया है, वह ज्यादा रखा जाए। पी० डबल्यू० डी० ने अम्बाला कैन्ट में सडक का साढे तीन मील का टुकडा बनाया है। यह नया ही बनाया है। इसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूं। वह सडक ऐसी है जहां पर सिविल हस्पताल है, डी० ए० वी० स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे पढते है, सनातन धर्म कालेज है जहां 1800 बच्चे हैं। उस सडक पर बडी भीड रहती है इसलिए उस सडक को चौडा किया जाए। जब तक इस सडक को चौडा नही किया जायेगा। तब तक वहां एक्सीडेन्ट्स होते रहेंगे। वह हस्पताल 50 बैड का है, उसमें ज्यादा केसिज़ एक्सीडेन्ट्स के ही आते हैं। अगर इस सडक को चौडा कर दिया जाए तो हादसे नही होंगे। फोरलेन कर दिया जाये तो और भी ज्यादा अच्छा होगा जो हस्पताल केवल 50 बैड का हो और इतने ज्यादा एक्सीडेन्ट्स हो तो मरीज कहां जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, यह हस्पताल सन् 1901 में बना था। उस टाइम से ही पचास बैडज का है। इस हस्पताल के बारे में कई बार वायदा किया गया है कि इसे सौ बैडज का बना दिया जाएगा। भायद अब 75 बैडज का प्रोविजन किया है। वहां पर डेढ लाख की आबादी है। इस हस्पताल के आस पास के एरिया में श्री निर्मल सिंह, श्री फूलचन्द मुलाना और मेरा हलका आता है। तीनों हलको की काफी आबादी है और इन तीनों को यही हस्पताल फीड करता है। भाहर में सौ बैडज का हस्पताल है लेकिन हमारे यहां पचास का ही है। यह सौ साल पुराना हस्पताल है। इस को जल्दी से जल्दी दोबार

बनाया जाये। जब कोई काम भुरु होगा तभी वह मुकम्मल होगा। यहां पर बहुत बडी बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। जमीन काफी पडी हुई है। एक कमरा बनाने से ही 25 बैडज लग जाते है। थोडे से खर्चे से उस काम को किया जा सकता है। उसी रास्ते पर ब्लाइंड इंस्टीच्यूट है और उसी के उपर एस0 डी0 कालेज है। इसके अलावा दूसरी ओर भी बहुत सी संस्थाएं हैं। उस के ऊपर इतनी घटनाएं रोज होती है जिनका कोई हिसाब नहीं है। अगर उसे साढे तीन किलोमीटर के टुकडे को फोर लेन कर दिया जाए तो एक्सीडेंट्स सिर्फ एक परसैन्ट ही रह जाएंगे। डिमांड नं0 9 एजुके ान की है। तालीम के लिए अम्बाला कौन्ट में टोटल 12 सरकारी स्कूल है। इनमें से 8 तो प्राइमरी है, तीन मिडल स्कूल है, और एक हाई स्कूल है। यहां पर एक भी सरकारी कालेज न ही लडको का और न ही लडकियों का है। सो ाल और धार्मिक संस्थाएं ही वहां पर कालेज वगैरह चला रही है। यह तो इन संस्थाओं की मेहरबानी है जो बच्चो को िाक्षा दे रही है। यह बात सरकार को माननी चाहिए कि इनकी वजह से मदद हो रही है वरना इतनी बडी आबादी में 12 स्कूल बहुत थोडे हैं। मेरी मांग यह है कि वहां पर लडकियों का एक सरकारी कालेज अव य होना चाहिए।

**एक आवाज:** मैडिकल कालेज की मांग भी कर लो।

**सेठ राम दास धमीजा:** उसके लिए तो खर्च बहुत आता है। हां मै यह मांग करता हूं कि अगर सरकार वहां पर प्राइवेट

मैडिकल कालेज खोलने की इजाजत दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। इसके चलाने पर 5 करोड़ रुपये साल का खर्चा आता है। अगर सरकार इस को चलाने की इजाजत दे दे तो अम्बाला के लोग यह काम कर सकते हैं। मांग नम्बर 23 जो ट्रांसपोर्ट के बारे में है, मैं अब इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अम्बाला कैंट का बस स्टैण्ड उस समय बना था जब पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एकट्ठे हुआ करते थे। वह बस स्टैण्ड सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त का बना हुआ है। आज भी वह उतना ही है, हालांकि आबादी पहले से मुकाबले में 4-5 गुणा ज्यादा बढ़ गयी है। उस बस स्टैण्ड को बढ़ाने के लिए एक हाईपावर्ड कमेटी बनी थी और एक फैसला हुआ था।.....

**चौधरी हरिचन्द हुड्डा:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। धमीजा साहब जो डिमांड रख रहे हैं वह तो प्रोप्रो नेटली मांगेंगे। यह एप्रोप्रिएट बिल पर बहस हो रही है। इस पर डिस-प्रोप्रो नेटली अगर वह डिमांड करेंगे तो ठीक नहीं है। जब बजट आएगा, उसमें किस इलाके के लिए क्या प्रोवीजन है, वह ठीक है या नहीं है, उस वक्त देखने वाली बात है। ( और एवं व्यवधान)

**सेठ राम दास धमीजा:** मैं बिल्कुल रैलैवन्ट बोल रहा हूँ। सरकार ने जो डिमांड पे की है, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ और आइन्दा के लिए तजबीज दे रहा हूँ। यह मेरी तजबीज है कि बस स्टैण्ड के बिल्कुल पीछे 6.1 एकड़ जमीन पडी है जो सरकार की ही है। सरकार ने इस बात को मान भी लिया था कि जल्दी

ही बस स्टैण्ड बना देगी। अगर आने वाली सांतवी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में ही इसके बनाने के लिए प्रोविजन रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे हलके में एक घडवा नाला है। उसमें जब फलड का पानी आ जाए तो सारे भाहर में बडा भारी नुकसान होता है। उसको ठीक करने के लिए केवल सात आठ लाख रुपये का खर्चा होना है। उस नाले के पहले से चार मुहं हैं। फिर उसके तीन मुह है, फिर दो मुहं है और फिर एक मुहं है। उसमें चार हकुमतें इन्वालवड हैं। एक तो मिल्ट्री आती है, दूसरी म्यूनिसिपैलिटी आती है, तीसरे रेलवे बोर्ड आता है और चौथे एम0 ई0 एस0 आ जाता है। मेरा कहना यह है कि इस नाले को सुधारने के लिए कोई न कोई बन्दोबस्त जल्दी ही किया जाना चाहिए। (घंटी) डिप्टी कमी नर साहब, इतना कहते हुए मैं एक से लेकर 25 डिमांड तक रखे गये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**ठाकुर बहादुर सिंह (दडवां कलां):** मान्यवर डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो यह एप्रोप्रिए टन बिल हरियाणा सरकार की तरफ से यहां पर पे ा हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। सरकार ने एक से लेकर 25 तक जितनी भी डिमान्डज रखी हैं, हकीकत तो यह है कि इसमें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रदे ा की बहतरी के लिए, तरक्की के लिए, और हिफाजत के लिए जो यह डिमान्डज रखी गई हैं, यह जरुरी है। आपको पता है कि हरएक काम के लिए पैसे की जरुरत

होती है। हमारे भाई इसकी निंदा भी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ डिमांडज भी रखते हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, मेरी कांसचुएंसी में यह नहीं हो रहा है, वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, वहां पर डकैती हो गयी। हर तरह की बातें यहां पर इस सदन में हमारे भाई करते हैं। जहां पर यह बात आती है कि किसी मद में कुछ ज्यादा खर्च हो गया तो उसके लिए हाउस एप्रुवल देता है। जब वह राशि मांगी जाती है तो यह विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। सड़कों की मरम्मत या वाइंडिंग होनी चाहिए। प्रदेश की बेहतरी के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। अगर किसी मद में मंजूर हुआ से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो उसके लिए जब डिमांड पेन होती है तो हमारे यह भाई विरोध करते हैं। बड़ी ही अजीब बात है। एक तरफ तो कृदरती आपात की वजह से, हमारे वह सिस्टम यानि पास किए हुए पैसे कम पड जाते हैं, और जरूरत और पैसे की पडती है। फालतू पैसा खर्च हो जाता है। दूसरी तरफ एक भाई यहां यह कहते हैं कि फलां सड़क क्यों नहीं मरम्मत हुई। कोई अगर सड़क मरम्मत कर दी जाती तो ये कहते कि इतना पैसा कहां खर्च हो गया। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हमने तरक्की करनी है, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बरकरार रखनी है, तो हमें पैसा खर्च करना पडेगा। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर की बात है हम बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसी एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से, जैसे अभी मुख्य मंत्री जी ने ब्यान दिया था कि एक डकैती की वारदात



हरियाणा में हुई थी, उसको बहुत लम्बा चौड़ा फैलाया गया। उन डकैतों को हमने बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया। यह हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिसिएन्सी की निशानी है। जिस एफिसिएन्सी से इस किस्म की बुराईयां दूर करनी हो या फौरी तौर पर कार्रवाई करने वाले पकड़े जा सकते हों, उस के ऊपर अगर कुछ पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी चीज है। हर हरियाणा वासी यही चाहता है कि हमारे यहां पर इस किस्म के कार्रवाई न हो। होम डिपार्टमेंट की इसमें बात आती है। इसके लिए हमारी पुलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है। उसकी बेहतरी के लिए जितना भी बजट का हिस्सा खर्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि अगर उससे भी कुछ ज्यादा खर्च कर दिया जाता तो यह उनका हक था। आज हमें इस बात की जरूरत है कि हमें वो फोर्स चाहिए जो हमें भ्रान्ति से रहने का मौका दें। उस फोर्स को ज्यादा से ज्यादा हिमायत देनी चाहिए। बिल्डिंग एण्ड रोड्स की बात आगे आती है। हमारे हरियाणा में इस तरह से सड़कें बननी चाहिए कि जो बीच के टुकड़े छोड़ दिए गए थे वे पुरे होने चाहिए। आज कोई भी गांव दूसरे गांव से जुड़ा हुआ नहीं है। एकदम से सूरज की भुआओं की तरफ से सड़कें फेला दी गयी हैं। आज भी इस बात की जरूरत है कि इनको मिलाया जाए। आज यह कहते हैं कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया गया और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हमारे यहां सड़कें बनायी जानी चाहिए। मैं तो इसमें एक और बात एड करना चाहता हूँ। हमारी जो सड़कों की भुआएं फैली हैं, एक भाहर से किसी जगह

तक जाने के लिए इनको मिलाया जाए। 15 किलोमीटर की सड़क तो बना दी गयी है लेकिन उसके साथ ही कुछ डिस्टैन्स पर जो 4 किलोमीटर की दूसरी सड़क चल रही है, उसको जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह प्रोपोज करूंगा कि इस तरह की सड़कें हैं उनको जोड़ने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए ताकि उस प्वायंट पर वापिस न आना पड़े। इसलिए भी इन सड़कों को जोड़ना जरूरी है कि इससे पेट्रोल का खर्चा कम होगा, डीजल का खर्चा कम होगा। जनता को ज्यादा किराया अदा करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर सरकार इन सड़कों को जोड़ने पर विचार करे तो अच्छा रहेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारा प्रदेश मुख्य कृषि प्रधान है और इस मद में जो पैसा खर्च किया गया है मेरे विचार से वह कम है। डिप्टी स्पीकर साहब, कुदरती आपत्तियों के मुकाबले वह पैसा बहुत कम है। इसमें और पैसा खर्च करना चाहिए था। हम सब चाहे इधर बैठे हुए मैम्बर्ज है, चाहे उधर साईड में बैठने वाले मैम्बर्ज है, सभी एग्रीकल्चरिस्ट हैं। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि एग्रीकल्चर के बारे में जब भी कोई डिमांड हो तो हमारी मांग यह होनी चाहिए कि उस पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, अचानक ही कुदरत का कोई अटैक हो जाता है, औलावृष्टी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़

जाता है या हवाओं का रुख बदल जाता है तो किसान का बहुत नुकसान हो जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस साल भी पानी न मिलने के कारण फसलों का काफी नुकसान हुआ। बिजली भी समय पर किसान को नहीं मिली और इस कारण वह ट्यूबवैल का पानी फसलो को नहीं दे सका। इसलिए यह जरूरी है कि जिस तरह से भाखडा नहर टूटने पर सरकार ने किसानो को सबसिडी दी, उसी तरह स`अब भी दी जानी चाहिए। किसानो की सब तरह से मदद की जानी चाहिए ताकि वे अपनी फसलो को बचा सके। एग्रीकलचरिस्ट की ज्यादा से ज्यादा मदद की जानी चाहिए। इससे प्रदे 1 की तरक्की होगी। मैं अपने अपोजी 1न के मैम्बर्ज से प्रार्थना करुंगा कि जहां भी एग्रीकल्चर की बात आए, वहां इस बात की जरूरत है कि किसान की इमदाद के लिए हम सब आवाज उठायेँ।

**श्री उपाध्यक्ष:** ठाकुर साहब, अब आपका समय खत्म हो गया। आप बैठ जाएँ।

**ठाकुर बहादुर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तो बोलने का मूड बना था और अभी आम कह रहे है कि टाईम खत्म हो गया। मेरी सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि जो डिमान्डज़ है और जिन पर हरियाणा की जनता की भलाई के लिए पैसा खर्च किया गया है, वे उनको मंजूर करें और मैं भी अपना पूरा समर्थन देता हूँ।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): डिप्टी स्पीकर साहब, कृषि सम्बन्धी डिमान्डज के बारे में ठाकुर बहादुर सिंह बोल रहे थे, मैं भी उसी सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि हमारा प्रदे 1 कृषि प्रधान दे 1 है और अगर हम कृषि को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारा प्रदे 1 तरक्की नहीं कर सकेगा। इस मद के अन्दर जो पैसा मांगा गया है उसमें यह बात आई थी कि भाखडा नहर में कट होने के कारण यह पैसा एडी 1 नल खर्च करना पडा है। प्राकृतिक प्रकोप के कारण यह रकम बांटी गई। ट्यूबवैल्ज के लिए प्रावधान किया गया या पीने के पानी का इन्तजाम किया गया, इन सब कामों के लिए यह पैसा खर्च किया गया। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि क्या ये अच्छा होता कि जहां सात-सात आठ-आठ साल से, चाहे वह भिवानी का इलाका है, चाहे महेन्द्रगढ या सिवानी का इलाका है, कहर पड रहा है और वहां के लिए आज तक सरकार ने फ़ैमिन रिलीफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, उसके लिए भी कोई प्रावधान इन डिमांड में लाते। डिप्टी स्पीकर साहब, हालात यह हैं कि आज खेतीहर मजदूर भागने के लिए मजबूर हो रहा है। क्या ही अच्छा होता अगर यह सरकार प ुओं के लिए चारे का प्रावधान करती, जिससे किसान के प ुओं की रक्षा होती। अगर यह सरकार अपने आप को किसान का हितैशी कहती है तो इसको किसान की भलाई के लिए पैसे का प्रावधान करना चाहिए था। जहां इस सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की मांग की है, वहां किसानों के लिए भी रुपया मांग सकती थी। डिप्टी स्पीकर

साहब, 1979 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक स्कीम भुरु की गई थी जिसका नाम ट्रेनिंग एण्ड विजिट था। आज हालात यह हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उस स्कीम में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको जनवरी और फरवरी की तनखाह भी नहीं दे पाया है। उनकी तनखाह क्यों नहीं दी गई है, जहां तक मुझे जानकारी है उसका कारण यही है कि डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर इस बारे में एक मीटिंग के लिए बाहर गए थे। वहां पर वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग होकर कोई एग्रीमेंट साईन होना था। इस काम के लिए दूसरी टीम का दौरा बनाया जाना है। जिससे कि दूसरे लोगों को भी बाहर घूमने का मौका मिल सके। अब दूसरी टीम जाएगी, वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा और पैसा एप्रूव होगा, तब जाकर कर्मचारियों को तनखाह मिलेगी। मेरा ख्याल है कि इस स्कीम में एक हजार या आठ सौ कर्मचारी होंगे जिनको तनखाह नहीं मिली है। 1979 में, जब यह स्कीम भुरु की थी, तब इसका नाम ट्रेनिंग एण्ड विजिट था और अब इसका नाम बदलकर नैशनल एग्रीकल्चर ऐक्सटेंशन प्रोग्राम रखा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स तक एक्साइज ड्यूटी माफ कर रखी है और राजस्थान सरकार ने सेल्ज टैक्स माफ कर रखा है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर सेल्ज टैक्स माफ करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स सस्ते होंगे तो गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, दुर्भाग्य की बात यह है कि 1982 में एक

स्प्रिंकलर सैट पर 25 प्रति गत या मैक्सिमम पन्द्रह हजार रुपए की सबसिडी मिलती थी। 1983 में उसको घटाकर चार हजार कर दिया गया था और इस साल तीन हजार कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, हालत यह है कि जो सबसिडी पहले पच्चीस परसेंट या मैक्सिमम पन्द्रह हजार थी, उसको घटाकर तीन हजार कर दिया और फिर यह सरकार कहती है कि हम किसान के हितैशी हैं। उपाध्यक्ष महोदय अब मैं स्प्रे-पम्प के बारे में कहना चाहता हूँ। ऐप्रूव्ड सोर्स से अगर एक स्प्रे पम्प खरीदा जाए तो उसकी कीमत 420.00 रुपया सरकार ने फिक्स कर रखी है। जबकि प्राइवेट सोर्स से खरीदा जाए तो केवल 250.00 रुपये में मिल जाता है। जो स्टैंडर्ड की कम्पनीज़ है, उनसे अफसरों को कमीशन नहीं मिलता और घटिया किरम की कम्पनीज़ से कमीशन मिल जाता है इसलिए उसकी कीमत ऐप्रूव कर रखी है। सरकार इन स्प्रे-पम्प पर 50 प्रसेंट सबसिडी देती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की ओर से 210.00 रुपया सबसिडी के तौर पर दिया जाता है, लेकिन इसका फायदा न किसान को हुआ और न ही सरकार को। इसी संदर्भ में, मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक अमेरिकन स्प्रे कम्पनी है, वैसे तो वह इंडियन कम्पनी ही है। **12:00 बजे** ऐसी कम्पनी जो स्टैंडर्ड की हो और आई0 एस0 आई0 मार्क की हो, इसका माल न लिया जाए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि चाहे डिजल इंजन हो, चाहे पाईप्स हो, इन सब चीजों पर सेल्ज टैक्स तुरन्त ही खत्म कर देना चाहिए जिससे किसानों को काफी राहत मिले।

इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, एसें एटिड डिसटिलरी प्राइवेट लिमिटेड, हिसार में एक फर्म है, इन्होंने पहले फॉरेन लीकर बाटलिंग का लाईसैंस ले लिया था और अब देसी भाराब की बाटलिंग का लाईसैंस भी ले लिया है। इस फर्म ने हरियाणा तक ही अपना दायरा नहीं रखा बल्कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से भी मिलकर यह आर्डर करवा दिये कि वे भी इसी फर्म का ही परमिट काटें लेकिन असलियत यह है कि एक भी ठेकेदार इस कम्पनी का माल लेने को तैयार नहीं है। इस फर्म को पोलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है। चाहे इस फर्म का माल घटिया क्यों न हो लेकिन फिर भी इसी फर्म के नाम से परमिट इतने किये जाते हैं। वहीं से माल खरीदना पडता है। इसलिए मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूँ कि कहीं इस फर्म के कारण फिर कालावाली और नरवाना जैसी ट्रेडिज दोबारा न हो जाएं, इस तरफ ध्यान दें। आप लोगो को तबाह होने से बचायें। इसी तरह की एक और इंडस्ट्री \* \* \* \* के नाम से यहां हरियाणा में चल रही हैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** इस इंडस्ट्री का नाम नहीं आएगा क्योंकि यह रैलेवेंट नहीं है।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि पांच करोड रुपये की राशि उस फर्म को दी गयी है ( और एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** आर्य साहब, आप कितने अच्छे सुझाव दे रहे थे। आप एप्रोप्रिए इन बिल पर ही बोलें। चाहे एप्रोप्रिए इन बिल हो चाहे कोई दूसरा सबजेक्ट हो, रुल्ज के अनुसार सब पर चर्चा की जानी चाहिए। किसी का नाम यहां नहीं आना चाहिए।

**श्री हीरा नन्द आर्य:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि रुल्ज के अन्दर अन्दर बातें कहीं जाएं और एप्रोप्रिए इन बिल पर ही कहीं जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दो और बातों का यहां पर जिक्र करूंगा। 1-11-84 को लैण्ड मोर्टगेज बैंक, आदमपुर की बिल्डिंग का हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इलाज किया था लेकिन वह बिल्डिंग बनी नहीं है। अब जो किराए का भवन लिया गया है, वह एक साधारण सा बना हुआ है, इस में कोई स्ट्रांग रुम नहीं है जोकि बैंकिंग के लिए आवश्यक है। इस में कोई प्रोविजन भी नहीं है लेकिन यह भवन तीन हजार रुपये किराए पर लिया हुआ है। दूसरा एक और कोओपरेटिव बैंक है, उसके लिए एक कमरा लिया हुआ है, जिसका 800 रुपया महीना किराया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक न्यू बैंक आफ इंडिया की एक ब्रांच आदमपुर में है, उन्होंने पहले ही उसके लिए एक मकान किराए पर लिया हुआ है जिसका वे 250 रु महीना किराया दे रहे हैं। अब उसी बिल्डिंग का किराया बढ़ा कर ढाई हजार रु कर दिया गया है क्योंकि वह भवन किसी हाई अपस के परिवार से सम्बन्ध रखता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां के ए० जी० एम० और डी० जी० एम० की पत्नियों को सरकार



ने डिसकि अनरी कोर्ट में से पंचकूला और सोनीपत में प्लाट्स दिये हुए हैं। मैनेजर द्वारा आबजेव अन करने के बावजूद भी इनके आदमियों को 60-60 हजार रुपया बैंक से दिलवाया गया है। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान)

इसके आगे, मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय का मजदूरों से बहुत बड़ा सम्बन्ध रहा है। उनके हितों के लिए उन्होंने बहुत से काम किये भी हैं। मेरे नोटिस में यह बात है कि जिन हस्पतालों की बिल्डिंग्स 1979-80 में मंजूर हो चुकी थी, जिनको बनाने का सारा खर्च भारत सरकार ने ही देना था, उन बिल्डिंगों को बनाने का काम अभी तक इस सरकार की तरफ से भुरु नहीं हुआ। यह सारा काम मजदूरों और दूसरे हरिजन परिवारों की भलाई का ही है, जिस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन अस्पतालों को जल्दी से बनाया जाना चाहिए ताकि गरीब आदमी इन हस्पतालों का लाभ उठा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज गरीबी सारे हरियाणा में है। जहां पहले 5000 लोग काम करते थे जैसे कि टी0 आई0 टी0 मिल भिवानी है, आज वहां पर केवल 500 के करीब ही मजदूर रह गये हैं। यह भी मजदूरों के साथ, गरीब लोगों के साथ अन्याय है। सरकार को इस तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो बातें और कह कर अपना स्थान लूंगा। 15 अगस्त, 1982 को मुख्य मंत्री महोदय भिवानी में गये थे और वहां पर 13 हरिजन और बैकवर्ड लोगो की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय को एक एफ़ीडैविट दिया गया था कि उनसे अधिकारियों ने हजार हजार, दो दो हजार रुपये इकट्ठे किये है। लगभग 18-20 हजार रुपये की राशि वे स्वयं ही खा पी गए है, हेराफेरी की गयी है। इसके बावजूद हमें अभी तक इस बात का पता नहीं लगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई कार्यवाही भी की है या नहीं (घण्टी)। मैं तो यही कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार का प्रदेस में बोलबाला है लेकिन यह इस प्रशासन को स्वच्छ प्रशासन का नाम देते है। इन भाब्डों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। जय हिन्द।

**श्री अजमन खां (नूह):** मोहरीतम डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा विधान सभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस चल रही है। मैं इस पर बोलने और इसकी पूरी तरह से हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस बिल पर मैं पहली बार हाउस में बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कई गलतियां भी हो जाएं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, इसको सारा हिन्दुस्तां मानता है कि हरियाणा जैसा एडमिनिस्ट्रेशन सारे देस में कही नहीं है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन कभी कभी लॉ एण्ड आर्डर की आड में कुछ अफसरान लोग

बेगुनाहों को बिना वजह तंग करते हैं, जुल्म ढाते हैं, जिसकी तरफ मैं सरकार की खास तवज्जोह दिलाना चाहता हूँ। सरकार जहाँ लॉ एण्ड आर्डर को मँटेन करने के लिए जिम्मेवार है वहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी गरीब आदमी के ऊपर बिना वजह जुल्म न ढाया जाए। इस तरह का भी कोई प्रावधान होना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं एक्सआईज़ एण्ड टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे एक मित्र ने बोलते हुए कहा था कि भाराब की जितनी बोटलें बिकें उसके हिसाब से ही लोगों से पैसे लिए जाएं और ठेके ज्यादा न उठाए जाएं। मैं यह कहूँगा कि ठेके अगर ज्यादा न छोड़े जाएंगे, तो जो बेईमानी करने वाले ठेकेदार हैं, क्या वे लोगों से थोड़े पैसे लेंगे? वे तो उतने ही कमाएंगे जितने कि उन्होंने कमाने हैं, लेकिन हरियाणा की आमदनी जरूर घट जाएगी। जैसे बापू ने कहा था कि हिन्दुस्तां में भाराब नहीं बिकनी चाहिए। वह बात तो ठीक है लेकिन भाराब को पीने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। इससे कम से कम जो पैसा मिलेगा वह गरीब लोगों की भलाई के लिए काम आएगा। इसके बाद मैं पब्लिक वर्क्स के बारे में कहना चाहता हूँ। इस महकमे पर जितना रुपया खर्च किया जाता है, अगर उस पर चैकिंग की जाए तो उसी पैसे में से और ज्यादा काम निकाल जा सकते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि जो रुपया हम दे है, उसको सही मायनो में यूटिलाइज नहीं किया जाता। बे-वक्त काम किये जाते हैं। सडको पर बरसात के दिनों में मिट्टी डाली जाती है। इसलिए

मैं गुजारि । करुंगा कि एसे अफसरान पर चैक रखा जाए। खास तौर से जहां मिट्टी डाली ही नहीं जाती और बिल तैयार कर दिए जाते है वहां ज्यादा चैक रखा जाए। इससे एक तरफ तो स्टेट को नुकसान होता है और दूसरी तरफ पब्लिक को नुकसान उठाना पडता है। उनका वक्त पर कोई काम नहीं होता क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए इस डिपार्टमेंट को जहां हम ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की हिमायत करते हैं, वहां हम यह भी चाहते है कि जिन अफसरों की आनॅस्टी डाउटफूल पाई जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाए। इससे ही भ्रष्टाचार में कमी हो सकती है। (विघ्न) जिसको आप भ्रष्टाचार कह रहे है उसमें आप लोग भी हिस्सेदार हैं। लॉ एण्ड आर्डर को खराब करने के लिए जितना भाोर आप लोगों की तरफ से दिया जात है, उसकी मिसाल नहीं है। इसके साथ साथ अगर किसी के साथ ज्यादाती हो जाती है तो उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेवार है जितनी की सरकार। आप अपना रवैया हाउस में भी और हाउस के बाहर भी बदलें। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक पब्लिक हैल्थ की बात है, मैं यह चाहूंगा कि इस पर जो रुपया खर्च हो रहा है, इससे भी ज्यादा खर्च किया जाए। मैं चाहता हूं कि खासतौर पर मेवात के अन्दर लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी जाए। पहले जमाने में तो लोग कच्चे कुएं का पानी पिया करते थे और गुजारा कर लिया करते थे लेकिन मेवात के बहुत बड़े एरिया के अन्दर पीने का पानी नहीं है। पहाड के दामन में दोनो पहाडियों के साथ साथ पीने का पानी है लेकिन बीच का एरिया खाली पडा

हैं। चौधरी देवी लाल जी ने स्कीम मंगवाई थी और प्लड का पानी कंट्रोल किया गया था। उस वक्त मैंने कहा था कि क्योंकि प्लड का पानी कंट्रोल होगा इसलिए पीने का पानी नहीं होगा। हमने कहा था कि मेवात में जो यह लंडवार नाला आता है, यह मेवात के लिए रहमत बनकर आता है, जहमत बनकर नहीं आता। उस वक्त अफसरान ने कहा था कि टैक्नीकल आदमी हम है। आज पोजी इन यह हो गई है कि तीन चार साल से बारि इन होने के कारण और पानी को कंट्रोल करने की वजह से किसी भी गांव में पानी नहीं है। इसलिए दोनो पहाडो के दामन में से एम0 आई0 टी0 सी0 के बडे बडे ट्यूबवैल्ज लगाएं जाएं। उससे यह फायदा होगा कि एक तरफ तो इरीगे इन होगी और दूसरी तरफ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। पीने का पानी सिर्फ पहाडो के दामन से ही निकाला जा सकता है। इलाके में और बहुत कम पानी है जिसके लिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। जानवरों के लिए पीने के पानी का भी फौरी तौर पर बन्दोबस्त करना बहुत जरूरी है। जानवर जो है वे उधर से हमारे इलाके में अकसर टिपट होते रहते हैं। मैं ज्यादा न कहता हुआ इतनी ही कहूंगा कि मेवात के इलाके की तरफ तवज्जोह दी जाए और मैं इस डिमांड की हिमायत करता हूँ। एजूके इन के बारे में मेरी अर्ज है कि जिस एरिया में एजूके इन के लिहाज से पीछे है, वहां ज्यादा तवज्जोह दी जाए। उसमें खास तौर पर मेवात का इलाका आता है। (धंटी) इन भाब्डों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इस खर्च को मंजूर किया जाए।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल (मुंडाल): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो एप्रोप्रिए इन बिल रखा गया है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तीन चार डिमांडज पर बोलूंगा। मेरे कुछ साथी कहेंगे कि सरकार की नुक्ताचीनी करना आपकी आदत हो गई है। हम नुक्ताचीनी के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी देंगे। मेरे लायक दोस्त राम दाम धामीजा जी, जनरल एडमिनिस्ट्रे इन पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि क्योंकि हम चुनावो में हार गए हैं इसलिए हम आउट आफ फस्ट्रे इन बोल रहे थे। डिप्टी स्पीकर साहब, ये चुनाव आउट आफ सैंटीमेंट्स हुए थे। श्रीमती गांधी के कत्ल के बाद सारे दे । में लोगो को सैंटीमेंट्स भडक गए और सरकार की विफलताओं को भूल गए और कहा कि बहुत बुरा हुआ। विपक्ष की पार्टियों में जितने भी प्रोग्राम थे, उसको लोगो ने छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी बहुमत दे दिया। (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) इसमें कोई भाक नहीं कि हरियाणा में लॉ एण्ड आर्डर बहुत बढिया है लेकिन जो घटनाएं उस कत्ल के बाद हुई, वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसके अलावा, दो तीन डिमांडज और है जिन पर मैं चर्चा करूंगा। एक रैवेन्यू की डिमांड है। हमारे माल विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी बेईमानी है कि कोई भी काम बगैर पैसे दिए नहीं होता। अब चीफ मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर कहेंगे कि आपकी तो आदत है, आपने तो नुक्ताचीनी करनी है। कोई रजिस्ट्री करवानी हो तो बगैर पैसे दिए नहीं होती। किसानो से रजिस्ट्री और इन्तकाल के लिए पांच पांच

सौ, हजार हजार रुपया लिया जाता है। इसका मैंने सबूत भी दिया है। मैंने अपने हलके में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में कह रखा है कि रजिस्टरी के लिए और इन्तकाल के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना है। किसी ने करवानी है तो हमें बताए, हम साथ चल कर करवाएंगे। एक बार मैं बाई चांस 15-20 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। जब मैं वापिस आया तो एक आदमी कहने लगा कि आपने कहा था कि रजिस्टरी के लिए पैसे नहीं देने लेकिन मैंने रजिस्टरी करवानी थी इसलिए मुझे पांच सौ रुपये देने पड़े। मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ फलां तारीख को आएँ और मैं आपके पैसे वापिस दिलवाने के लिए कोर्त्ता करूंगा। मैंने अपना एक साथी उस तहसीलदार के पास भेजा जिसने रजिस्टरी की थी। उसको कहा गया कि भले मानस, आपको तनखाह मिलती है, किसानो को क्यों लूटते हो। उसने एक महीने के बाद पांच सौ रुपए वापिस भेज दिए क्योंकि वह हालात को समझ गया था। स्पीकर साहब, मैं आपके नोटस में लाना चाहता हूँ बल्कि मेरी सजैतान है कि मुख्य मंत्री जी और मिनिस्टर साहेबान इंस्ट्रक्शन भेजें कि रजिस्टरी के वक्त कोई पैसा नहीं लिया जाए। जहां तक हमार ताल्लुक है, हम चाहेंगे कि हमारी एन्टरटेनमेंट कोई न करे और हमारा जो खर्चा है वह हम खुद करें। अगर सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन चली जाए तो ये तहसीलदार या दूसरे अफसर इस खराबी को छोड़ देंगे। आज ये लोग रैड कास का बहाना लगा कर लोगों से पैसे ले लेते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस

तरह की इंस्ट्रक्शन जरूर भेजी जाए जिससे कि किसान लुटने से बच जाएं।

इसके अलावा स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 8 रोड्ज के बारे में है। इस बारे में मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहूंगा कि भिवानी जिले में कुछ ऐसी सडके हैं, कुछ ऐसे गांव हैं, जिनको एक दूसरे गांव में आने जाने के लिए 20-20 किलामीटर घुम कर आना जाना पडता है। मैंने इस बारे में पिछले सेशन में भी जिक्र किया था लेकिन अभी तक उन लिंक रोड्ज को नहीं बनाया गया। ये रोड्ज जरूर बनानी चाहिए ताकि उन गांवों को 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना जाना न पड़े। यदि उन गांवों के लिए छोटे छोटे सडके के टुकडे बना दिए जाएं तो लोगों को काफी सहूलियत हो सकती है। उन हलको से अपोजीशन के एम0 एल0 ए0 हैं इसलिए सरकार उन सडको को नहीं बना सकती, भायद यह सरकार की मजबूरी है, लेकिन उन गांवों के किसानों की कठिनाईयों की तरफ तो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। इसलिए जहां जहां टिब्बे हैं वहां पर तो कम से कम सरकार को सडक बना देनी चाहिए। यदि सडक बना दी जाए तो सरकार फेल नहीं होती। उन गांवों के लोगों ने सरकार को कई बार लिख करके दिया है कि हमारे यहां सडकों के छोटे छोटे टुकडे बनाने बाकी रहते हैं, उनको बना दिया जाए। मेरे हलके में एक गांव है, यदि मंत्री जी उस गांव का नाम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। उस गांव के किसानों को दूसरे गांव में आने जाने के लिए 15 किलोमीटर



का चक्कर काट कर आना-जाना पडता है। यदि उनके लिए सीधा लिंक रोड बना दिया जाए तो उस गांव के लोगों का एक रुपया 20 पैसे किराया भी बच सकता है। लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती, ये सिर्फ यह कह देते हैं कि हम नुकताचीनी कर रहे हैं। यह सरकार हमारी जायज बातों को भी नहीं मानती। स्पीकर साहब, चाहे हम विपक्ष के हैं, हमारी बात माननी चाहिए। डेमोक्रेसी का यह कायदा है कि चाहे किसी भी पार्टी का राज हो, सरकार को किसानों की तकलीफों की तरफ ध्यान देना चाहिए। राज किसी भी पार्टी का आ सकता है, सरकार किसी भी पार्टी की बन सकती है। एक समय ऐसी भी आया था कि कांग्रेस पार्टी का भी लोगों ने सफाया कर दिया था। लेकिन जो अफसरान है वे सोचें कि सरकार तो आती जाती रहती है, इसलिए मंत्रियों की गलत बातों को कम से कम अफसरान न माने। यदि अपोजी उन के एम0 एल0 ए0 की कोई बात सही है तो उसको जरूर माने। इसके अलावा स्पीकर साहब, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं, इसलिए खेतीबाड़ी को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। आज देश में एग्रीकल्चर के बारे में ऐसी एटीच्यूड बन चुका है कि जिस के कारण गांवों में किसानों की हालत बहुत बुरी है। आप गांवों में जाकर देखें, किसानों को उनकी प्रोड्यूस का भाव बहुत ही कम मिलता है। आप किसानों की कोई भी प्रोड्यूस ले लें, चाहे गेहूं है, आलू है, चावल है, सरसों है, काटून है, यदि इनके दाम बढ़ेंगे तो केवल एक या दो प्रसेंट ही बढ़ेंगे लेकिन मैनुफैक्चरिंग

गुड्स के भाव 12-12, 15-15 और 20-20 प्रसेंट बढ जाते है। आप सब को यह पता है कि गावों के अन्दर किसान अपनी प्रोडूस का भाव लेने के लिए किस तरह से पिट रहा है। अगर मैं ज्यादा कहूं तो आप कहेंगे कि हम उनके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते है। जनता पार्टी के भासन के समय चौधरी चरण सिंह ने भुगरकेन के भाव के बारे में कहा था कि यदि गुड का एक्सपोर्ट किया जाए तो किसान भुगरकेन के भाव में पिटने से बच जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए जिनके कारण उनकी यह नीति गलत हो गई। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आज किसान उसकी हर प्रोडयूस के भाव में पिट रहा है वह चाहे काटन की पैदावार है चाहे सरसों की पैदावार है, चाहे तोरिए की पैदावार है और चाहे कोई भी पैदावार है, आज किसान को उसकी पैदावार का सही भाव नहीं मिल पा रहा। यदि गेहूं बाहर से मंगवाया जाएगा तो हमें बहुत महंगा पडेगा।

**श्री अध्यक्ष:** ग्रेवाल साहब, आप वाइंड अप करें।

**चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल:** स्पीकर साहब, मैं दो चार मिनट में ही खत्म कर दूंगा। स्पीकर साहब, एक बहुत बडे इकानोमिस्ट डा० मैकलोम एडीसेरियाह, सैवंथ प्लान पर बैटर टर्म्ज आफ ट्रेड फार दी फारमर्ज के बारे में बोल रहे थे। वे नई दिल्ली में सैवंटीन्थ लाल बहादुर भास्त्री मैमोरियल लैक्चर दे रहे थे। उन्होंने इन्डियन एग्रीकल्चर रीसर्च इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली में कहा कि किसानों की फसल लूटी जा रही है, उनको फसल का

कुछ भी भाव नहीं मिलता है, उनको लगातार लूटा जा रहा है और जो किसानों के नुमाइंदा है, वे ब्यूरोक्रेट्स के जाल में फंस चुके हैं। उनका दृष्टीकोण अर्बनडाइज्ड है, उनका दिमाग अर्बनडाइज्ड है इसलिए वे किसानों की तकलीफों को नहीं समझते। लिहाजा वे किसानों की फसलों का सही दाम नहीं दे पाते हैं। उस इकोनोमिस्ट ने ऐसा लैक्चर दिया है। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि वे गावों में जाकर किसानों की माली हालत को देखें, आपको सारा पता लग जाएगा। अगर आपको बहुत बड़ी मैजोरिटी मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैजोरिटी मिलने के बाद किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान न दें। आज गावों में बहुत समस्याएँ हैं। अनएम्प्लामेंट की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, डिसपैरिटी की समस्या है और आर्थिक समस्या हैं। इन समस्याओं को हल करना चाहिए। सरकार का यह फर्ज है कि वह इन समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाले। किसानों की ऐसी समस्याएं दूर होनी चाहिए।

इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं सिंचाई के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे भिवानी जिले के किसानों को नहरी पानी बहुत ही कम मिलता है और बिजली की सप्लाई भी काफी कम होती है। जिसकी वजह से भिवानी जिले में 50 प्रसेंट स्टैंडिंग फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला जी यहां हाउस में बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे भिवानी जिले में जा कर इस बात का पता लगा लें कि उस जिले में एक

महीने में केवल एक बार ही नहरों में पानी आता है। आपको यह पता है कि गेहूं की फसल 7 या 8 पानी लगने से पकती हैं। यदि गेहूं की फसल को दो या तीन बार पानी मिलेगा तो वह फसल कुछ भी नहीं हो पाएगी। आपको कोई ऐसा प्रोविजन करना चाहिए जिसके तहत किसानों के उनकी गेहूं की फसल के लिए कम से कम 7 या 8 बार पानी अवय मिल जाए। भिवानी का इलाका डैजर्ट इलाका है। यदि किसान गेहूं की फसल को जब तक 10 या 12 बार पानी ट्यूबवैल्वेजसे नहीं देंगे तो वह फसल नहीं पक सकती। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि ट्यूबवैल्वेज से गेहूं की फसल को 10 या 12 बार पानी न मिले तो उनसे बिजली के बिल न लिए जाएं और यदि नहरी पानी 8 या 9 बार नहीं मिल पाता है तो उनसे आबियाना न लिया जाए। सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि यदि ट्यूबवैल्वेज से 10 या 12 बार पानी और नहरों से 8 या 9 बार पानी गेहूं की फसल को नहीं मिलेगा तो उनसे बिजली के बिल और आबियाना नहीं लिया जाएगा। इन भावों के साथ मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का विरोध करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ।

**वित्त मंत्री (श्री सागर राम गुप्ता):** स्पीकर साहब, एप्रोप्रिएशन बिल पर हुई बहस का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन माननीय सदस्यों ने आज बहस में हिस्सा लिया है, उन्होंने अपने आपको सबजैक्ट तक ही कन्फाइन किया है। मैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देता

हूँ। मेरे अपोजी इन के काफी माननीय सदस्य बोलते हुए पहले इधर उधर की बातों में चले जाया करते थे लेकिन आज सारी बातें एप्रोप्रिए इन बिल के बारे में कहते रहे हैं। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं श्री हीरा चन्द आर्य जी की एक बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स में यह चीज क्यों नहीं लाए, वह चीज क्यों नहीं लाए और यह फ़ैसिलीटीज़ क्यों नहीं दे पाये। मैं उनके इस सुझाव से तवक्को नहीं करता हूँ। आप सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सप्लीमेंटरी डिमांडज हे, बजट नहीं। आप सभी जानते हैं कि सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस लाने का एक ही कारण होता है कि जो गुजर गया, इस साल के दौरान किन्ही कारणों की वजह से जिस पैसे का बजट में प्रावधान नहीं हो पाया था और कुछ खर्चा ज्यादा हो गया, उसको पास करवाने के लिए हम सप्लीमेंटरी डिमांडज आपके सामने लेकर आए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए नई स्कीमें, नई चीज और नए सुझाव नहीं आ सकते। लेकिन जो पैसा खर्च हो चुका है उसको पास करवाने के लिए हम आपके सामने सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस लेकर हाजिर होते हैं। कल बजट आएगा उस पर बोलते हुए आप ये सारी बातें कहें कि यह चीज और आनी चाहिए थी और यह फ़ैसिलीटीज़ होनी चाहिए थीं। आप काफी पुराने माननीय सदस्य हैं, मैं उनकी इस बात से तवक्को नहीं करता। कुछ थोड़ा सा पासिंग रिमार्क ग्रेवाल साहब ने भी किया कि पार्टियां चुनाव में जीतती रहती हैं और हारती रहती हैं। इन्होंने इस बारे में बोलते हुए जो कुमेंट्स किये थे वे ठीक नहीं

किए। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अभी पार्लियामेंट के चुनाव में और हरियाणा के तीनो उपचुनावों में अपोजी इन पार्टीज का जो हाल हुआ है, वह सब को पता है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 1977 में भी कांग्रेस पार्टी का ऐसी हाल नहीं हुआ था जो आपका हुआ है ( गोर एवं विघ्न)

**श्री हरि चन्द हुडडा:** साउथ में तो आपकी एक ही सीट आई थी (विघ्न)

**श्री सागर राम गुप्ता:** हम तो अढाई साल बाद ही वापिस आ गए। अब कहां गई जनता पार्टी। ( गोर एवं विघ्न) आप क्यों पासिंग रिमार्क करते हैं? अगर आप ऐसे रिमार्कस देंगे तो उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ( गोर एवं विघ्न) मेरे कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां तक पी० डबल्यू० डी० हरियाणा का सवाल है, वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज के दिन दूसरे प्रांतों के मुकाबले सबसे ज्यादा सडकें हमारे यहां पर बनी हुई हैं। आज के दिन 98 प्रति 100 गावों को पक्की सडको से जोड़ा हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं इन भाईयों से निवेदन करूंगा कि वे दूसरे प्रान्तों में जा कर वहां की सडको की हालत देखें कि वहां पर कितनी सडकें हैं और कैसी हैं। ( गोर एवं विघ्न) डा० साहब, आप जैसा मैम्बर भी कटाक्ष करे तो अच्छी बात नहीं है। एक पी० डबल्यू० डी० सब-डिवीजन चण्डीगढ़-पंचकूला का जिक्र यहां पर आया है। मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि यह डिवीजन जब से हरियाणा प्रान्त बना है,

उसी समय से है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन डा० दहिया साहब की यह बात ठीक है कि पीछे उस डिवीजन में एक फ़ाड का केस या एम्बजलमेंट का केस नोटिस में आया। उस डिवीजन के अन्दर किसी ने 6 हजार के चैक या ड्राफ्ट को टैम्पर विद करके 60 हजार रुपए बना लिए और वह पैसा ले लिया। यह कार्यवाही 6 फरवरी को हुई थी। ज्यों ही गवर्नमेंट के नोटिस में यह मामला आया तो गवर्नमेंट ने उसी समय ऐक्टिव न किया और जो ए० टी० औ० मि० विज वहां पर थे, उनको वहां से हटाया गया। गवर्नमेंट के नोटिस में आते ही इस केस की जांच पडताल की गई। अब एक केस धारा 420/467/468/ और 479 के तहत दर्ज किया गया है। हमारी सूचना के मुताबिक जो एस० डी० ओ० वहां पर थे उनको 14-3-85 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वे बेल पर हैं। इसके साथ ही साथ उस ए० टी० ओ० को भी निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा, पी० डबल्यू० डी० द्वारा भी अपनी कार्यवाही की जा रही है। मैं डा० साहबा को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई गफलत या देरी नहीं की। स्पीकर साहब, यहां पर एक बात यह कही गई कि हरियाणा के कुछ ऐसे स्थानों पर सड़के बनी हुई हैं जहां धूम कर लोगों को जाना पड़ता है। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि कुछ छोटे छोटे लिंक रोड्स बना दिए जाएं ताकि लोगों को धूम कर न आना पड़े और ज्यादा किराया न खर्च करना पड़े। यह सुझाव ठाकुर बहादुर सिंह का बहुत अच्छा है। मैं सरकार की तरफ से विवास दिलाना चाहता हूँ कि यह मामला सरकार के

विचाराधीन है कि ऐसे डायरेक्ट लिंक्स रोड्ज को कैसे और किस रफतार से जोड़े जाएं। आप जानते हैं और सारा हाउस भी इस बात को जानता है कि यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। ये लिंक्स 5,10 या 15 हजार रुपए में बन कर तैयार नहीं हो सकते। आज के दिन एक किलोमीटर सडक बनाने पर एक लाख रुपया खर्च आता है।

**श्री हरिचंद हुडडा:** जहां जहां गांव वाले मिट्टी डलवा दें वहां तो आप ये रोड्ज जल्दी बनवा दें?

**श्री सागर राम गुप्ता:** हम हुडडा साहब की ऑफर का फायदा उठायेंगे।

**श्री हरि चन्द हुडडा:** मैं वायदा करता हूं कि जहां जहां पर मेरे हलके में ऐसी सडके बननी है वहां वहां पर मिट्टी डलवा दूंगा।

**श्री सागर राम गुप्ता:** इस मामले में सरकार बिल्कुल जागरुक है और कोर्ि । । यह होगी कि अगले 5-7 सालों में जो ऐसे कुछ लिंक्स हैं जहां काफी दूर से घूम कर आना जाना पडता है, उनसे बचा जा सके। इन लिंक्स को सरकार जल्दी से जल्दी बनाने की कोर्ि । । करेगी। धमीजा साहब ने जिक्र किया है कि म्यूनिसिपल कमेटीज के जो रोड्ज है, उनकी बहुत खराब हालत है। इस बारे में मैंने कल भी हाउस को बताया था और आज फिर दोहराता हूं कि सरकार इस बात को मान करके चल रही है कि



बहुत से भाहरों की सडकों की हालत बहुत ही खराब है। मै सदन को बताना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल कमेटीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वे नई सडके बना सकें और पुरानी सडको की मुरम्मत अच्छी प्रकार से कर सकें। सरकार इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है कि भाहरो की जो सडके हैं उनकी मुरम्मत पी० डबल्यू० डी० द्वारा जल्दी से जल्दी करवाई जाए। आप इस बात को देखेंगे इस पर जल्दी ही कार्यवाही भुरु हो जाएगी। इसी प्रकार से अम्बाला के बारे में धमीजा साहब ने जिक किया है कि वहां पर फोर लेन सडक बननी चाहिए। इनका यह सुझाव बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी सरकार इस बात पर विचार करेगी और पी० डबल्यू० डी० निश्चित तौर पर कोई कदम उठाएगा। इसी प्रकार से अम्बाला छावनी में जो बस-स्टैण्ड बना हुआ है, वह ज्वायंट पंजाब का बना हुआ है। इनकी मांग है कि वहां पर नया बस-स्टैण्ड बनाया जाए। मै इनकी सूचना के लिए और दूसरे साथियों की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के पास पहले ही यह मामला अंडर कंसिडरेशन है कि वहां पर एक नया अच्छा सा बस-स्टैण्ड मॉडर्न टाइप का बनाया जाए। अम्बाला कैंट में नया बस-स्टैण्ड बनाने के लिए रवैन्यू डिपार्टमेंट से जमीन ट्रांसफर करवाई जा रही है। सदस्यों को जानकर इस बात की खुशी होगी कि इस बस-स्टैण्ड के निर्माण का कार्य अगले साल यानि 1985-86 में भुरु कर दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष:** आप अपने जवाब को छोटा करके जल्दी खत्म करने की कोशिश करें क्योंकि अभी एक आइटम और आनी है।

**श्री सागर राम गुप्ता:** ठीक है जी, लेकिन जो सवाल इन्होंने किए हैं उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अजमत खां जी ने एक बात कही है कि सड़को पर जो मिट्टी डाली जाती है वह वक्त-बे-वक्त डाली जाती है और उसमें हेराफेरी होती है। सरकार के नोटिस में ऐसी हेराफेरी की बात नहीं है। अगर ये ऐसी कोई बात नोटिस में लाएंगे तो निश्चित तौर पर इन्कवायरी करवायेंगे और जो अधिकारी इस मामले में लिप्त पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से डा० दहिया ने पुलिस के खर्च का जिक्र करते हुए कुछ बातें कही हैं। दरअसल इस मामले में यदि मेरी व्यक्तिगत राय पुछें तो मैं डा० साहब से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि वे भी ऐसी बातें कहें। डा० साहब को अच्छी तरह से पता है कि ज्यों ज्यों किसी देश में आबादी बढ़ती है त्यों त्यों लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब होती है। मेरे भाई बुरा न मानें तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये विरोधी पक्ष के भाई ही जनता को गलत काम करने के लिए भडकाते हैं जिससे पुलिस का खर्च बढ़ता है। स्पीकर साहब, इस डिमांड में पुलिस का ज्यादा खर्च इन्वाल्वड नहीं है। अधिकतर खर्च तो महंगाई भत्ते का है जो कर्मचारियों को दिया गया है, इसी वजह से इतना खर्चा बढ़ पाया है। दूसरी बात यह है कि हमने पुलिस फोर्स नहीं बढ़ाई। टोटल

फोर्स 23 हजार है। वर्ष 1984-85 में मामूली इन्क्रीज़ हुई है। यह इन्क्रीज़ इतनी कम है जो न होने के बराबर है, भायद दहिया साहब को यह मालूम नहीं है।

**श्री हरि चन्द हुड्डा:** ये तो यह चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसे हालात हो जाए जिससे पुलिस फोर्स की जरूरत ही न रहे।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, माननीय सदस्य को एक बात मालूम नहीं कि 450 के करीब कांस्टेबल हटाये गये थे। इनको हरियाणा सरकार ने हटाया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इन कांस्टेबल को हरियाणा सरकार को वापिस नौकरियों में लेना पडा और फ़ैसले के मुताबिक इनकी तन्खाह का एरियर भी देना पडा। पुलिस पर जो इतना खर्चा हुआ है यह उसकी वजह से हुआ है। यह बात नहीं है कि इस साल पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। लेकिन स्पीकर साहब, जब पुलिस अच्छे तरीके से काम करेगी, ला एण्ड आर्डर को मैन्टेन करेगी, चोरियों और डकैतियों की रोकथाम करेगी तो इस में कुछ खर्चा बढ़ना मुनासिब बात है। हमने पुलिस को वायरलैस सैट प्रोवाईड किये हैं, मोटर साइकल प्रोवाईड किये हैं, एम्बूलेंस गाडियां प्रोवाईड की हैं और जीपें प्रोवाईड की हैं। पुलिस को इलैक्ट्रोनिक इक्विपमेंट्स दिये गये हैं ताकि एफिं एंसी बढे, इसीलिए यह खर्चा हुआ है। स्पीकर साहब, डा0 दहिया ने कहा कि पुलिस का मिसयूज़ होता है। यह बिल्कुल गलत है। न तो जलसों में हाजिरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और न ही

पुलिटिकल पर्पज के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। यह तो उनकी भ्रान्ति है। स्पीकर साहब, चौधरी भागीराम ने एक बात कही थी, मैंने उसका ख्याल रखा है। रानियां सब—तहसील बनाने की बात कर रहे थे। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि वह स्कीम सैंकान हो गई है। स्पीकर साहब, एक और बात का जिक्र दहिया साहब ने किया था कि झंडो का बडा मिसयूज हो रहा है, इस बात से दहिया साहब को बडी तकलीफ है। मैं इन्हे बताना चाहता हूँ कि अगर 100 झंडे दिखाई देते हैं तो इन में से 95 परसैंट झंडे ट्राईक्लर के होते हैं। मेरे पास इस का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई इलाज है तो वह यही इलाज है कि वे उधर से रिजार्इन करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें। इस का यही एक इलाज है।

**डा० भीम सिंह दहिया:** स्पीकर साहब, मैंने कहा था कि बिजनैस प्रिमिसिज में जो झंडे लगाते हैं, वह न लगाए जाएं। अपने अपने घरों में लगाओ।

**श्री सागर राम गुप्ता:** अगर कोई आदमी अपने ट्रक्टर पर झंडा लगा लेता है, खेत वाला खेत में लगा लेता है तो इसका इलाज मेरे पास क्या हो सकता है?

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, वित्त मंत्री ठीक बात कह रहे हैं कि झंडे लगाये जाते हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस झंडे का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का झंडा राष्ट्रीय झंडे

से मिलता जुलता है। किसी भी देश का जो राष्ट्रीय झंडा होता है, वह किसी एक पार्टी का झंडा नहीं होता। \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

**श्री अध्यक्ष:** यह बात रिकार्ड न की जाए।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, मैंने अर्ज किया है कि इस पर हम रोक नहीं लगा सकते क्योंकि यह क्या मालूम कौन किस पार्टी में जाता है, कौन किस पार्टी का झंडा लगाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मकान पर कोई झंडा लगाता है तो हम उसको कैसे उतार सकते हैं? मैं इनको सुझाव दे चुका हूँ कि वे रिजार्डिन करके देखें, तब इधर आ सकते हैं। स्पीकर साहब, दहिया साहब ने एक बात एक्साईज डिपार्टमेंट के बारे में कही कि हरियाणा में एक डिस्टिलरी खोली जा रही है। यह डिस्टिलरी इसलिए नहीं खोली जा रही कि हरियाणा सरकार को डिस्टिलरी खोलने का कोई भौक है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां भुगरमिल्ज़ बहुत हो गई हैं। पिछले साल हरियाणा में तीन भुगरमिल्ज़ चालू की गईं। अगर प्रान्त में गन्ना ज्यादा पैदा होगा और चीनी ज्यादा बनेगी तो मोलैसिज़ की क्वालिटी देश में बढ़ेगी। यह हमारा रा-मैटीरियल है और हम चाहते हैं कि हमें अपना रा-मैटीरियल स्टेट के बाहर न भेजना पड़े और वह भी बहुत सस्ते दामों पर। हम इसका बैस्ट यूज इन दी इन्ड्रस्ट आफ द स्टेट करना चाहते हैं। हमें डिस्टिलरी खोलने का कोई भौक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग भाराब तो पीते ही नहीं जिसके लिए

डिस्टिलरी खोली जाए। डिस्टिलरी बनेगी तो हम इन भाईयों की ही सेवा करेंगे। मोलैसिस प्रदे 1 से बाहर जाए तो ठीक नहीं है।

**Mr. Speaker:** Gupta Ji, be brief please.

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, एक बात मैंने कल भी बताई थी और आज फिर बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में हूच ट्रैजडी की कोई गुंजाइ 1 नहीं है। पहले जो हूच ट्रैजडी हुई थी, इसको कारण यह था कि पहले कोटे कम थे। अब हमने कोटे बढ़ा दिये हैं। अगर कहीं इस किस्त की भांका होगी तो हम उसका इलाज कर देंगे। स्पीकर साहब, पुलिटिकल बात ले ओ कि साहब, हिसार की एक कम्पनी है जिसका नाम एसे 1 एटिड डिस्टिलरी है। इस कम्पनी को अनड्यू ऐडवांटेज दिया जा रहा है। और इस कम्पनी के मालिक चीफ मिनिस्टर साहब के रि तेदार है। ऐसी बातें कहना इनको भाभा नहीं देती। न जाने इस किस्म की बातें यें क्यों करते हैं? बिना बेसिज के बात करना हाउस में बदमग्जी पैदा करता है। स्टेटमें अलकोहल की जो रियलाइजे 1न होती है वह ठीक ढंग से होती है। जो सरप्लस अलकोहल होती है, वह लाइसेंस होल्डर्ज को दी जाती है लेकिन किसी पर थ्रस्ट अपौन नहीं करते। वे अपनी जरूरत के मुताबिक परचेज करते हैं। यह एसो 1 एटिड डिस्टिलरी रजिस्टर्ड है और डी0 जी0 टी0 डी0 इसका कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है जिस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया का कंट्रोल है। स्टेट गवर्नमेंट इस में कोई दखल नहीं दे सकती। यह बिल्कुल गलत किस्म की बात है जो इन्होन कही।

**चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल:** स्पीकर साहब, आप देहातों में जाकर देखें। वहां बोरियो में भर कर भाराब जाती है। इस तरह भाराब गावों में जा, इससे गलत बात और क्या हो सकती है?

**प्रो० सम्पत सिंह:** स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एसोसिएटेड डिस्टिलरी की बात की है और कहते हैं कि हम प्रदेश में कंट्रैक्टर्ज पर थ्रस्ट अपॉन नहीं करते। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इसी कंसर्न की पहले डिस्टिलरी थी जो बन्द हो गई थी। इसके बाद मैसर्ज ए सोसिएशन ने इसी कंसर्न नाम से एक और डिस्टिलरी भुरु की थी जिस में इंडियन मेड फारेन लीकर बनती थी। इसके बाद इन्होंने देसी भाराब का लाइसेंस ले लिया लेकिन देसी भाराब का प्रोडक्शन लाइसेंस लेने से पहले ही यह भाराब मार्केट में आ गई थीं। एक्साइज डिपार्टमेंट के आफिसर हर ठेकेदार को कहते हैं कि इस कम्पनी की रुस्तम ब्रांड है, उसी को खरीदो, हालांकि रुस्तम ब्रांड का स्तर बहुत ही घटिया है।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बात भावना नहीं देती कि इस तरीके से हमें गैर पोलिटिकल आदमियों को जान बुझकर इंवॉल्व करने की कोशिश की जाए। (विध्वन्) खैर, मैं सदन की सूचना के लिए यह बता दूँ कि हरियाणा सरकार को अपने एक्साइज डिपार्टमेंट के उपर फख है क्योंकि यह काफी अच्छे ढंग से काम कर रहा है। पिछले साल इस डिपार्टमेंट की आय 296 करोड़ रुपये की थी लेकिन जो साल

अब जा रहा है इसमें 338 करोड़ रुपये की अर्निंगज इस डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है। यहां कोई एरीयर्ज नहीं रखे जाते। 99 परसेंट वसूली साथ के साथ हो जाती है। कुछ पुराने एरीयर्ज है और कुछ मामले कोर्ट में पड़े है उनको भी जल्दी से सुलझाने की हम कोर्िंग कर रहे है। (विघ्न) स्पीकर साहब, यहां वर्ल्ड बैंक के प्रोजैक्ट का भी जिक्र आया। मैं सदन की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि यह जो प्रोजैक्ट वाला मामला है यह बहुत जल्दी ही फाइनेलाइज होने वाला है।

**प्रो० सम्पत सिंह:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, स्पीकर साहब, पिछली बार भी हाउस मे बौंडिड वेयर हाउसिंग का जिक्र आया था। उसके बारे में केसिज़ दर्ज हुए थे और कोई 15-20 करोड़ रुपए की गडबड हुई थी। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की यह जिम्मेवारी बनती है कि वे हाउस को बताएं कि उस 15-20 करोड़ रुपये की ऐम्बजलमेंट का क्या रहा? क्या उनसे कुछ पैसा लिया गया था या नहीं लिया गया। अगर यह पैसा आ जाए तो स्टेट को और आमदनी हो सकती है।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह गलत है। कोई एम्बैजलमेंट की बात नहीं है। इस तरीके से खामखाह बेबुनियाद बात करना मुनासिब नहीं है।



**प्रो० सम्पत सिंह:** पिछली बार सरकार ने यह माना था।  
(विघ्न)

**डा० मंगल सेन:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।  
(विघ्न)

**शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):** स्पीकर साहब,  
ये वैसे ही टाईम वेस्ट कर रहे हैं।(विघ्न)

**डा० मंगल सेन:** स्पीकर साहब, मैं आपको रुलिंग चाहता हूँ। इस सदन में यह बात कैटेगरीकली मानी गई थी कि कुछ बॉडिड हाउसिज ने ऐक्साइज डिपार्टमेंट से मिलकर भाराब निकलवा दी थी और ऐक्साइज की चोरी हो गई थी। अब फाईनैस मिनिस्टर साहब, जो अभी नए नए बने हैं, इस बात को गलत बता रहे हैं। If he is ignorant about it, he must have asked from his friend sitting with him. अगर उनको भी पता नहीं तो बृज मोहन सिंगला जी से पूछ लें जो ताजे ताजे सुप्रीम कोर्ट से बचकर आए हैं। (विघ्न)

**एक सदस्य:** बचकर नहीं, जीत कर आए हैं।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, मैं डा० मंगल सेन जी की सूचना के लिए बता दूँ कि हरियाणा सरकार बहुत पुरानी है, कोई नएपन की बात नहीं है। यह बात ठीक है कि कोई बॉडिड वेयर हाउस का स्कैंडल हुआ था लेकिन उसमें इवेजन 15 करोड रुपये का नहीं था बल्कि 3 करोड रुपए का था और उस

इवेजन के बारे में सरकार ने उचित कदम उठा लिए हैं। इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है।

**डा० मंगल सेन:** क्या कदम उठाए हैं?

**श्री सागर राम गुप्ता:** सरकार जो उचित समझती थी, वे कदम उठा लिए गए हैं। स्पीकर साहब, ये क्वैशन कर दें, हम जवाब दे देंगे।

**श्रीमती चन्द्रावती:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, माननीय सम्पत सिंह जी ने जो बात कही है, इस कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आफ इंडिया ने भी माना है। एक बात जिसे सरकार पहले मान चुकी है उस पर वित्त मंत्री को अवयरोपनी डालनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** जितना वे बता सकते थे उन्होंने बता दिया है। मैं उन्हें जवाब देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता।

**श्री सागर राम गुप्ता:** स्पीकर साहब, यहां यह जिक्र आया की फरीदाबाद में अभी एक झगडा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति मारा गया है। यह भी कहा गया कि बौंडिड लेबर के बारे में हरियाणा सरकार जागरुक नहीं है। यह बात बिल्कुल गलत है। मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 295 बौंडिड लेबर के बारे में जो आर्डर दिया था, उस पर सरकार ने ऐक्टिवली काम किया है। 72 आदमियों को रिलीज करवा कर री-पैट्रिएट कर दिया है। 78 के करीब आदमी अपने आप चले गए हैं। 73 के करीब आदमी ऐसे हैं

जो जाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत से लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 44 के करीब लोग ऐसे हैं जो ट्रेसेबल नहीं हैं। 28 आदमियों को हम रीपैट्रीएट करने के प्रोसैस में हैं। जहां तक फरीदाबाद वाली बात का सम्बन्ध है, वहां एक ठेकेदार और मजदूरों के बीच झगडा हुआ था। ठेकेदार ने बाहर से कुछ बाहर से कुछ आदमी बुला लिए थे और मजदूरों ने भी पथराव आदि किया। इस झगडे में एक आदमी मारा गया। सरकार इस मामले में सतर्क है। केसिज रजिस्टर करवा दिए गए हैं। दोनों तरफ के आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लॉ एण्ड आर्डर की कोई प्रोब्लम अब वहां नहीं रही है।

स्पीकर साहब, मेवात की डिवैल्पमेंट के बारे में चौधरी अजमत खां जी ने एक बात कही। कल भी मैंने जिक्र किया था और आज फिर कह देता हूं कि सरकार उसकी डिवैल्पमेंट के लिए बहुत कोशिश कर रही है। यह बात ठीक है कि पीने के पानी की बहुत जगह तकलीफ है। इस साल हमने 800 प्रोब्लम विलेजिज की पीने के पानी की तकलीफ को हल किया है। अगले दो सालों में हरियाणा की प्रोब्लम विलेजिज में चल रही ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीमो को पूरा कर देंगे। इन भाब्दो के साथ, स्पीकर साहब, मैं हाउस से गुजारि करुंगा कि इस ऐप्रोप्रिएटन बिल को पास किया जाए।

**Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

*The motion was carried.*

**श्री अध्यक्ष:** अब सदन बिल पर क्लोज वाई क्लोज विचार करेगा।

**श्री हीरा चन्द आर्य (लोहारु):** अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने 138, 52 करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट हाउस के सामने पे आ किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह सारे साल के बजट का एक तिहाई से भी ज्यादा बनता है। अगर कोई ऐमरजेंसी आ जाए, कोई नैचुरल कैलेमिटीज आ जाएं तब तो कोई 5-10 परसेंट सप्लीमेंटरी बजट की बात समझ में आ सकती है लेकिन बिना किसी ऐमरजेंसी के, बिना किसी नैचुरल कैलेमिटीज के यदि इतना बड़ा सप्लीमेंटरी बजट पे आ किया जाए तो बात जंचती नहीं। स्पीकर साहब, यह बड़ा अन-प्लैंड बजट है। अध्यक्ष महोदय, किसी दे आ और प्रदे आ के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए भुरु साल में कोई योजना नहीं थी, कोई स्कीम नहीं थी कि कितने स्कूल अपग्रेड करने है लेकिन जब इनकी तबीयत की तो 93 स्कूल अपग्रेड कर दिए। उसके लिए 13,56,590 रुपए रखे गए है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का स्तर अगर उठाना है तो बकायदा प्लानिंग करनी पडेगी लेकिन ये बडे अनप्लैंड-वे से काम कर रहे हैं। एजुकेशन बोर्ड कई साल से इनसे ठीक प्रकारसे

कॉन्सिडरिड नही हो पाया है। अगर ये कोई अच्छे काम करते तो हमें खुशी होती।

**श्री अध्यक्ष:** अब आप कृपया बैठिए।

प्रश्न है—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**कलाज 3**

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न है—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**भाङ्गूल**

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न है—

कि भाङ्गूल बिल का भाङ्गूल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**कलाज 1**

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैकिटिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि अनैकिटिंग फार्मूला बिल का अनैकिटिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**Mr. Speaker:** Now the Minister will move that the Bill be passé

**Finance Minister (Sh. Sagar Ram Gupta):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरकारी संकल्प

सविधान (तिरपनवां सं गोधन) विधेयक 1984 की रेटिफिके ान  
सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब औफि ायल  
रैजोल्यू ान मूव करेंगे।

**Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):** Sir, I beg to move-

That this House ratifies the amendment to the Consitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Consitution (Fifty-third Amendment) Bill, 1984 as passed by the two House of Parliament.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, हमें इसके सम्बन्ध में कोई कागज तो मिले नहीं। न हमारे पास अमेंडिड बिल है और न ही ओरिजनल बिल है। हम कैसे डिसक ान में पार्टीसिपेट करेंगे?

श्री अध्यक्ष: जो डाक्यूमेंटस टेबल आफ दी हाउस पर ले लिए हैं, वही सब मैम्बरान को भेजे थे, दो कापियां भेजी थी।

13:00 बजे

**आवाजें:** हमें एक भी कापी नहीं मिली।

**श्री अध्यक्ष:** अगर हुडडा साहब को मिल गई है तो आपको भी मिलनी चाहिए थी।

**चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला:** मिस-प्लेस हो गई होंगी।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, गलती भी हो सकती है। लेकिन जब हुडडा साहब को पहुंची है तो आपको भी पहुंचनी चाहिए थी।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, हुडडा साहब को पहुंची होगी लेकिन हमें नहीं पहुंची।

**चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर साहब, विधान सभा ने 31 मार्च, 1980 को एक रैज्योलू इन पास किया है और भारत सरकार से यह दरखास्त की है कि उनकी अपनी असेम्बली में और लोक सभा में भी, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के रिजर्व इन के लिए उपलब्ध किया जाये। दोनों जगहों पर रिजर्व इन के लिए दरखास्त की है। इस प्रस्ताव का समर्थन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में किया है। इन्होंने यह प्रपोज़ किया है कि आर्टिकल 330 में संशोधन इसलिए किए जाने का प्रस्ताव है कि इसमें लोक सभा की सीटों में रिजर्व इन के लिए प्रोविजन है। आर्टिकल 332 का संशोधन इसलिए किए जाने का प्रस्ताव है कि नागालैंड और मेघालय की विधान सभाओं में ऐसे ही आरक्षण के



लिए उपलब्ध हो जाए। स्पीकर साहब, यह जो प्रस्ताव आया है, इसका कांस्टीच्यु इनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है और हमारी विधान सभा में रैटीफिके इन के लिए आया है। इस प्रस्ताव को लाने का कारण यह है कि उनकी स्टेटस में दूसरे लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उनकी ओरिजनल पापुले इन गिनती में इतनी कम न हो जाए कि वे असेम्बली में अपने तौर पर आ ही न सकें। इसलिए उनकी आकांक्षाओं को, इगोज को, कस्टमज को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि उनकी पूरी तरह से हिफाजत हो सके। इन बातों को पूरा करने के लिए यह अमेंडमेंट ले कर आये है। इस अमेंडमेंट को जो प्रैजन्ट लोक सभा पर कोई असर नहीं पड़ेगा यानि उनकी सीट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद इलैक् इन कमी इन डीलिटिमे इन ओर डेजिने इन आफ कांस्टच्युएन्सी करेगा। जब अगला इलैक् इन लोक सभा और विधान सभा का होगा उसमें ट्राइबलज के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। इसका हिन्दुस्तान की किसी दूसरी स्टेट के साथ कोई सरोकार नहीं है और न दूसरो पर इसका कोई असर है। इस का बहुत ही अच्छा मुद्दा है और इस में ट्राइबलज लोगो की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रिजर्वे इन का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं हाउस सर दरखास्त करुंगा कि इस सं गोधन का अनुसमर्थन करें।

**Mr. Speaker:** Motion moved-

That this House ratifies the amendment to the Consitution of India falling within the purview of the proviso

to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Consitution (Fifty-third Amendment) Bill, 1984 as passed by the two House of Parliament.

**श्री मंगल सेन (रोहतक):** स्पीकर साहब, पार्लियामेंट अफेयर्ज मिनिस्टर ने कुछ भूमिका के साथ संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन का प्रस्ताव रखा है। मेरे कुछ मित्र यहां हाउस में कह रहे थे कि इस अमैडमेंट के बारे में हमें पूरा मैटीरियल नहीं मिला।

**श्री अध्यक्ष:** सब को लैटर भेजे हैं।

**श्री मंगल सेन:** स्पीकर साहब, राज्य सभा की डिबेट इसके साथ मिली है लेकिन लोक सभा की नहीं मिली। अच्छा तो यही होता कि लोक सभा की डिबेट भी भेज देते। यह तो वही बात हुई कि छोटे मियां सो छोटे मियां, बड़े मियां सो सुभान अल्ला। सन् 1980 में मेघालय की विधान सभा ने यह पास किया। आज पांच साल होने वाले हैं। हम तो सोचते थे कि हमारे यहां ही जल्दी से काम होता है, वहां तो सैन्टर में हम से भी जल्दी काम होता है। पांच साल तक कुम्भकर्ण की तरह सोये रहे और अब ये अमेडिंग बिल ले कर आए है। ये बड़ा मासूम चेहरा बना कर कह रहे थे कि उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए, उनके कस्टम, इगोज खत्म न हो जायें, उन्हें कायम रखने के लिए भारत सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। बड़ी अच्छी बात है परम्परागत प्रथाओं को जीवित रखना चाहिए। आदिवासियों,

वनवासियों की आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने बड़ी दूरी की सोच कर आर्टिकल 330 और 332 में रिजर्वेड आन् आफ सीट्स फार रिजर्वेड कास्टस एण्ड रिजर्वेड ट्राइब्ज रखी हैं। इन्होंने चार पांच प्रदेशों को गिनवाया है जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि हैं। स्पीकर साहब, हरियाणा में भी बसने वाले जो पसमान्दा लोग हैं, जन-जातियां हैं जो निर्धनता की रेखा के नीचे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासिज के नाम से एक कार्पोरेट बैंक बना दी। उसका एक चेयरमैन बना दिया जिसको आने जाने का खर्चा और भत्ता आदि भी दिया जाता है। \* \* \* \* \*

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब ने जो यह बात कही है यह रिकार्ड में की जाये।

**श्री मंगल सेन:** स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांस्टीच्यूटिव की अब 53वीं अमेंडमेंट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आप खानदानी वकील हैं क्योंकि आपके पिता जी भी वकील रहे हैं। खुद भी वकील हो और आज जिस कुर्सी पर आसीन हो, वह आपकी काबलियत का नमूना है।

**श्री अध्यक्ष:** यही नहीं मेरे दादा जी भी वकील रहे हैं।

**श्री मंगल सेन:** यही से तो इन्सपीरेटिव लेने वाली बात है। आपसे इन्सपीरेटिव लेकर हम भी एल० एल० बी० कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांस्टीच्यूटिव की जो 53 वीं बार

अमैडमेंट होने जा रही है, इससे हमारा दुनिया में मजाक उड रहा है। इस संविधान की कुछ धाराएं 26 नवम्बर, 1949 को लागू हो गयी थीं, मुझे इस बात का इसलिए पता है क्योंकि मैं भी भारत के उच्चतम न्यायालय में एक बार प्रार्थी यानी पैटीनर डिफेंस बन कर गया था। मेरी सिटीजनशिप को आपकी चेयर पर विराजने वाली एक बहिन श्रीमती भान्नो देवी ने एक दफा चैलेंज किया था। इसलिए मुझे पता है कि कुछ धाराएं 26 नवम्बर, 1949 को लागू हो गयी थी जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात है। बाकी धाराएं और पूरा संविधान 26 जनवरी, 1950 को ही लागू हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान को लागू हुए 35 साल हो गये हैं और अब 53वीं बार इसमें अमैडमेंट हो रही है। दुनिया के दूसरे देशों के कांस्टीच्यूशन में, मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा अमैडमेंटस नहीं हुई हैं जितनी हमारे कांस्टीच्यूशन में हुई हैं। स्टेटसमैन इयर बुक ट्वेंटी-फर्स्ट एडीशन में यह दिया हुआ है कि यू0 एस0 ए0 का कांस्टीच्यूशन 1776 में लागू हुआ था। 209 साल हो गये हैं लेकिन उसमें 20 से भी कम बार अमैडमेंट हुई हैं। यहां पर आए दिन अमैडमेंट होती रहती है। ठीक है, एण्टी डिफैक्टिव इन बिल द्वारा जो अमैडमेंट की गयी है, वह तो होनी चाहिए थी। उसके ऊपर एक इन भी होना चाहिए था। हरियाणा के मुख्य मंत्री पर सबसे पहले एक इन होना चाहिए था और सारी कैबिनेट पर एक इन होना चाहिए था। लेकिन बहुत अफसोस है कि उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। (व्यवधान एवं भाोर)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): आपके ऊपर अमल हो तो रहा है। अब आप लोग इधर नहीं आ सकते।

श्री मंगल सेन: नेहरा साहब, मैं आपको क्या कहूँ। आपको कुछ कहना मैं जरूरी भी नहीं समझता। आप इतने इन्नोसैंट है कि आप बात कर जाते हैं। आप इतने भोलेपन से बात कह जाते हैं कि आप उसका मिनिंग भी नहीं समझते। इसलिए मैं आपको कुछ न कहते हुए इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि कांस्टीच्यूटनरी के जो फ़ेमर्ज थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो विद्वान लोग थे और आजादी के बाद संविधान सभा में बैठकर जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं को रिप्रैजेंट किया, उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि उनके किये हुए काम की इस तरह से आने वाली पीढ़ी चीर-फाड़ कर देगी। 42 वे या 43 वें संविधान संशोधनों के द्वारा, जिसके अन्तर्गत हमारा बोलना बन्द कर दिया गया था, हमारे मौलिक अधिकार भी छीन लिये गये थे, उसके खिलाफ कुछ वकील लोग कोर्ट्स में चले गये थे। ये कहने लगे कि इसका कोई चककर ही नहीं है। अगर कोई गोली मार दे या कोई आजादी छिन ले तो इसकी कोई अपील नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हिन्दुस्तान की जनता ने इन संशोधनों को ठुकराया। आज चाहें कुछ भी कहते रहें। हमारे कई मित्र जो आज उधर बैठे हैं, हमारे पास जनता पार्टी का टिकट लेने आया करते थे। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि संविधान में जो इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं, यह नहीं होने चाहिए थे।

हमारे संविधान में संशोधन करने के दो मार्ग दिखाए गये हैं, एक पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत होना चाहिए और दूसरा स्टेट विधान सभाओं की सहमती होनी चाहिए। यानि पचास प्रतिशत से ज्यादा स्टेट विधान सभाओं की सहमति होनी चाहिए। इस अमैडमेंट के लिए दूसरा रास्ता अपनाया गया है। यह बिल हमारी विधान सभा में इसलिये आया है कि इस विधान सभा ने भी इसका अनुमोदन करना है। इस रैज्योलूशन पर पार्लियामेंटेरी अफेयर्ज मिनिस्टर महोदय ने पेश करते हुए कहा कि इस अमैडमेंट का मतलब हम यह समझते हैं कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का जो बनवासी है, अपना विकास हो उनकी तरक्की और विकास होना चाहिए आजाद हिन्दुस्तान में बिरला, टाटा, और हरियाणा के पूंजीपतियों के घरों में विकास न होकर, गरीब की झोपडी में विकास होना चाहिए। इसलिए यह प्रावधान लाया गया है। यह कदम सराहनीय है और समर्थन करने योग्य है। अन्त में मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

**श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा):** यह जो 53वीं अमैडमेंट हाउस में रैटीफिकेशन के लिये आयी है इसके बाद मैं यह समझती हूँ कि थोड़े दिनों में भाष्य हमारे संविधान का यह भी पता नहीं पड़ेगा कि ओरीजनल संविधान क्या है और अमैडिड क्या है। स्पीकर साहब, इस अमैडमेंट से यह क्या करना चाह रहे हैं? यह कहते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, अकेले त्रिपुरा में ही भाष्य 60-70

लाख से ज्यादा लोग बंगाल से आकर यहां बसे हुए हैं। आसाम में भी यह सिलसिला चल रहा है। दूसरी जगहों पर भी यदि यही सिलसिला चालू हो जायेगा तो जो ओरिजनल लोग हैं उनके हितों की रक्षा भाायद नहीं हो सकेगी। उनकी संख्या यदि कुछ भी नहीं रहेगी तो उनके इन्ट्रैस्ट कैसे प्रोटैक्ट होंगे? वह पंचायत के मैम्बर भी नहीं बन सकते, असैम्बलियों और पार्लियामेंट तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर की है।

**श्री अध्यक्ष:** आपके पास मैटीरियल पडा हुआ है, आपने पढा होगा कि दोनों ही हाउसिज में यह बिल यूनानीमसली पास हुआ था। किसी भी सदस्य ने विरोधता नहीं की है।

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, मैं विरोध तो नहीं कर रही हूं। मैं तो आपके द्वारा यह बात कहना चाहती हूं कि भारत सरकार इन बातों की तरफ ध्यान दें कि आज चाहे वह ि 1डयूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं, चाहे ि 1डयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, जो भी वहां के ओरीजनल बाि 1न्दें है, उनके हितों की रक्षा किस ढंग से हो सकती है। उनके हितों की रक्षा करने की बताये, विदे ि लोगो को वहां पर बसा कर भारत सरकार उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। तिब्बत तो वैसे ही चीन को दे दिया और तिब्बत वालो को यह कह दिया कि आप यहां पर आ जाओं। यही हाल अब थोडे दिनों में श्रीलंका के लोगो का हो जायेगा कि कि तुम यहां आ जाओ। आप उनको जमीन भी दे देना। असम का क्या हाल हुआ है? असम की आज जो प्राब्लम है, वह प्रोब्लम

इसलिए पैदा हुई है कि उसमें करोड़ों लोग बंगला दे 1 से आकर बस गए। थोड़े दिनों में कुछ चीन के कुछ बर्मा के और कुछ दूसरे लोग आयेंगे जो मिजोरम और नागालैंड में आ कर बस जाएंगे। मैंने सुना है कि 5 लाख के करीब बंगला दे 1 के लोग दिल्ली और हरियाणा में आकर बस चुके हैं। स्पीकर साहब, वहां पर त्रि चीयैनिटी का प्रचार होता है। जब मैं एम0 पी0 थी, तब होकर आयी थी। वहां पर दूसरे दे 10 के लोग आकर बस रहे हैं। इस दे 1 के ओरीजनल लोग हैं, उन लोगों के हितों की रक्षा तो बस इस तरह से ज्यादा बेहतर होगी कि वहां पर विदे 11 लोगों को न बसने दिया जाए। दूसरे प्रान्तों के लोग तो बस जाएंगे लेकिन यहां के लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं रहेगी। मैं इस पर बोलने हुए सारे दे 1 के बारे में बोल सकती हूं। नेहरा जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि स्पीकर साहब, के द्वारा हम यह बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि विदे 11 लोगों को यहां पर न बसने दें। जब बंगला दे 1 बनाया गया था उस वक्त हमें यह चाहिए था कि बंगला दे 1 से जो लोग हमारे यहां पर आ रहे थे, उनके हिस्से की जमीन भी हम लेते। यहां पर हमें जमीन मिलनी चाहिए। मैं इतनी ही बात कहकर आपका धन्यवाद करती हूं।

**चौधरी औम प्रका 1 (बेरी):** अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव कांसटीट्यू 1नल (तरेपनवां अमैडमेंट) बिल, 1984 संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्य



सभा के पास होने के पश्चात् रैटिफिकेशन के लिए यहां रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री जगदीश नेहरा:** स्पीकर साहब, इनके लीडर ने तो इस बिल का विरोध किया है और ये समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। (गौर एवं व्यवधान)

**श्रीमती चन्द्रावती:** स्पीकर साहब, मैंने इस बिल का विरोध नहीं किया है। मैंने तो बिल का समर्थन किया है। मैंने तो अपनी औबजरवेशन और सुझाव दिए हैं।

**श्री वीरेन्द्र सिंह:** स्पीकर साहब, अगर हमारा लीडर इसका विरोध भी रके तो क्या उनको इसकी सजा मिलेगी?

**श्री मंगल सेन:** स्पीकर साहब, मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूँ और आपकी रूलिंग भी चाहता हूँ। ये जो पौने मिनिस्टर है। (हंसी) शिक्षा राज्य मंत्री हैं इनका पार्लियामेंट अफेयर्स का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन एक्टिंग उनसे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। एक पार्टी के मैम्बर ने कोई बात कह दी और दूसरा मैम्बर उसके समर्थन में खड़ा हो रहा है तो इनको क्या एतराज है और कौन से रूल के तहत ये इस बारे में एतराज कर सकते हैं? इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठिए।

**चौधरी औम प्रकाश** : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि इस कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट को लोक सभा और राज्य सभा ने पास कर दिया है। 31 मार्च, 1980 को मेघालय असेम्बली ने इस बारे में प्रस्ताव पास किया था। आर्टिकल 330 और 332 में लोक सभा ने जो अमेंडमेंट की थी उसकी रैटिफिकेशन के लिए यहां पर प्रस्ताव लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत देरी से ही सही, जो यह अमेंडमेंट है उसका मैं स्वागत करता हूँ। स्पीकर साहब, आजादी को मिले हुए 37-38 साल हो गए लेकिन नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे इलाके के लोगों के पास अभी तक विकास की रीढ़ नहीं पहुंची है। उनके पोलिटिकल राइट्स कायम करने और सैपरेट आइडेन्टिटी कायम रखने के लिए संसद ने यह बिल पास किया है। स्पीकर साहब, मेरे पास 1981 में हुई जनगणना की फिगर है। ये फिगर इस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि जो इलाके आदिवासियों के थे उनमें दूसरे इलाकों के लोग आकर बस गए हैं और उन्होंने उन आदिवासियों से प्रॉपर्टी खरीद ली है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर नॉन-ट्राइबल 70 प्रतिशत है। 1981 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 83 प्रतिशत, मेघालय में 80 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 50 प्रतिशत और मिजोरम में 93 प्रतिशत आदिवासी हैं लेकिन धीरे धीरे इनकी आबादी कम होती जा रही है और गैर आदिवासी बढ़ते जा रहे हैं। यह तो बहुत अच्छा हुआ है कि ट्राइबल्स के पोलिटिकल राइट्स और प्रॉपर्टी के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और

उसकी रैटिफिके ान के लिए जो प्रस्ताव सदन में पे ा किया गया है मैं उसकी सराहना करता हूं और चाहता हूं कि यह प्रस्ताव युनानिमसली पास होना चाहिए।

**सिंचाइ तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला):** स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव पर बोलते हुए डा0 मंगल सेन, श्रीमती चन्द्रावती, और श्री औम प्रका ा ने संक्षेप में कुछ बातें की। डा0 मंगल सेन ने कहा कि राज्य सभा की डिबेट की कापी तो हमें मिल गई है लेकिन लोक सभा की डिबेट की कापी नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा में इस बिल पर कोई डिस्क ान नहीं हुआ। यह बिल लोक सभा में पे ा हुआ और बिल पास हो गया। राज्य सभा में इस पर डिस्क ान हुआ था और उसकी कापी मैम्बर्ज मे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। यहां पर यह भी कहा गया कि यह 53 वी अमडैमेंट है ओर बार बार अमडैमेंट कर के कास्टीच्यू ान की भावल ही बदल दी गई है, और कुछ दिनों मे पता ही नहीं लगेगा कि असली कास्टीच्यू ान कौन सा था। स्पीकर साहब, कास्टीच्यू ान कोई स्टेटिक चीज नहीं है, कोई डैड चीज नहीं है। कास्टीच्यू ान एक लिबिंग डाकूमेंट है। हिन्दुस्तान के लोग जैसे जैसे तरक्की करेगे वैसे वैसे लोगो की ऐस्पीरे ांज बढेगीं। हिन्दुस्तान के लोग एग्रीकल्चर में ऐक्सपेंड करेगे, नोलिज मे ऐक्सपेंड करेंगे और इंडस्टरी में ऐक्सपेंड करेगे, उसी तरह से कांस्टीच्यू ान में अमैडमेंट होती रहेगी कांस्टीच्यू ान लोगो के

लिए बना है, लोग कांस्टीच्यू इन के लिए नहीं बने। जैसे जैसे कन्ट्री ऐक्सपैंड करेगा वैसे वैसे कांस्टीच्यू इन में सूटेबल अमैडमेंट होगी ताकी किसी तरह की रिटार्ड न हो, दे आ की प्रगति में बाधा न आये और उन्नति का मार्ग प्रोस्त हों। इस तरह का कांस्टीच्यू इन बनाया जाए। इसलिए जो तरमीमे हुई हम उनको वैलकम करते हैं। स्पीकर साहब, पहले हिन्दुस्तान में बड़े बड़े बिस्वेदार थे, बड़े-बड़े साहूकार थे और बड़े बड़े रजवाड़े थे। उस वक्त भारत की पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाये जिनको ऐंगरेरियन रिफार्मर्ज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों को स्ट्रोक डाउन कर दिया क्योंकि उस वक्त कांस्टीच्यू इन इस बात की इजाजत नहीं देता था। बाद में पार्लियामेंट ने कांस्टीच्यू इन में इस तरह का प्रोविजन किया कि किसी एक हाथ में सारी दौलत न रह जाए। किसी एक हाथ में सारी जमीन न रह जाए और वह जमीन कल्टीवेटर्ज में बंटनी चाहिए। यह कांस्टीच्यू इन में अमैडमेंट करके ही हो सकता है। संसद ने जायदाद पर पाबन्दी लगाई, जमीन पर पाबन्दी लगाई ताकि दे आ में समाजवाद लाने के लिए मार्ग प्रोस्त हो सके। स्पीकर साहब, लीडर आफ दी अपोजी इन ने बोलते हुए कुछ ऐक्सट्रानुअस बातें कीं। मैं समझता हूँ उनका ऐसी बातें करने का कोई औचित्य नहीं था। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट आफ इंडिया पूरी तरह से जागरूक है। अब तक किसी प्रकार से भी टैरिटोरियल इन्टैग्रेटी को कोई आघात नहीं पहुंचा है और न आगे पहुंचेगा। भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। एक बात चौधरी औम प्रकाश जी ने आदिवासियों की प्रापर्टी

की प्रोटैकान की बात की। उन्होंने कहा कि उनकी जायदाद दूसरे लोग खरीद लेते हैं। स्पीकर साहब, जहां तक मेरा ज्ञान है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहां के लोगों के प्रोपर्टी राइट्स पूरी तरह से सेफ है। बाहर के लोग उनकी प्रोपर्टी को नहीं खरीद सकते। उनका कल्चर उनकी संस्कृति और उनकी भाशा पूरी तरह सेफ है। उनके रीति रिवाजों के बारे में उनको पूरी तरह से प्रोटैकान दी जा रही है। इस सम्बन्ध में पंडित जवाहर लाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी दोनों ने ट्राइबलज़ लोगों को पूरा सम्मान का दर्जा दिया और उनकी संस्कृति और कल्चर को प्रिजर्व करने के प्रयत्न किए। आज के प्रधान मंत्री भी हर स्फीयर में चाहे ट्राइबल का स्फीयर है, चाहे कोई और स्फीयर है, पूरी तरह से जागरुक है। ये देश को पूरी स्पीड से और आफ टेक की स्पीड से 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। इन भावों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जायें।

**Mr. Speaker:** Questionis-

That this House ratifies the amendment to the Consitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Consitution (Fifty-third Amendment) Bill, 1984 as passed by the two House of Parliament.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker:** The motion has been carried unanimously.

अब हाउस कल प्रातः 9:30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

**13:30 बजे**

(तत्प चात सदन बुधवार दिनांक 20 मार्च, 1985 करे प्रातः 9:30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)